R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 22
16 से 31 अगस्त 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा है क्यों बरपा?

मानसून सत्र की एक ही उपलब्धि...
...बिन चर्चा बिल पास

विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में
कौन पास, कौन फेल?

HAPPY INDEPENDENCE DAY

15TH AUGUST

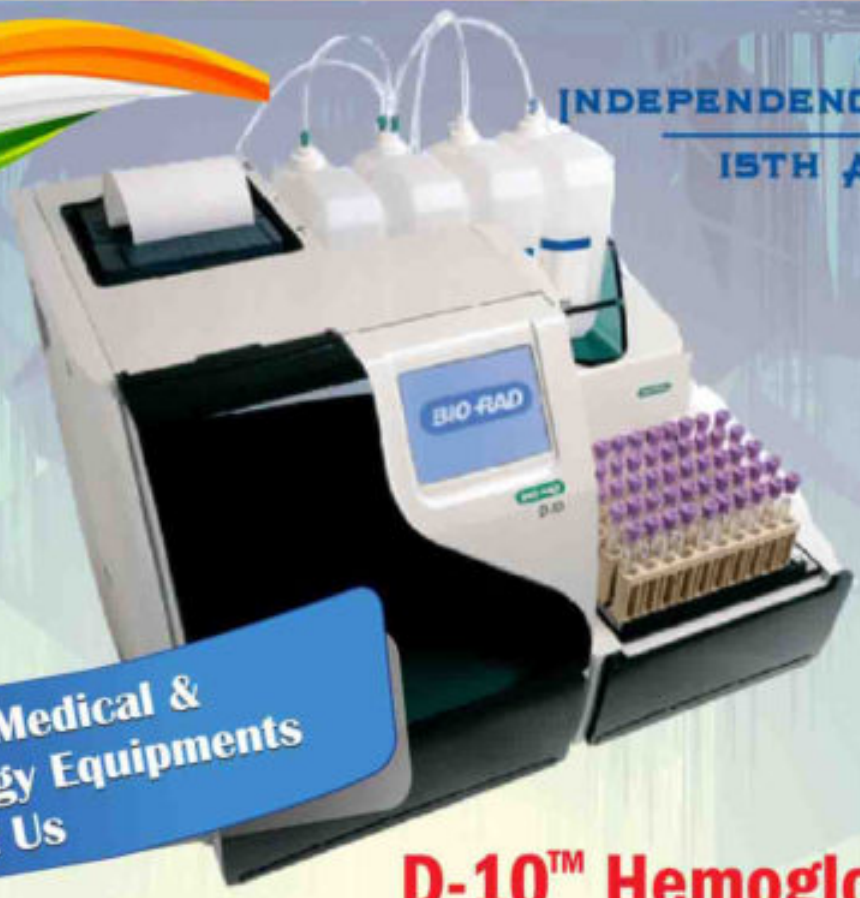

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

तैयारी

9 | वीबी-1, सतपुड़ा, विंध्याचल का...

भोपाल के सतपुड़ा भवन में अग्निकांड की घटना के बाद प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी बिल्डिंगों में अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही उनके रखरखाव पर विशेष फोकस किया है। इसके तहत वल्लभ भवन-1, सतपुड़ा...

राजपथ

10-11 | अबकी बार कमल पर दांव

मप्र में भाजपा इस बार नई रणनीति से चुनाव लड़ेगी। अबकी बार पार्टी किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ेगी। पार्टी आलाकमान ने प्रदेश संगठन और सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि...

दर्पण

18 | कथा पॉलिटिक्स का अखाड़ा

मप्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। दावेदार क्षेत्र में लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए नित-नए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बार मिशन 2023 में टिकट के दावेदार मतदाताओं को आकर्षित करने और अपनी सियासी...

योजना

19 | मप्र के महुए से अंग्रेज पिएंगे चाय

नशीली शराब से मदहोश बना देने वाले महुए से अब तरोताजगी, चुस्ती, फुर्ती लाने वाली ग्रीन टी यानी चाय भी बन रही है। यह चाय हिंदुस्तान ही नही इंगलिस्तान यानि इंग्लैंड तक धूम मचा रही है। मप्र के बैतूल समेत 9 जिलों से इसके लिए इंग्लैंड महुआ भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

संसद का 23 दिनी मानसून सत्र समाप्त हो गया। सबको उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के 8 महीने पहले होने वाले इस सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे, लेकिन तय समय तक चलने वाले इस सत्र में केवल हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। विपक्ष जहां वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या मणिपुर हिंसा पर धारा 176 के तहत चर्चा के लिए अड़ा रहा, वहीं सत्तापक्ष 267 पर चर्चा के लिए खड़ा रहा। इस कारण संसद केवल आखिरी तीन दिन ही चल पाया।

16-17

20

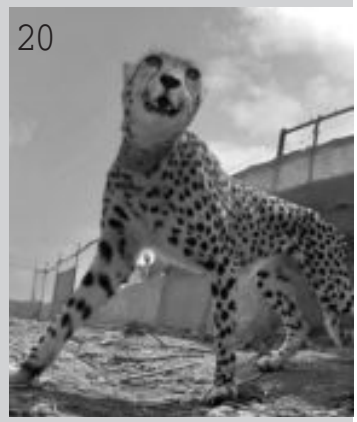

29

39

राजनीति

30-31 | क्या चुनौती बन पाएगा इंडिया?

विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया) रखकर भाजपा को असहज कर दिया है। धर्म और राष्ट्रवाद के सहारे राजनीति करने वाली भाजपा के इस एकाधिकार को विपक्ष ने इस बार अलग अंदाज में चुनौती दे दी है। विपक्ष ने अपने लिए...

महाराष्ट्र

35 | अजित को लेकर फंसी भाजपा

भाजपा के कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट को गठबंधन सरकार में शामिल करने का फैसला बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। कार्यकर्ताओं ने जून 2022 में शिवसेना में दो फाड़ के बाद कभी फडणवीस सरकार में सिर्फ एक मंत्री रहे एकनाथ...

बिहार

38 | भाजपा के लिए पूरा मैदान

बिहार में पिछले महीने भाजपा की एक रैली में उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जिस बर्बर अंदाज में लाठियां चलाईं और उसके सांसदों-विधायकों को पीटा वह बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का प्रस्थान बिंदु हो सकता है।

6-7 अंदर की बात
39 पड़ोस
40 विदेश
43 कहानी
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

प्रधानमंत्री ने दिखाया विश्वास और सामर्थ्य का प्रतिबिंब

किसी शायर ने लिखा है...

वतन की ख़ाक जरा एड़ियां रगड़ने दे
मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा

उपरोक्त पंक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को भारत के विश्वास और सामर्थ्य का प्रतिबिंब दिखाया। साथ ही देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री के भाषण में जहां देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का विश्वास दिखा, वहीं उन्होंने अगली बार भी अपनी सरकार बनाने का संकेत दे दिया। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को साकार करने वाला संकल्प सूत्र था। यह संबोधन प्रेरणादायी होने के साथ ही देश के विश्वास एवं सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करने वाला था। स्वतंत्रता दिवस पर सीमावर्ती गांवों के ग्राम पंचायत प्रधानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सिद्ध करता है कि वह भारत के अंतिम गांव नहीं, बल्कि प्रथम गांव हैं। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि एवं कौशल विकास योजना के प्रतिभागी, किसान उत्पादक संगठनों के सदस्य, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रम योगी, अमृत सरोवर के लिए काम करने वाले श्रम योगी, खादी श्रमिक, सीमा सड़क निर्माण में काम करने वाले श्रमिक, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, नर्स और मछुआरे भी आमंत्रित थे। एक तरह से ये संपूर्ण भारत के नवनिर्माण में काम करने वाले हरेक श्रम योगी का सम्मान था जिन्हें पिछली सरकार पूछती तक नहीं थी। सेवा और श्रम योगदान को विशेष रूप से मोदी सरकार द्वारा उचित सम्मान दिया गया है। संबोधन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र की युवा शक्ति के नाम रहा। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की है। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को सिरमौर बना दिया है। साथ ही, देश को आगे ले जाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को भी प्रदर्शित करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अब देश की कार्यसंस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। इनके चलते नीतिगत स्थिरता, बेहतर समन्वय और ईज आफ डूइंग बिजनेस की स्थिति सुधरी है। इससे भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने फ्रेजाइल फाइव से टॉप फाइव की यात्रा की है और अगले पांच वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होंगे। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण आज सरकार की हर योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है जिससे लाभार्थियों का सशक्तीकरण हो रहा है। डीबीटी के तहत अब तक लगभग 27 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन-धन, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और पीएम आवास जैसी योजनाएं जन-जन के जीवन में कल्याण लाने का माध्यम बनी हैं। यह बदलते भारत और आगे बढ़ते भारत की सुनहरी तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में विश्व मित्र के रूप में राष्ट्र को संदर्भित किया गया है। अर्थात् वैश्विक कल्याण में योगदान के कारण भारत आज सभी देशों के मित्र रूप में प्रस्थापित है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम् के सूत्र को चरितार्थ करते हुए एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का आव्हान किया है जिसे वैश्विक स्वीकृति और समर्थन मिला है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 22, पृष्ठ-48, 16 से 31 अगस्त, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र-संपादक के नाम

akshnews.com

चुनावी तैयारियां तेज

दो दशक से सत्ता में काबिज भाजपा नेतृत्व को पता है कि इस बार का चुनाव चुनौतीपूर्ण है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व मप्र विधानसभा चुनाव पर कोई चूक नहीं रखना चाहता। इसलिए पहले की तरह मनमानी टिकट का बंटवारा भी नहीं होगा। यही हाल कांग्रेस का भी है।

● **प्रियांशी मोदी,** भोपाल (म.प्र.)

रिंग-विंग फेंसिंग योजना

मप्र सरकार के दिशा-निर्देश पर प्रदेश का ऊर्जा विभाग बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। बिजली संग्रहण के लिए जहां कैपिसेटर बैंक बनाया जा रहा है, वहीं फीडर सेप्रेशन पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए रिंग-विंग फेंसिंग योजना बनाई जा रही है।

● **नेहा सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

वंदे भारत ट्रेन सफल होगी?

मप्र के इंदौर और भोपाल के बीच 100 से ज्यादा बसें रोज चलती हैं। इनका किराया भी लगभग आधा है। एआईसीटीएस की सुविधायुक्त एसी बसें साढ़े तीन घंटे में भोपाल पहुंचा देती हैं। वह भी 435 रुपए में। यानी इसका किराया भी वंदे भारत से कम है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन सफल कैसे होगी।

● **उपेंद्र यादव,** ग्वालियर (म.प्र.)

फैल रही मणिपुर की आग

अभी तक मणिपुर हिंसा में स्थानीय मुसलमानों अथवा रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने के साक्ष्य नहीं हैं। परंतु अगर मुसलमान इस हिंसा का हिस्सा बने, तो इसका रूप बदल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि मणिपुर में आरक्षण को लेकर फैली जातीय हिंसा हिंदू-ईसाई हिंसा से होते हुए हिंदू-मुस्लिम हिंसा का रूप ले ले। इसलिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को इसे तत्काल रोकना चाहिए। अगर हिंसा रोकना उनके वश से बाहर है अथवा संभव नहीं है, तो राज्य सरकार को बर्खास्त करके मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।

● **आमिर अली,** नई दिल्ली

बस ऑपरेटर्स आस में...

दिल्ली में लागू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर मप्र सरकार अपने यहां भी वैसा ही प्रावधान लागू करती है तो हर साल 10 साल पुरानी करीब 200 बसें बाहर होंगी। ऐसा हुआ तो बस ऑपरेटर्स समेत शासन को भी राजस्व की हानि होगी। अभी प्रदेश में 2202 बसें सभी तरह के परमिट पर चल रही हैं। इनमें से 200 बसें जल्द ही एक्ट के दायरे में आ जाएंगी। प्रदेश में परिवहन कार्यालयों में रजिस्टर्ड कुल बसें 35,882 हैं।

● **शिवेंद्र पुरोहित,** जबलपुर (म.प्र.)

टाइगर स्टेट मप्र

टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन रेग्युलर फॉरेस्ट में बिना ऐसे किसी बजट के बाघों की मौजूदगी ने मप्र को एक बार फिर बाघों से उन्नत प्रदेश बनने की संभावना से भर दिया है। वर्ष 2006 में देश में महज 1411 बाघ थे। वर्ष 2010 में 295 बाघ बढ़ गए और बाघों की संख्या 1706 हो गई। वर्ष 2014 के स्टीमेशन की रिपोर्ट जारी हुई तो वह पहले से ज्यादा खुशियां लेकर आई क्योंकि इस साल देश में 520 बाघ बढ़े थे और देश में बाघों की संख्या 2226 हो गई थी।

● **राहुल शिवहरे,** पिपरिया (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

बीआरएस की कठिन राह

तेलंगाना में इस बार विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं। सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए कांग्रेस के साथ भाजपा भी कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने यहां पर काफी काम किया है और कुछ अहम सफलताओं के साथ वोट प्रतिशत भी बढ़ाया है। वहीं कांग्रेस को कई झटके लगे हैं। इन पांच वर्षों में एक बड़ा बदलाव सत्तारूढ़ दल के नाम में भी आया है और टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) अब बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) बन गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार बीआरएस की राह आसान नहीं है। दरअसल, आंध्र प्रदेश से विभाजन के बाद अस्तित्व में आए तेलंगाना में बीआरएस का अभी तक एकतरफा राज चल रहा है। उसकी ताकत के सामने विरोधी कमजोर रहे हैं, लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं। आम चुनाव में भाजपा ने चार सीटें जीतकर अपनी जगह बनानी शुरू की थी। उसने दूसरे दलों के कई नेताओं को भी साथ जोड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 119 सीटों में टीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 7, तेलुगुदेशम को 2, भाजपा को 1, फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। दल-बदल, इस्तीफों एवं उपचुनाव से वर्तमान में बीआरएस के 103, एआईएमआईएम के 7, कांग्रेस के 5, भाजपा के 2 एवं 1 निर्दलीय विधायक हैं।

इंडिया के संयोजक बनेंगे नीतीश

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के खिलाफ एकसाथ मैदान में उतरने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने महागठबंधन बनाया है। जिसकी अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। लेकिन इस बैठक से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो इंडिया के सभी प्रमुख सहयोगियों के शीर्ष नेता और कांग्रेस नेतृत्व संयोजक के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर सहमत भी हो गए हैं। मुंबई बैठक में इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता चाहते हैं कि 11 सदस्यीय समन्वय समिति का नेतृत्व सोनिया गांधी करें। क्योंकि वह यूपीए की अध्यक्ष रही हैं। विपक्षी दल इससे पहले पटना और बेंगलुरू में दो बैठकें कर चुके हैं। 18 जुलाई को बेंगलुरू में हुई विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मुंबई में अगली बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति का चुनाव किया जाएगा। इसी बीच जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू विपक्षी एकता की राह में बाधा नहीं बनेगी, हमारे नेता नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक कद संगठन में किसी भी बड़े पद के लिए उपयुक्त है।

एनसीपी-कांग्रेस शिवसेना की एक ही विचारधारा

महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र अपने अंतिम पड़ाव में है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए कांग्रेस ने अपना दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास पेश किया है। विजय वडेट्टीवार के नाम का यह पत्र कांग्रेस की ओर से राहुल नार्वेकर को दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार और वर्षा गायकवाड़ मौजूद थीं। इस दौरान कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद नहीं थे। पटोले की गैर मौजूदगी की वजह से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी भी उजागर हुई है। गौरतलब है कि नाना पटोले के महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेताओं ने उनके काम करने के तौर-तरीकों पर कई बार आपत्ति जताई है। खासकर नाना पटोले के बयानों ने पार्टी को कई बार मुश्किलों में भी डाला है और हर बार बालसाहेब थोरात, अशोक चव्हाण जैसे नेताओं को आगे आकर सफाई देनी पड़ी है। वहीं पार्टी आलाकमान के पास भी कई बार इन नेताओं ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर भी की है। विधानसभा में अजित पवार की बगावत के बाद नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की ओर से होना तय था क्योंकि विपक्षी दलों में फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है।

करीब आने लगी भाजपा

देश में जहां साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चुनाव से पहले दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया के अलावा तीसरे मोर्चे को लेकर भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक जो दल इन दोनों गठबंधन के साथ नहीं गए हैं वो इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। विपक्षी गठबंधन छोटे-छोटे दलों को साधने का प्रयास कर रहा है तो एनडीए एक बार फिर मोदी के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति तैयार कर रही है। विपक्ष गठबंधन की दो बैठकों में बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया और साथ ही एनडीए की बैठक में भी नहीं दिखाई दी। बसपा को लेकर राजनीतिक जगत में कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद बसपा भाजपा के साथ जाए। बसपा अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले चुनाव में भी अपनी पार्टी को उतारने का ऐलान किया है।

देश में लागू होगा छग मॉडल!

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने स्कूली शिक्षा के साथ-साथ आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) का संयुक्त पाठ्यक्रम पढ़ाकर देशभर के लिए नजीर पेश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्कूली शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। संभावना है कि केंद्र सरकार इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश कर सकती है। इसके लिए भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कमेटी गठित की है। इसमें छत्तीसगढ़ से एक सदस्य को नामांकित करने का अनुरोध किया गया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में इस पाठ्यक्रम के तहत आईटीआई की परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से आईटीआई का प्रमाण-पत्र भी दिया जा रहा है।

एनजीओ की दमदारी

2014 में जबसे केंद्र की सत्ता में परिवर्तन हुआ है, सबसे अधिक नकेल एनजीओ पर कसी गई है। सरकार ने हजारों एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। वहीं लगभग हर एनजीओ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इन सबके बीच मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक एनजीओ तेजी से फल-फूल रहा है। जबकि इस एनजीओ की पड़ताल की गई तो पता लगा कि यह एनजीओ पलायन करके सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुए एक मंत्रीजी की श्रीमतीजी का है। दरअसल, इस एनजीओ को इस कदर लाभांवित किया जा रहा है कि हर किसी की नजर इसको लग रही है। आलम यह है कि मंत्रीजी के पास भी प्रदेश का वह सबसे बड़ा विभाग है, जिसमें केंद्र और राज्य से भरपूर फंड मिलता है। इस विभाग में कई कंपनियां और ठेकेदार भी काम करते हैं। ऐसे में मंत्रीजी की कृपा और साख से एनजीओ खूब तरक्की कर रहा है। इस एनजीओ से जलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि मंत्रीजी की पत्नी के नाम पर चल रहे इस एनजीओ में एक अखबारनवीस का लाड़ला भी हिस्सेदार है। बताया जाता है कि सरकार की तरफ से इस एनजीओ को काम मिले या न मिले, लेकिन कंपनियां और ठेकेदार बराबर इसे लाभांवित कर रहे हैं। एनजीओ की इसी दमदारी को देखकर लोग मंत्रीजी के कौशल को सराह रहे हैं।

कप्तान पर भारी टीआई

शीर्षक पढ़कर आप भी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन अजब-गजब वाले मप्र में सबकुछ संभव है। ऐसा हुआ है विंध्य क्षेत्र के एक जिले में। दरअसल, 2016 बैच के एक आईपीएस अधिकारी जिले में पहली बार एसपी बनकर गए। पहली बार एसपी बनने के उत्साह में साहब ने मातहतों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जिले के बिगड़े सिस्टम को सुधारने के लिए साहब ने सुशासन की ऐसी लाठी चलाई कि उसमें वे खुद फंस गए। दरअसल, साहब जिले में पदस्थ मैदानी अफसरों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने जिले के एक टीआई के खिलाफ एफआईआर करवा दी। साहब को लगा कि इस कार्यवाही से सरकार भी उन पर खुश हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उलटा। साहब के इस कदम को सरकार ने गंभीरता से लिया और अभी जिले को समझने की कोशिश में लगे साहब को चलता कर दिया गया। साहब को यह समझ में नहीं आया कि आखिरकार मैंने ऐसी कौनसी गलती कर दी, जिससे कप्तानी का मजा भी नहीं उठा पाए। वहीं साहब को यह सबक भी मिल गया कि किसी को छोटा और कमजोर आंकना उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

फर्जी पत्र बढ़ा गया पारा

चुनावी साल में बात का बतंगड़ बनना आम बात है। प्रदेश में अगले 3 माह के बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा। ऐसे में पार्टियां एक-दूसरे को घेरने के लिए कोई मौका और कोरकसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में इन दिनों एक तथाकथित ठेकेदार का तथाकथित पत्र चर्चा में है। पत्र किसका है, यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस पत्र ने प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। दरअसल, विपक्षी पार्टी की एक राष्ट्रीय स्तर की नेत्री ने उस फर्जी पत्र के आधार पर बनाई गई एक खबर को ट्वीट कर दिया। उन्होंने उस ट्वीट में वर्णित बात का जिक्र करते हुए लिख दिया कि कर्नाटक में सरकार 40 फीसदी कमीशन लेती थी, यहां की सरकार तो 50 फीसदी कमीशन ले रही है। फिर क्या था, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इस मसले को लेकर इस कदर टूट पड़े कि प्रदेश में एफआईआर का दौर चल पड़ा। प्रदेशभर में तकरीबन डेढ़ दर्जन एफआईआर दर्ज करा दी गई। लोग यह देखकर हैरान हो उठे कि बच्चा हुआ नहीं और ढिंढोरा जमकर पीट दिया गया। जिस तरह सरकार और पार्टी उस फर्जी पत्र को लेकर हमलावर हुई, उससे जनता भी आश्चर्यचकित थी। वहीं कुछ लोग यह कहते हुए भी सुने गए कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम की असलियत क्या है, यह तो सरकार और आरोप लगाने वाले ही जानें, लेकिन यह बात तो तय हो गई है कि प्रदेश में इस चुनावी साल में बात का बतंगड़ ऐसे ही बनता है।

प्रारूप का अनुमोदन

विगत दिनों सहकारी समितियों की भूमि को लेकर एक समाचार पत्र में गलत खबर छप गई। इस खबर के छपने के बाद जिलों में सोसायटी में प्लाट लेने वालों और बेचने वालों के नामांतरण पर ऊपरी तौर से रोक लग गई। जबकि आदेश निकला ही नहीं। खबर को आधार मानते हुए स्वयं एसडीएम और तहसीलदार ने रोक लगा दी। जैसे ही यह मामला मंत्री के पास पहुंचा, उन्होंने इसका खंडन किया। वहीं विभाग ने खंडन भी भेजा, लेकिन उसी अखबार ने नहीं छापा। ऐसे में स्थिति यह हो गई है कि नामांतरण का काम बंद हो गया है। इससे जनता परेशान हो उठी है। इस मामले में मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि केवल सहकारी समितियों की भूमि के नामांतरण पर रोक लगी है, न कि भूखंड के नामांतरण पर? फिर क्या था, फाइल का खेल चालू हुआ और स्पष्ट निर्देश दिए कि आदेश को स्पष्ट करें। अब आदेश भी स्पष्ट हो गया। मजा यह है कि एक सीनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच के अधिकारी ने अब नए और स्पष्ट प्रारूप को अनुमोदन के लिए प्रमुख सचिव और मंत्री को भेज दिया। इसी को लेकर इनकी क्लास होना निश्चित है।

अरमां आंसुओं में बह जाएंगे

फिल्म निकाह का यह गाना तो आपने सुना ही होगा- दिल के अरमां आंसुओं में बह गए...। इसी तरह की कुछ स्थिति प्रदेश के उन नौकरशाहों की होने वाली है, जो प्रदेश का प्रशासनिक मुखिया बनने का अरमान पाले हुए हैं। दरअसल, जिस तरह की स्थिति दिख रही है, उसमें यह कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश के वर्तमान प्रशासनिक मुखिया को एक और एक्सटेंशन मिलना तय है। इसकी वजह यह है कि बड़े साहब का वर्तमान कार्यकाल 20 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उससे पहले अक्टूबर के पहले पखवाड़े में किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही सरकार बड़े साहब के एक्सटेंशन का एक और प्रस्ताव केंद्र को भेज देगी। और यह 100 फीसदी तय भी है कि साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगा। ऐसे में उन वरिष्ठ नौकरशाहों के दिल के अरमां आंसुओं में बह जाएंगे, जो प्रदेश का प्रशासनिक मुखिया बनने का सपना देख रहे हैं। दरअसल वर्तमान सरकार को विश्वास है कि ये प्रशासनिक मुखिया ही चुनाव में उसके लिए फायदेमंद होंगे।

किसी व्यक्ति की किस्मत में कब सफलता मिल जाए और कब असफलता आ जाए, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने हिंदी सिनेमा सहित हॉलीवुड के लिए भी लेखन कार्य किया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब मैंने गैराज में काम किया और गोडाउन में सोया।

● **गुलजार**

जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मेरी जमीनी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी जानकारी मुझे पहले मिल जाती थी और अफसरों को बाद में। दरअसल, मैंने खुद ऐसी कार्यशैली बनाई। इसका मुझे बड़ा फायदा होता था। वहीं मैंने काम करने की कार्यशैली भी विकसित की। जिससे काम में जरूर पूरी शक्ति लगती थी, लेकिन उससे बड़ी सफलता भी मिलती थी।

● **नरेंद्र मोदी**

रोहित शर्मा अच्छे कप्तान हैं, लेकिन उन्हें और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि इंग्लैंड जैसी टीमें इस बार किस तरह खेल रही हैं। सिर्फ रोहित शर्मा को ही नहीं सभी टीमों को इस बारे में सोचना होगा। मैच जीतना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि ड्रॉ करना। इसके लिए कप्तान को पहले से ही रणनीति बनानी होती है।

● **कपिल देव**

पाकिस्तान की सरकार दिन पर दिन क्रूर होती जा रही है। जिस तरह देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। उससे यह साफ हो गया कि देश में एक बार फिर से तानाशाही शासन लागू होगा। सरकार मुद्दों से भटक रही है, इसलिए महंगाई चरम पर है।

● **इमरान खान**

जब मैं 3 इडियट्स की शूटिंग कर रही थी, तब मैं पहली बार पूरी टीम के साथ काम कर रही थी और मैंने आमिर सर को देखा और मुझे लगा- हे भगवान वह क्या कर रहे हैं? हमने करीब 100 बार रिहर्सल की और वह हर बार सीन में कुछ अलग लेकर आए। एक टीवी एक्ट्रेस के तौर पर मुझे रिहर्सल की आदत नहीं थी। मैंने टीम से पूछा कि हम इतनी रिहर्सल क्यों कर रहे हैं? तो आमिर ने समझाया कि मोना यह एक फिल्म है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह कोई टीवी शो नहीं है, जिसका अगला एपिसोड कल रिलीज होने वाला है। यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हम एक दिन में एक सीन करेंगे।

● **मोना सिंह**

वाक्युद्ध

मणिपुर में जैसी हिंसा दिख रही है, वैसा देश में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। संसद के मानसून सत्र में उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस मसले पर बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वे अविश्वास प्रस्ताव के बाद मजबूर होकर संसद में आए भी तो मणिपुर हिंसा पर बोलने से कतरा गए। आखिर पीएम इतने गंभीर मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे।

● **राहुल गांधी**

संसद में विपक्ष मणिपुर मुद्दे को लेकर कितना संवेदनशील रहा, यह पूरे देश ने देख लिया है। सरकार मुद्दे पर बोलने के लिए रोज कह रही थी, लेकिन विपक्ष को सदन न चलने देने में मजा आ रहा था। दरअसल, विपक्ष केवल मणिपुर मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसे हम कभी भी साकार नहीं होने देंगे।

● **अमित शाह**

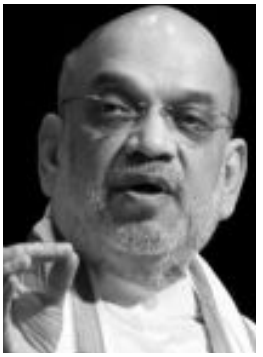

वीबी-1, सतपुड़ा, विंध्याचल का होगा कायाकल्प

भोपाल के सतपुड़ा भवन में अग्निकांड की घटना के बाद प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी बिल्डिंगों में अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही उनके रखरखाव पर विशेष फोकस किया है। इसके तहत वल्लभ भवन-1, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन का कायाकल्प करने की तैयारी की गई है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रपोजल बना लिया है।

इन तीनों बिल्डिंगों में होने वाले कार्य और उन पर खर्च होने वाली रकम का अनुमानित आंकलन कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार इन भवनों में सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लंबिंग, फायर हाइड्रेंट आदि के निर्माण की जानकारी दी गई है। साथ ही इन भवनों पर खर्च होने वाली राशि का भी जिक्र किया गया है।

विभागीय प्रस्ताव में मंत्रालय वल्लभ भवन क्र.-1 सतपुड़ा भवन एवं विंध्याचल भवन के नवीनीकरण एवं उन्नयनीकरण के लिए क्रमश: 98.61 करोड़, 88.40 करोड़ एवं 79.19 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल रुपए 266.20 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति बजट मद मांग संख्या 24-4217-7218-001 (मंत्रालय का विस्तार) के अंतर्गत किए जाने का अनुमोदन किया गया है। प्रस्तावित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि को लोक निर्माण विभाग की सूचकांक की सीमा से विमुक्त किए जाने के लिए अनुमोदन किया गया है।

गौरतलब है कि सतपुड़ा भवन एवं विंध्याचल भवन का निर्माण वर्ष 1982 में हुआ था। सतपुड़ा भवन का क्षेत्रफल 43,399 वर्गमीटर और विंध्याचल भवन का क्षेत्रफल 40,954 वर्गमीटर है। यानी इन भवनों की उम्र लगभग 40 वर्ष हो चुकी है। नई योजना के अनुसार भवनों के सिविल संरचना, शौचालय, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकासी, लिफ्ट, बिजली लोड, सुरक्षा कैमरा, जनरेटर, पार्किंग सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता है। वर्ष 2016 के एनबीसी प्रावधान के अनुरूप नवीनतम फायर हाइड्रेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एवं प्लंबिंग की आवश्यकता है। इन सभी उपायों से इन भवनों की आयु आगामी 35 से 40 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव के तहत सतपुड़ा भवन एवं विंध्याचल भवन में जो उन्नयन कार्य होने हैं, उनमें एचटी एंड एलटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग, सीसीटीवी सिस्टम, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (सी3), फायर एस्केप स्टेयर विथ प्रेशराइजेशन, फायर हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, फिनिशिंग एंड फर्निशिंग ऑफ कॉमन एरिया, एक्सटर्नल फेस्ड, एसटीपी-100 केएलडी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर लाइन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इंटरनल वाटर सप्लाई एंड प्लंबिंग, सर्विसेज का काम होना है।

266 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च

लोकनिर्माण विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव में वल्लभ भवन-1 में सिविल वर्क पर 48.50 करोड़, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लंबिंग, फायर हाइड्रेंट पर 32.63 करोड़, ऐड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी चार्जेज (3 प्रतिशत) पर 2.43 करोड़, जीएसटी (18 प्रतिशत) पर 15.04 करोड़, जीएसटी के साथ कुल 98.61 करोड़ खर्च होंगे। वहीं सतपुड़ा भवन में सिविल वर्क पर 28.83 करोड़, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लंबिंग, फायर हाइड्रेंट पर 43.90 करोड़, ऐड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी चार्जेज (3 प्रतिशत) पर 2.18 करोड़, जीएसटी (18 प्रतिशत) पर 13.49 करोड़, जीएसटी के साथ कुल 88.40 करोड़ खर्च होंगे। इसी प्रकार विंध्याचल भवन में सिविल वर्क पर 30.95 करोड़, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लंबिंग, फायर हाइड्रेंट पर 34.20 करोड़, ऐड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी चार्जेज (3 प्रतिशत) पर 1.95 करोड़, जीएसटी (18 प्रतिशत) पर 12.08 करोड़, जीएसटी के साथ कुल 79.19 करोड़ खर्च होंगे। इस प्रकार वल्लभ भवन-1, सतपुड़ा भवन, और विंध्याचल भवन पर कुल 266.20 करोड़ खर्च होंगे।

गौरतलब है कि वल्लभ भवन-1 का निर्माण वर्ष 1962 में हुआ था। इसका क्षेत्रफल 30,020 वर्गमीटर है। लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि वल्लभ भवन ब्लॉक-1 की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। मंत्रालय में पुराने एवं नए भवन में कुल 54 विभाग कार्यरत हैं। नवीन ब्लॉक-2 एवं ब्लॉक-3 में कुल 35 विभाग कार्यरत हैं। शेष 19 विभागों एवं माननीय 10 मंत्रियों की बैठक व्यवस्था हेतु ब्लॉक-1 को नव निर्मित भवनों के अनुरूप सुविधायुक्त किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2016 के एनबीसी प्रावधान के अनुरूप नवीनतम फायर हाइड्रेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एवं प्लंबिंग की आवश्यकता है। अन्य सुविधाओं जैसे बैंक, लाइब्रेरी, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, झूलाघर, कैंटीन, रिकार्ड रूम और बैठक कक्ष की व्यवस्था आवश्यक है। वल्लभ भवन ब्लॉक-1 के नवीनीकरण एवं उन्नयनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है।

वल्लभ भवन-1 में सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य इलेक्ट्रिकल एंड एलवी सिस्टम अपग्रेडेशन, फायर हाइड्रेंट एंड स्प्रिंक्लर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम, एक्सिस्टिंग लिफ्ट अपग्रेडेशन, इमरजेंसी लाइटिंग फॉर एक्जिट रूट, सीसीटीवी सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सिस्टिंग टॉयलेट अपग्रेडेशन, प्लंबिंग एंड रैन वाटर सिस्टम अपग्रेडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टॉयलेट, इंटीरियर एंड फर्निशिंग वर्क, रेस्टोरेशन ऑफ फेसाड, इंटरनल कॉर्टयार्ड लैंडस्कैपिंग, आर्ट एंड साइनेज वर्क होना है। सभी कार्यों के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण कर इन सभी भवनों का कायाकल्प हो जाएगा।

● **राजेंद्र आगाल**

मप्र में भाजपा इस बार नई रणनीति से चुनाव लड़ेगी। अबकी बार पार्टी किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ेगी। पार्टी आलाकमान ने प्रदेश संगठन और सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कार्यकर्ताओं को पूरा महत्व दिया जाए। वैसे मप्र संगठन पूरी तरह कार्यकर्ताओं के इर्द-गिर्द ही काम करता है। लेकिन आलाकमान से मिले निर्देश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अबकी बार कार्यकर्ताओं पर दांव लगाने का अभियान शुरु कर दिया है।

अबकी बार कमल पर दांव

भाजपा कैडर आधारित पार्टी है। पार्टी में प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या सांसद-विधायक सभी ही हैसियत एक कार्यकर्ता की होती है। इसलिए भाजपा में कार्यकर्ता ही सबकुछ होता है। इसलिए भाजपा हाईकमान ने इस बार मप्र के चुनाव में कार्यकर्ताओं पर जोर देने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गत दिनों इंदौर में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत के बहाने प्रदेश में चुनाव प्रचार का विधिवत आगाज किया। साथ ही दिग्गज भाजपाइयों की उपस्थिति में अपने भाषण में कार्यकर्ता को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए चेहरे की बजाय कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव मैदान में उतरने पर पूरा जोर दिया है।

दरअसल, इस बार भाजपा मप्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी साथ-साथ कर रही है। जुलाई में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मप्र के ताबड़तोड़ प्रवास कर साफ संदेश दे दिया कि आने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा मोदी-शिवराज सरकार की उपलब्धियों के आधार पर लड़ेगी और इसमें चेहरा कमल का फूल होगा। शाह ने इंदौर में कार्यकर्ताओं को भी समझा दिया कि चुनाव जिताने की ताकत नेताओं में नहीं बल्कि केवल आप में है। उल्लेखनीय है कि शाह अकेले जुलाई में चार बार मप्र आए। उनके नियमित प्रवासों से भी स्पष्ट हो गया है कि मप्र विधानसभा चुनाव के सारे सूत्र केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में ही रहेंगे। कर्नाटक की सत्ता हाथ से फिसलने के बाद से भाजपा मप्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद आशंकित है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को नए सिरे से जोश भरने की कोशिश की। इसके बाद से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मप्र के विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। शाह निरंतर मप्र में आ रहे हैं और चुनाव के सारे सूत्र अपने हाथ में रखे हैं। दरअसल, भाजपा को डर है कि वर्ष 2024 से पहले मप्र में पार्टी को नुकसान हुआ तो ठीक नहीं होगा। उनके इंदौर दौरे से यह भी तय हो गया है कि भाजपा लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और चेहरे पर लड़ेगी किंतु राज्यों में वह चेहरे के स्थान पर कार्यकर्ताकृत चुनाव लड़ेगी। शाह ने साफ कहा कि भाजपा को चुनाव बूथ पर बैठा कार्यकर्ता जिता सकता है। प्रदेश में चुनाव जीतने का आधार कार्यकर्ताओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि आज यहां से संकल्प लेकर जाना है कि प्रचंड बहुमत के साथ 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना है तथा 2024 में लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।

मप्र में तीन-चार महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस और भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। ज्यादातर कांग्रेस नेता तो कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के बजाय कमल के फूल के नाम पर वोट मांगने की बात कह रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि 2018 के नतीजों से सबक लेकर भाजपा ने अपनी स्ट्रैटजी बदली है? क्या इस बार के चुनाव पूरी तरह मोदी के नाम पर लड़े जाएंगे? ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा

मप्र पर शाह का कंट्रोल

मप्र में सत्ता और संगठन में बदलाव के तमाम कयासों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि शाह ने यह संकेत भी दे दिया है कि मप्र में विधानसभा चुनाव का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल और इंदौर में भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह ने चुनावी जंग फतह करने की रूपरेखा बनाई। बैठक के पहले, बैठक के दौरान और बैठक के बाद जो संदेश निकला उससे साफ हो गया है कि मप्र में चुनाव का पूरा कंट्रोल अमित शाह के पास रहेगा। गौरतलब है कि मप्र की चुनावी कमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। इसके साथ ही संदेश दे दिया गया है कि प्रभारी भूपेंद्र चौधरी और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ही विधानसभा चुनाव के पावर सेंटर होंगे। अमित शाह ने राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों की तैयारियों का जायजा लिया। राज्य की 150 सीटों पर खास फोकस करने की रणनीति बनाई है।

सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का क्या होगा? राजनीतिक परंपरा में चुनावों के बाद सबसे बड़ी पार्टी का विधायक दल अपना नेता चुनता है। उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 2003 में भाजपा ने तय किया कि मप्र में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए और दिग्विजय सिंह के सामने उमा भारती को उतारा था। सफलता मिली तो यह परिपाठी बन गई। 2008 से लेकर 2018 तक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और उनके चेहरे को दिखाकर ही भाजपा ने वोट मांगे। पिछले चुनाव में भाजपा को मिली हार ने स्ट्रैटजी बदलने को मजबूर कर दिया है। यह बात अलग है कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक भाजपा में आ गए और सरकार फिर भाजपा की बनी। उस समय शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि भाजपा के पास उनके जैसे व्यक्तित्व वाला कोई और नेता नहीं है। अब 2023 के चुनावों को लेकर पार्टी के नेता शिवराज की जगह कमल के फूल को चेहरा होने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा लिया जा रहा है। उनके कटआउट भी शिवराज से बड़े लग रहे हैं। सागर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि पार्टी का चेहरा कमल का फूल होगा। एक दिन पहले इंदौर में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी इसे दोहराया। उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही चेहरा होगा। इन बयानों से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बढ़ रहा है।

2018 में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। भाजपा को मालवा-निमाड़, ग्वालियर-चंबल और महाकौशल में भारी नुकसान हुआ था। भाजपा इन क्षेत्रों में खोया जनाधार बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों को मजबूती देना चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर कमल के फूल को चेहरा बनाया गया है। कमल के फूल के पीछे सभी नेता एकजुट हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस में क्षेत्रीय क्षत्रप होते थे। अब भाजपा में भी कई क्षेत्रों में समान कद के कई नेता हैं। उनका अपने क्षेत्र और कार्यकर्ताओं पर प्रभाव है। यह एक जमाने में कांग्रेस के साथ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद यह लाइन और गहरा गई है। ऐसे में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने कमल को आगे रखकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।

संघ के सूत्रों का कहना है कि भाजपा अब भविष्य को देखते हुए नेताओं की जगह कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने जहां कार्यकर्ताओं को महत्व देने का निर्देश जारी दिया है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ और असंतुष्ट नेताओं को भी महत्व देने को कहा है। गौरतलब है कि मप्र भाजपा में पुराने नेताओं में नाराजगी और असंतोष है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें मनाने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। नेता कार्यकर्ताओं को कमल चेहरा होने की बात कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमल मतलब कार्यकर्ता। ताकि उनकी नाराजगी दूर कर उन्हें चुनावी तैयारी में लगाया जा सके। एक निश्चित समय तक रहने के बाद जनता सत्ताधारी दल से असंतुष्ट हो जाती है। बदलाव चाहती है। 2018 के डेढ़ साल छोड़ दें तो भाजपा 2003 से सत्ता में है। शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमला बोल रही है। उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार, घोटाले गिना रही है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा अब शिवराज की जगह कमल के फूल को चेहरा बता रही है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार गत दिनों हुई बैठक में अमित शाह ने भाजपा की मप्र इकाई से दो टूक कहा है कि हर हाल में पार्टी के नाराज नेताओं को मनाना होगा। उनकी नाराजगी दूर करने के साथ यह संदेश हर कार्यकर्ता और नेता तक पहुंचना है कि एकजुट होकर लड़ने पर ही जीत मिलेगी। सरकार बनी तो सबका ध्यान भी रखा जाएगा।

इसी वजह से भाजपा मप्र में पूरी ताकत झोंक रही है। शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी प्रदेश में बढ़ाए जा रहे हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में शाह ने उन्हें भी समझा दिया कि अब वाद-विवाद का समय नहीं बचा है। सरकार रहेगी तो ही आपकी पूछ-परख होगी। अन्यथा फिर आपको भी कोई पूछने वाला नहीं है। शाह की सक्रियता से साफ है कि भाजपा कांग्रेस की ताकत बढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए मप्र में उसे रोकने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि अमित शाह का पाथेय कार्यकर्ताओं को मिला है। उन्होंने विजय संकल्प के साथ चुनाव का आगाज कर दिया है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार कांग्रेस के अस्त्र हैं, भाजपा इन पर किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 51 प्रतिशत मत लाने का संकल्प दिलाया है। इसी विजय संकल्प के साथ एक-एक कार्यकर्ता जनता के बीच जाएगा।

● कुमार विनोद

शिवराज-वीडी का नेतृत्व

इस बार मप्र में भाजपा हाईकमान ने भले ही चेहरे को महत्व नहीं दिया है लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव 2023 के तहत मप्र पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। शाह जहां प्रादेशिक नेताओं में समन्वय बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय नेताओं से उनके क्षेत्र की विधानसभा सीटों का फीडबैक भी लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने मालवा और निमाड़ की सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय से बात की है, तो वहीं ग्वालियर-चंबल की सीटों पर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की। विंध्य और बुंदेलखंड के साथ-साथ महाकौशल की सीटों पर प्रहलाद पटेल से बात हुई। यही नहीं वे दावेदारों की कुंडली और वहां के समीकरण साथ ले गए हैं। यह भी लिस्ट ले गए हैं कि कब कौन हारा और कब जीता। लोकल कारण क्या रहे, इस पर समीक्षा भी की जा रही है। वे यहां के संगठन के नेताओं का स्पष्ट संदेश देकर गए हैं कि चुनाव में किसी भी हाल में 2018 जैसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। प्रदेश की 230 में से अधिकतर सीटें भाजपा को जीतना है। एक बार फिर भाजपा को कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल बताकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़े नेताओं को आईना दिखा दिया।

रेत खदानों से भरेगा सरकार का खजाना

मप्र में रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मप्र सरकार ने इस बार 1500 करोड़ रुपए के मुनाफे का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन अब तक हुई नीलामी में 1676 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं। नीलाम खदानें सितंबर के बाद से चालू होंगी। प्रदेश में बालाघाट की जिला रेत खदान समूह सबसे महंगी नीलाम हुई है। यहां खदान समूह की ऑफसेट प्राइज 37 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन ये रेत खदान समूह 84 करोड़ से अधिक में नीलाम हुई। यानी ऑफसेट प्राइज से 31 फीसदी ज्यादा में खदान नीलाम हुई। महंगी रेत खदानें नीलाम होने से सरकार को रेवेन्यू का फायदा तो हुआ है, लेकिन इसकी कीमतें जनता को अपनी जेब से देनी होगी। प्रदेश में 42 जिले की 44 रेत खदान समूहों की नीलामी की आखिरी तारीख आज है, लेकिन अब तक करीब 25 जिलों में रेत खदान समूह के नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खनिज संसाधन विभाग द्वारा मप्र के 44 जिलों में 101 रेत खदानों को नीलाम किया जाएगा। रेत की खदानें अगले तीन साल के लिए नीलाम की जाएंगी। निविदा में आने वाले अधिकतम मूल्य को आधार बनाकर खदानों की बोली लगवाई जाएगी। यह खदानें तीन साल के लिए नीलाम होंगी।

रेत खदानों की पहले दौर की नीलामी ने सरकार को 300 करोड़ का फायदा करा दिया। सरकार ने 25 जिलों के 27 रेत समूहों का रिजर्व प्राइज 660.23 करोड़ रुपए रखा था, लेकिन कई दौर की नीलामी के बाद यह 963.03 करोड़ में गई। जबकि अभी भी 17 रेत समूहों की नीलामी बाकी है। ज्यादा कीमत पर उठीं रेत खदानों से साफ है कि इनकी कीमतें अब और बढ़ेंगी। हालांकि सरकार यह मानकर चल रही है कि जब ज्यादा खनन होगा और बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी तो कीमतें अपने आप कम होंगी। बहरहाल, 42 जिलों के 44 रेत समूहों की 1171 रेत खदानों में 3.76 करोड़ घनमीटर रेत की उपलब्धता है। इसका रिजर्व प्राइज सरकार ने 939.78 करोड़ रुपए रखा है। इसमें से 27 रेत समूहों का रिजर्व प्राइज 660.23 था। इससे ही सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपए ज्यादा आ गए। ई-नीलामी की प्रक्रिया एक जुलाई से प्रारंभ की गई, जो 8 अगस्त तक चली। यहां बता दें कि स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन को रेत खदानें 10 वर्ष की लीज पर दे दी गई हैं। यहां बता दें इस बार प्रति घन मीटर रेत का रिजर्व प्राइज 125 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है जो दो गुना है। इसी वजह से रेत की कीमतें बढ़ने की संभावना बन गई है।

रेत उत्खनन के मामले में मप्र में नर्मदापुरम सबसे बड़ा जिला है। नर्मदापुरम में तहसील स्तर पर तीन समूह बनाए गए हैं, जबकि 43 जिलों में जिला स्तर पर ही रेत समूह नीलाम होंगे। नर्मदापुरम जिले में तीनों रेत खदानों का निविदा के लिए प्रारंभिक आधार मूल्य 160 करोड़ (75, 55 और 30 करोड़) रुपए निर्धारित किया गया है। इस तरह सभी 44 जिलों में रेत खदानों का प्रारंभिक निविदा मूल्य 779 करोड़ रुपए रखा गया है। नर्मदापुरम की रेत खदानें भी नीलाम हो गई हैं। यहां तीनों रेत खदान समूह ऑफसेट प्राइज से 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए से अधिक में नीलाम हुई हैं। भोपाल और सीहोर की रेत खदानें काफी महंगे दामों में नीलाम हुई हैं, सीहोर जिले की रेत खदानों की न्यूनतम दर 65 करोड़ तय की गई थी, लेकिन करीब 70 करोड़ में नीलाम हुई है। रेत कारोबार से जुड़े सूत्रों के अनुसार प्रदेश की 25 जिलों की 27 रेत समूहों के नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष जिला रेत खदान समूहों के नीलामी की प्रक्रिया अभी जारी है। बताया जाता है कि खदानों की ऑफसेट प्राइज 1,250 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन अब तक हुई नीलामी में 1676 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं। नीलाम खदानें सितंबर के बाद से चालू होंगी।

मप्र सरकार ने रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया का जिम्मा खनिज निगम को सौंपा है। रेत खदानों का संचालन खनिज निगम ही करेगा। इस बार पहली बार खनिज निगम सभी तरह की जरूरत अनुमतियां लेकर ही ठेकेदारों को सौंपेगा। ऐसे में रेत ठेकेदारों को किसी तरह की परेशानी से नहीं जूझना होगा। इससे पहले ठेकेदार ही इस तरह की अनुमतियां लेते हैं, नतीजतन एक-एक साल तक ठेकेदार अनुमति नहीं ले पाते थे और वे बीच में ही रेत ठेके छोड़ देते थे। बता दें इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार में साल 2019 में रेत खदानें नीलाम हुई थीं, इस दौरान 1400 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इस बार 1500 करोड़ रुपए का मुनाफा तय किया गया है। नीलामी के तीन खदानों में 3 करोड़ 11 लाख घन मीटर रेत निकाली जाएगी, इसमें सबसे अधिक 64 लाख घन मीटर रेत नर्मदापुरम जिले की खदानों से निकाली जाएगी।

● **लोकेंद्र शर्मा**

17 जिलों में ठेकेदारों की रुचि नहीं

प्रदेश के 17 जिला खदान समूहों के लिए ठेकेदारों ने रुचि नहीं दिखाई है। इनमें गुना, राजगढ़, धार, देवास, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, शाजापुर, डिंडोरी, पन्ना, टीकमगढ़, अलीराजपुर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा और भिंड जिला शामिल हैं। इन जिलों में एक दो से ठेकेदार निविदा में शामिल हुए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश ठेकेदार उपयुक्त नहीं पाए गए। कुछ खदानों के लिए तीन दो से ज्यादा ठेकेदार बोली में शामिल हुए, लेकिन इन्हें तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाए जाने के कारण निविदा प्रक्रिया शून्य कर दी गई है। गुना, राजगढ़, धार, देवास, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, शाजापुर, डिंडोरी, पन्ना, टीकमगढ़, अलीराजपुर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा और भिंड में रेत खदानों की नीलामी अभी बाकी है। पहले चरण में 27 समूहों के पास 2.64 करोड़ घन मीटर रेत नीलामी गई है। शेष 1.12 करोड़ घन मीटर रेत अभी भी नीलामी के लिए बची हुई है। भिंड में रेत खदानों की नीलामी अभी नहीं हुई है। यहां खींचतान ज्यादा है। राजस्थान के साथ उप्र के भी वेंडर जोर-आजमाइश कर रहे हैं। यही स्थिति पन्ना को लेकर भी है। यहां भी उप्र के कॉन्ट्रेक्टर सक्रिय हैं। सरकार को इससे भी 100 करोड़ से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।

आयोगों की जांच अधर में

मप्र में बीते डेढ़ दशक में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण हुए बड़े हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। अपनों को खोने का दर्द उनके परिवार के लोग अभी भी झेल रहे हैं। जिनके कारण यह दर्द मिला, उन दोषियों पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने जनमानस के जख्म पर मरहम लगाने के लिए ऐसे बड़े मामलों में न्यायायिक जांच आयोग का गठन किया था। इनकी रिपोर्ट भी आई लेकिन अब तक किसी भी दोषी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। जबकि जांच आयोग में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ऐसे में अब लोग सवाल करने लगे हैं कि किसकी मजाल है जो न्यायायिक जांच आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सके।

गौरतलब है कि न्यायायिक जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा-3 के तहत गठित होता है। फिर गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी कार्रवाई पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। न्यायिक आयोग बनाए जाते हैं। ये आयोग इसलिए गठित किए जाते हैं, ताकि जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसकी असलियत जनता के सामने आ सके। आयोग जांच करता है। जांच के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? असलियत ये है कि आयोग की रिपोर्ट विभागों में धूल खाती है। प्रदेश में 15 साल में 8 आयोग की रिपोर्ट आई हैं और वे धूल खा रही हैं। जबकि इस दौरान 4 सरकारें आईं, लेकिन एक भी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। मप्र में 6 बड़े हादसों में 374 मौतें हुई हैं। किसी में मजिस्ट्रियल तो किसी में ज्यूडिशियल जांच के आदेश हुए। हर हादसे के बाद जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का सरकारी ऐलान हुआ, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई।

जब भी कोई बड़ी घटना-दुर्घटना होती है सरकार न्यायायिक जांच आयोग का गठन कर देती है। आयोग के अध्यक्ष, सचिव, दो क्लर्क, एक स्टेनो, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर आदि के वेतन, इसके अलावा यात्रा भत्ता, खाने-पीने का खर्च, दो कम्प्यूटर, स्टेशनरी, पूरा दफ्तर का सामान, दो गाड़ियों का खर्च, इस तरह एक महीने में कम से कम लाखों रुपए खर्च करते हुए करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वह कहां खो जाती है इसकी सुध किसी को नहीं रहती है। 15 साल में राज्य में चार सरकारें सत्ता में रहीं। इसमें तीन बार भाजपा और डेढ़ साल कांग्रेस का शासनकाल रहा। इस कार्यकाल में राज्य में कई बड़ी वारदातें हुईं। सरकार ने इसकी जांच के लिए 8 आयोग बनाए। आयोगों ने सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन ये रिपोर्ट फाइलों में कैद हो गईं। 15 साल बाद भी सरकार ये रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं पहुंचा सकी है, जबकि मंत्रालय से विधानसभा की दूरी महज आधा किमी है। 15वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब नई सरकार में ही जिम्मेदारी तय होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इनमें से पेटलावट में मोहर्रम जुलूस रोकने की घटना की जांच रिपोर्ट सरकार ने विधानसभा में रखा। अन्य आयोगों की अनुशंसाओं पर कार्रवाई चल रही है। मंदसौर गोलीकांड, वृद्धावस्था पेंशन घोटाला समेत कई जांच आयोगों की रिपोर्ट फाइलों में बंद हैं।

वर्ष 2008 से लेकर अभी तक सरकार ने 9 मामलों में आयोग का गठन कर जांच करवाई है। इनमें से 8 की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन वे धूल खा रही हैं। सरकार ने 18 फरवरी 2008 को सामाजिक सुरक्षा व वृद्धावस्था पेंशन योजना की अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग बनाया था। आयोग ने 15 सितंबर 2012 को रिपोर्ट सबमिट की। 15 साल में सरकार रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रख सकी। इसमें कई नेता, अफसर घेरे में हैं। कई बार सवाल भी उठे, पर हर बार सरकार ने कार्रवाई की बात कही। वहीं मंदसौर गोलीकांड में 6 जून 2017 को 5 किसानों की मौत के बाद सरकार ने 13 जून 2018 को जांच के लिए रिटायर्ड जज जेके जैन की अध्यक्षता में जैन आयोग बनाया। आयोग ने 13 जून 2018 को रिपोर्ट दी। पूर्व विधायक पारस सखलेचा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा, रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखना जरूरी है, पर सरकार जानबूझकर नहीं रख रही। वहीं भोपाल में यूका जहरीली गैस रिसाव की रिपोर्ट आयोग ने 24 फरवरी 2015 को सबमिट की। गैस राहत विभाग में कार्रवाई चल रही है। भिंड गोली चालन में जांच आयोग ने 31 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट सबमिट की। जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई चल रही है। गोलपुरा-2 मानमंदिर ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के मामले में आयोग ने 9 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दी, यह गृह विभाग में पड़ी है। पेटलावद के विस्फोट मामले की जांच रिपोट आयोग ने 11 दिसंबर 2015 को मुख्य सचिव को भेजा। यह गृह विभाग को भेजा गया। पेटलावद में मोहर्रम जुलूस रोकने की घटना की जांच आयोग ने 20 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दी। 5 जुलाई 2019 को यह विधानसभा के पटल पर रखा गया। मंदसौर में घटित घटना की जांच आयोग ने 14 जून 2018 को गृह विभाग को भेजी। लेकिन रिपोर्ट के मिलने के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं इंदौर में पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर की बावड़ी की छत धंसने से हुई 36 मौतों के मामले में पिछले दिनों पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट मिल गई है। सभी मौतें पानी में डूबने से हुई हैं। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट नहीं मिलने से पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ी। तत्कालीन अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर जांच कर रहे थे। बताया जा रहा है, जांच पूरी हो गई। हालांकि अधिकारिक खुलासा नहीं किया। बता दें, 30 मार्च को रामनवमीं पर पूजा के दौरान मंदिर परिसर में बावड़ी की छत धंस गई थी। इसमें 36 लोगों की गिरने से मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।

● **राकेश ग्रोवर**

जांच आयोग ने लिखा कि अफसर दोषी हैं, लेकिन सब बच गए

शिवपुरी स्थित मड़ीखेड़ा डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से रतनगढ़ में 1 अक्टूबर 2006 को सिंध नदी में डूबने से 47 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हादसे की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने जस्टिस एसके पांडेय की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया था। आयोग ने जांच के बाद साफतौर से लिखा था कि यह बड़ी दुर्घटना है, ज्यादा लोगों की मौत हुई है, अधिकारियों की उदासीनता दंडनीय है। आयोग ने कहा था कि गृह विभाग के निर्देश की कलेक्टर ने अनदेखी की, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। देवास के धाराजी हादसे के बाद गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके ठीक 8 महीने बाद यह हादसा हो गया था। तत्कालीन कलेक्टर एम गीता को दोषी माना था, लेकिन उन्हें निलंबित तक नहीं किया गया था। जांच आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन लेने के बजाय सरकार ने तीन मंत्रियों की उप समिति बनाई थी। इस समिति ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वह रिपोर्ट ही कहीं अलमारी में बंद पड़ी रही।

मप्र में भ्रष्टाचार की पंचायतें

पिछली बार के 4,309 केस लंबित

मप्र की पंचायतों में भ्रष्टाचार का आलम क्या है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली बार यानी 2014-15 में चुने गए कई सरपंचों ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। किसी भी सरकारी योजना को नहीं छोड़ा। इन पर विकास के पैसे को अपनी जरूरतों में उड़ाने का आरोप है। कोई कपिलधारा योजना के कुएं पी गया तो किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान खा लिए। इनमें से कई तो शौचालय बनाने के लिए आए पैसे तक हजम कर गए। बीते पांच साल में पंचायत एक्ट के तहत ऐसे सरपंचों और पंचायत सचिवों पर 4309 केस दर्ज हुए हैं। भ्रष्टाचार, गबन, हेराफेरी के आरोपों में 483 सरपंच हटाए जा चुके हैं। जबकि 2858 मामलों में सरपंचों और सचिवों से अब वसूली की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोपी 456 अन्य सरंपचों पर कार्रवाई होना बाकी है। बड़ी बात ये है कि प्रदेश की पंचायतों के भ्रष्टाचार से एक भी जिला अछूता नहीं है। इन 2858 में से सिर्फ 222 मामलों में आरोपियों ने पैसे जमा कराए हैं। अभी भी 2636 के खिलाफ एफआईआर होना बाकी है। सबसे बड़ा घपला सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुआ। इसमें स्कूलों के भवन, बाउंड्रीवाल, खेल मैदान और खेल सामग्री के लिए पैसा आया, लेकिन सरपंचों और सचिवों की मिलीभगत से उस पैसे की बंदरबांट कर ली गई।

पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिन लोगों पर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी है, वे ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आलम यह है कि सरपंच और पंचायत सचिव मिलकर कहीं सड़क खा गए, कहीं कुएं पी गए, कहीं शौचालय ही चट कर गए। अब ऐसे भ्रष्टों के खिलाफ खुद जनता ने मोर्चा खोल दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भ्रष्टाचार की 3 हजार से अधिक शिकायतें आ गई हैं। गौरतलब है कि दूसरी तरफ सरकार ने हाल ही में सरपंच से लेकर जिपं अध्यक्ष के वेतन-भत्ते बढ़ाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। संचालक, पंचायत राज संचालनालय के आदेश अनुसार जिपं अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए मासिक मिलेंगे। इसमें मानदेय राशि 35 हजार और वाहन भत्ता 65 हजार रुपए शामिल हैं। जिपं उपाध्यक्ष का मानदेय एवं वाहन भत्ता मिलाकर 42 हजार रुपए मासिक, जपं अध्यक्ष को 19 हजार 500 रुपए और जपं उपाध्यक्ष को 13 हजार 500 रुपए मासिक मिलेंगे। साथ ही पंच-उप सरपंच की अधिकतम वार्षिक मानदेय राशि में वृद्धि कर 1800 रुपए की गई है।

दरअसल, जब से पंचायतों में विकास के लिए फंड मुहैया कराया जाने लगा है, तभी से भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने लगे हैं। सरपंचों ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। किसी भी सरकारी योजना को नहीं छोड़ा। इन पर विकास के पैसे को अपनी जरूरतों में उड़ाने का आरोप है। कोई कपिलधारा योजना के कुएं पी गया तो किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान खा लिए। इनमें से कई तो शौचालय बनाने के लिए आए पैसे तक हजम कर गए। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी समस्या से लड़ने के लिए अब लोग खुलकर आगे आने लगे हैं। उनके द्वारा सरपंच और सचिव के खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही हैं। खासतौर पर ग्रामीणों को गुमराह करना, आधे-अधूरे विकास कार्य कर खानापूर्ति करना आदि हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतें भी की जा रही हैं।

मप्र में पंचायती राज व्यवस्था में किस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब जनता खुद शिकायतें दर्ज कराने सामने आ रही है। पिछले तीन माह के अंदर शिकायतों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस तरह के मामलों को लेकर करीब तीन हजार से अधिक ग्रामीणों ने शिकायतें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में की हैं। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और मैदानी अमलों पर गबन, फर्जी तरीके से राशि निकालने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि वर्क ऑर्डर अथवा काम स्वीकृति के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। जबकि इस कार्य के लिए सरपंच, सचिव सरकारी खजाने से पूरी राशि निकाल चुके हैं। ग्रामीणों ने इन कार्यों को पूरा करने और मामले की जांच कराने के लिए सरकार से मांग की है। विभागीय सूत्रों के अनुसार विभाग के अधिकारियों ने जांच के दौरान कई शिकायतें सही भी पाई हैं। इसके आधार पर मैदानी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।

प्रदेश में सरपंच और सचिवों के भ्रष्टाचार की रोजाना पोल खुल रही है। प्रदेशभर में लगातार चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। भिंड जिले के ग्राम बड़पुरी में सीसी रोड बनाने के लिए दो वर्ष पहले राशि निकाली गई थी। रोड नहीं बनाई गई, जबकि सरपंच और सचिव ने इस रोड के निर्माण के लिए राशि निकाली है। रवि खान ने इस मामले की शिकायत भी जनपद पंचायत में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है। वहीं प्रकाश लोधी ने शिकायत की है कि पन्ना जिले के बधवारा कलां में निर्माण कार्यों के लिए सचिव और सरपंच राशि लगातार राशि निकाल रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकी जांच कराई जाए। आगर मालवा, ग्राम नंदोरा के निवासी योगेश सूर्यवंशी का कहना है कि उनके गांव में सरपंच और सचिव ने सड़क बनाने के लिए राशि निकाली थी, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से इसकी जांच कराने की मांग की है।

पंचायत राज अधिनियम की धारा-40 के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में सरपंच को उसके पद से हटाने का प्रावधान है। पहले यह कार्रवाई एसडीएम करते थे, लेकिन बीते दो साल जिला पंचायत के सीईओ कर रहे हैं। सरकारी धन के दुरुपयोग या गबन पर धारा-92 के तहत वसूली का अधिकार भी सीईओ को है। धारा-92 के तहत वसूली आदेश निकलते हैं। एसीएस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मलय श्रीवास्तव का कहना है कि प्रत्येक शिकायत की जांच कराई जाती है। कार्य में गड़बड़ी करने वाले सरपंच, सचिव, इंजीनियरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है। कई बार लोग दुर्भावना से भी शिकायतें करते हैं। यह अच्छा है ग्रामीणों में निर्माण और विकास कार्यों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।

● **अरविंद नारद**

सांसदों का गांवों से मोहभंग!

करीब 10 माह बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। लेकिन विडंबना यह देखिए की विकास की बड़ी-बड़ी बात करने वाले मप्र के सांसदों ने गांवों के विकास के लिए शुरू की गई आदर्श ग्राम योजना के अधिकांश सांसदों ने रूचि नहीं दिखाई है। स्थिति यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक सहित 13 सांसदों ने एक भी गांव को गोद नहीं लिया है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों और गांवों को आदर्श बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम कार्यकाल में ही प्रारंभ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को हर साल एक-एक ग्राम पंचायत को गोद लेना था लेकिन कई सांसद मोदी सरकार में ऐसे हैं जिनकी इस योजना में बिल्कुल भी रूचि नहीं है और उन्होंने एक भी ग्राम पंचायत को गोद नहीं लिया है।

मोदी सरकार में वर्ष 2014 में शुरू हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना के दूसरे पार्ट (एसएजीवाई-2, 2019-2024) में मप्र के सांसद कोई रूचि नहीं दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से यहां के 40 सांसदों में सिर्फ ढालसिंह बिसेन (बालाघाट) ही ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना में पूरी पांच ग्राम पंचायतों को गोद लिया है। गौरतलब है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी को विकास पुरूष बताने वाले भाजपा सांसदों ने ही इस योजना में रूचि नहीं दिखाई है। इन हालातों को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मप्र ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है कि वे जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों का चयन कर कलेक्टर को बताएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एसएजीवाई-2 में प्रावधान है कि पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक ग्राम पंचायत का चयन होना है। कई सांसदों ने पूरी पांच ग्राम पंचायतों का चयन ही नहीं किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने ही सांसदों पर सांसद आदर्श ग्राम योजना का रंग नहीं चढ़ पा रहा है। जिसकी वजह से इस योजना को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों को अभी से चिंता सता रही है। वे सांसत में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्वपनिल योजना होने की वजह से अधिकारियों पर किसी भी तरह से योजना को परवान चढ़ाने का दबाव है। पीएमओ की ओर से योजना की सफलता को लेकर लगातार अपडेट भी मांगे जा रहे हैं। मगर योजना के प्रति भाजपा सांसदों के जरिए ही उत्साह न दिखाने से मंत्रालय के अधिकारी परेशान हैं। लगातार आग्रह के बाद भी सांसद दूसरे चरण के लिए गांव गोद लेने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर दूसरे चरण के गांव गोद लेने का आग्रह किया था। लेकिन उस पत्र का भी असर सांसदों पर होता नहीं दिख रहा है। मप्र के 40 सांसदों को कुल 200 ग्राम पंचायतों को गोद लेना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 62 ली गई हैं। 138 बाकी हैं। यदि ये सारी गोद ले ली गई होतीं तो ग्राम पंचायतों का कायाकल्प हो गया होता। इस योजना में ग्राम पंचायत के बुनियादी ढांचे के साथ उसका पूरा विकास, लोगों को काम के साथ समान अधिकार देना, असमानता खत्म करना, जनजीवन बेहतर करने समेत शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर ठीक करने जैसे काम होते हैं। एसएजीवाई-2 में प्रधानमंत्री मोदी का मिशन था कि 2500 गांवों को बेहतर करें, लेकिन सांसदों का तर्क है कि वे 500-700 गांवों के साथ करीब 2000 बूथ पर चुनाव लड़कर सांसद बनते हैं। पांच गांव गोद लेंगे तो बाकी क्षेत्र के लोग नाराज होते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में देशभर के सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव चुनने और उन्हें तकनीकी, सांस्कृतिक रूप से आदर्श बनाने के निर्देश दिए थे। इस बार प्रधानमंत्री ने प्रत्येक सांसद को पांच गांव गोद लेकर अपने कार्यकाल में उन्हें आदर्श ग्राम में बदलने को कहा है। यह निर्देश मई 2019 में दिए गए थे, लेकिन प्रदेश में इन निर्देशों का असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन चार साल से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक 13 सांसदों ने एक भी गांव को गोद नहीं लिया है। इनमें एल मुरुगन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि, हिमाद्रि सिंह, रीति पाठक, डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक, अजय प्रताप सिंह, गणेश सिंह, सुधीर गुप्ता, विवेक तन्खा, छतरसिंह दरबार शामिल हैं। वहीं एक ग्राम पंचायत गोद लेने वालों में दिग्विजय सिंह, राजमणि पटेल, कैलाश सोनी, रमाकांत भार्गव, जनार्दन मिश्रा, रोडमल नागर, विवेक नारायण शेजवलकर, नकुलनाथ शामिल हैं। दो ग्राम पंचायत लेने वालों में दुर्गादास उइके, संध्या राय, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, महेंद्र सोलंकी, ज्ञानेश्वर पाटिल, नरेंद्र सिंह तोमर, राज बहादुर सिंह शामिल हैं। वहीं तीन ग्राम पंचायत गोद लेने वालों में अनिल फिरोजिया, गुमान सिंह डामोर, फग्गन सिंह कुलस्ते, विष्णुदत्त शर्मा, उदय प्रताप सिंह, कृष्णपाल यादव शामिल हैं। चार ग्राम पंचायत वाले सांसदों में शंकर ललवानी, राकेश सिंह, गजेंद्र पटेल, धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।

● **राजेश बोरकर**

योजना में तीन बातों पर जोर

सांसद ग्राम का मकसद गांव में सफाई, सड़क, स्वास्थ्य से जुड़े काम बेहतर कराना है। सांसद जिन गांवों को गोद लेता है, वहां सभी विभाग अपने काम प्राथमिकता से करते हैं। मसलन, स्वच्छता मिशन, सड़क, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि के काम तेजी से होते हैं। योजना में गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर ध्यान दिया जाना है। इसमें तीन बातों पर जोर दिया गया है। गांव के लिए जो भी योजना बनाई जाए, वह मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और उसमें जनता की भागीदारी हो। योजना का मुख्य उद्देश्य सांसदों की देखरेख में चुनी गईं ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत ग्रामों के विकास के लिए इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना और मनरेगा से फंडिंग की जाती है। अभी जितनी भी गोद ली गई पंचायतें हैं, वहां स्वच्छता के काम हो गए हैं। लेकिन सांसद मानते हैं, 5 गांव गोद लेने से बाकी लोग नाराज होते हैं। योजना से सांसदों की बेरुखी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे। वे भी पूरी तरह से विकास कार्य नहीं करा सके। जबकि उन्हें दो साल में पूरी तरह से गांव की तस्वीर बदलनी थी।

मप्र में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर उस पर अमल करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी सरकारी एजेंसियां भ्रष्टों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। इन सबके बीच हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के कुछ मंत्रियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है। यह भ्रष्टाचार ट्रांसफर से लेकर विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन तक में हो रहा है। इससे सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लागू नीति को पलीता लग रहा है।

ट्रांसफर का खेला

कथित तौर पर मप्र देश के सबसे सुशासित राज्यों में से एक है। सरकार इस बात को लेकर लगभग हर मंच पर दावे करती रहती है। लेकिन इससे इतर प्रदेश के सबसे प्रमुख और बड़े पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ऐसा है, जहां सरकार की न नीति चलती है और न ही नीयत। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विभाग में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और उनकी भर्राशाही, लाटशाही, लालफीताशाही और मनमानी चलती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस विभाग में लगभग रोजाना ट्रांसफर होते हैं। ये ट्रांसफर केवल **हाथी के दांत** की तरह होते हैं। यानी सिखाने और चमकाने के लिए। बताया जाता है कि विभागीय मंत्री विभाग में चल रही योजनाओं की चिंता करते हैं, परंतु उनका निजी स्टाफ केवल इस बात के गुणा-भाग में लगे रहते हैं कि किसके ट्रांसफर से कितनी कमाई होगी। फिर शुरू होता है ट्रांसफर का खेला। विभाग में किसी न किसी अधिकारी के ट्रांसफर की नोटशीट तैयार की जाती है। वहीं स्टाफ द्वारा मंत्रीजी को पाठ पढ़ाकर नोटशीटों पर साइन करा ली जाती है। (अक्स के पास ऐसी कई नोटशीटें हैं, जिन पर हस्ताक्षर तो हैं, परंतु डिस्पेच नहीं हैं) और फिर मंत्री के गुर्गों को सौंप दी जाती है। फिर शुरू होता है, वसूली का खेल। यह खेल मंत्रीजी के संज्ञान में है कि नहीं, यह तो वही जानें।

ट्रांसफर का भय दिखाकर वसूली में जुटे मंत्रीजी के तीन गुर्गे गांधीजी के तीन बंदरों की तरह ही हैं। ये न तो कुछ देखते हैं, न कुछ सुनते हैं और न कुछ बोलते हैं। बस वसूली के खेल में जुट जाते हैं। मंत्रीजी के इन तीनों गुर्गों को लेकर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में हर किसी को उत्सुकता है। इसी उत्सुकता में जब मंत्रीजी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये सभी मेरे विश्वसनीय हैं। यानी मंत्रीजी की आड़ में उनके विश्वसनीय लोग ट्रांसफर की नोटशीट निकालकर अफसरों से वसूली कर रहे हैं।

यहां बता दें कि मंत्रीजी पलायनवादी संस्कृति वाले हैं। उन्होंने साढ़े तीन साल पहले अपने श्रीमंत का इशारा मिलते ही अपनी मूल पार्टी छोड़ दी और विरोधी विचारधारा वाली भाजपा का दामन थाम लिया। यह पार्टी भले ही मंत्रीजी के मूल विचारों से विपरीत विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन मंत्रीजी के लिए यह किसी दुधारू गाय से कम नहीं है। मंत्रीजी अपनी सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मिलने के बाद से पूरी कर रहे हैं। आलम यह है कि अकेले मंत्रीजी ही नहीं, बल्कि उनके नाते-रिश्तेदार भी विभाग की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मंत्रीजी के नजदीकी रिश्तेदार और प्रभावशाली परिवार से संबंध रखने वाले एक धनाढ्य व्यक्ति। इन महाशय की वैसे तो दोनों पार्टियों में उनकी अच्छी पैठ है। ऐसे में उन्हें अपने रिश्तेदार मंत्रीजी का साथ क्या मिला, सोने पर सुहागा हो गया। अब वे सरकार से संबंध बनाकर लाइजिंनिंग कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये महाशय रीयल स्टेट के कारोबार में संलिप्त हैं। रीयल स्टेट से जुड़े हुए समीकरण में सिंचाई विभाग के ट्रेशर सुरेंद्र श्रीवास्तव मंत्री और उनके नजदीकी रिश्तेदार का काम देखते हैं। इसका अंदाजा कोई भी इनके डिलडौल को देखकर लगा सकता है।

बताया जाता है कि जब ये मंत्रीजी के यहां आए थे तो इनकी सामान्य कद-काठी थी। अब इनके पेट का साइज इतना बड़ा हो गया है कि वे शर्ट पहनते हैं तो वह भी चीखें मारने लगती

तबादले का ऐसा खेल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में तबादले का खेल कैसा चल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 मई 2022 को विदिशा जिले के कागपुर भ्रमण के दौरान अनियमितता मिलने और जनपद पंचायत प्रतिनिधियों के धरने के बाद जनपद पंचायत नटेरन के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएल कुरेले एवं पूर्व सहायक यंत्री एनपी मेहर के स्थानांतरण एवं जांच कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन मेहर उसी दिन से बीमारी का बहाना बनाकर अवकाश पर चले गए थे। करीब 8-9 महीने बाद उन्होंने जाकर ज्वाइनिंग दी। लेकिन 14 महीने बाद सीएम के यहां से ए-प्लस नोटशीट आती है और उन्हें वहीं पदस्थ कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के आदेश का यह कैसा असर? गौरतलब है कि अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में भी यह बात लाई गई थी, लेकिन आदेश जारी हो गया। यह तो महज एक उदाहरण है। विभाग में इस तरह का खेल बराबर चलता रहता है। दरअसल, सरकार को अंधेरे में रखकर तबादले का खेल खेला जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में विभागीय मंत्री ने कुरेले और मेहर के खिलाफ मंत्री द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय जांच करने के लिए अपर मुख्य सचिव को आदेशित किया था, लेकिन उस पत्र में कोई डिस्पैच नंबर नहीं था। बाद में एनपी मेहर को फिर से उसी जगह पदस्थ कर दिया गया और कुरेले को 4-5 माह पूर्व बीना में पदस्थ कर दिया गया।

है। ऐसा लगता है, जैसे वह कभी भी फट जाएगी। मंत्रीजी के दूसरे शिल्पकार हैं बृजेश श्रीवास्तव। ये मंत्रीजी के प्राइमरी स्कूल मेट हैं और मंत्रीजी के खासमखास हुआ करते थे, लेकिन अब ये बेचारे बिना सहारे चल रहे हैं। मंत्रीजी का कहना है कि ये पहली क्लास से हमारे साथ पढ़ने वाले हमदर्द हैं। इनकी शिकायतें बहुत थीं। इसके चलते इन्हें हटाया गया, ताकि इनको लेकर मंत्री और विभाग पर जो सवाल उठ रहे हैं, वे खत्म हो जाएं। लेकिन यहां भी मंत्रीजी का दम देखने को मिला। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को हटाया भी तो उनके रिटायरमेंट के बाद। अब सुदामा बेचारा हो गया है, लेकिन मंत्री कहते हैं कि कृष्ण उसके साथ हैं। यही नहीं मंत्री तो यहां तक कहते हैं कि मेरे सुदामा अभी भी काम देख रहे हैं और उन्हें विभाग की पकड़ है, इसीलिए उनके अनुभव का लाभ लिया जाता है, क्योंकि वह भी पंचायत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के ही उपयंत्री हैं।

जांच पर कैसे आएगी आंच

विभाग में भ्रष्टाचार का खेल किस तरह चलता है, इसका एक उदाहरण खरगौन जिले के वाटर शेड कार्यों के निर्माण की जांच में देखने को मिला है। मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इंदौर परिक्षेत्र इंदौर हरीसिंह झणिया 26 जुलाई को आदेश निकालते हैं कि वाटरशेड कार्यों की जांच का प्रतिवेदन प्रभारी कार्यपालन यंत्री देवास अजमेर सिंह डुडवे करेंगे। डुडवे को इसके लिए 4 अगस्त तक इंदौर में संलग्न किया गया था। इस दौरान 3 अगस्त को झणिया द्वारा एक आदेश निकाला जाता है और डुडवे की जगह कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग देवास का समस्त प्रभार (वित्तीय प्रभार सहित) विजय कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग देवास को सौंपा जाता है। इस आदेश में लिखा गया कि प्रतिवेदन तैयार करने में समय लगने की संभावना को देखते हुए ऐसा किया गया है। ऐसा अंदेशा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में श्रीवास्तव प्रभारी कार्यपालन यंत्री लंबे समय तक बने रह सकते हैं। ऐसा करना किसी बड़े घोटाले का संकेत देता है। 2010 बैच के डायरेक्ट अधिकारी डुडवे को जहां प्रतिवेदन बनाने का काम देकर उनकी जगह उनसे जूनियर 2013 बैच के प्रमोटी विजय कुमार श्रीवास्तव को बैक डोर से एंट्री कराकर मुख्य अभियंता कार्यालय में अटैच कर दिया गया है।

गौरतलब है कि इंदौर में 8 डिवीजन हैं। अत: वहां पर 8 ईई हैं। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि 50 किमी दूर से श्रीवास्तव को बुलाकर यह काम सौंपा गया। क्या ये इतने काबिल हैं? दरअसल, इसमें साफ नजर आ रहा है कि पद का दुरुपयोग किया गया है। गौरतलब है कि इस काम की जांच सज्जन सिंह चौहान ने की थी। अगर उन्हीं से प्रतिवेदन बनवाया जाता तो वे जल्दी और आसानी से बना देते। अब प्रतिवेदन तैयार करने में जो खेल खेला जा रहा है, उससे लग रहा है कि इस जांच को दबाने की कोशिश हो रही है।

बृजेश श्रीवास्तव

महेंद्र द्विवेदी

सुरेंद्र श्रीवास्तव

प्रभारियों का जमावड़ा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रभारियों का जमावड़ा लग गया है। यानी यहां लगभग सारे प्रमुख काम प्रभारियों के हवाले हैं। विभाग का ईएनसी भी प्रभारी ही है। 4 अगस्त को मुख्य महाप्रबंधक मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण संभाग भोपाल मांगीलाल डाबर को ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का प्रभारी प्रमुख अभियंता बनाया गया। इससे पहले खूबचंद धुवकर इस पद पर थे। अब उन्हें प्रभारी मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र इंदौर बनाया गया है। जबकि खूबचंद के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज है। इस संदर्भ में ईओडब्ल्यू ने विभाग से जानकारी मांगी है, लेकिन विभाग जानकारी नहीं भेज रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार विभाग में ऐसे अफसरों को कौन संरक्षण दे रहा है।

ट्रेनिंग प्रोग्राम के सरताज

अभी हाल ही में कांग्रेस ने पंचायत राज प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2019-2020 में मप्र के नवनिर्वाचित पंचायत राज प्रतिनिधियों के कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के लिए इस राशि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यह राशि आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के लिए आरक्षित थी लेकिन इस ट्रेनिंग में गैर आदिवासियों को प्रशिक्षण देकर बजट को ठिकाने लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र से आदिवासी उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 8 करोड़ 42 लाख रुपए का फंड दिया गया था। ये फंड मप्र के सभी 52 जिलों में आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के लिए जारी किया गया था लेकिन पंचायत मंत्री ने इसे मात्र तीन जिलों (बड़वानी, सिवनी और धार) में दिखा दिया। और विभागीय अफसरों द्वारा कराई गई जांच में भी जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग होना नहीं मिला। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इंदौर संभाग की आदिवासी उपायुक्त द्वारा कराई गई जांच में सामने आया है कि पंचायत स्तर पर कराए गए इस ट्रेनिंग में दर्जनों ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की जानकारी ही नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र से मिले ट्रेनिंग के पैसे से ट्रेनिंग कराने के पहले ही केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया है। नियमों के मुताबिक प्रशासकीय स्वीकृति के लिए विभागीय एसीएस, पीएस और सेक्रेटरी के जरिए फाइल भेजी जाती है। लेकिन पंचायत मंत्री ने जबलपुर से आई फाइल को बिना एसीएस, पीएस की अनुशंसा के सीधे प्रशासकीय स्वीकृति दे दी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 17 मार्च 2021 संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर के प्रस्ताव पर आदिवासी विशेष केंद्रीय सहायता राशि 8 करोड़ 42 लाख रुपए का उपयोग और प्रशिक्षण संबंधी प्रशासकीय अनुमोदन किया है यह अनुमोदन अवैधानिक है।

कांग्रेस के इस आरोप पर विभागीय अधिकारियों के मना करने के बाद भी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करोड़ों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के सरताज के पीछे मंत्री को नीचे देखना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि मंत्री अधिकारियों के मना करने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुए। हालांकि मंत्री ने भी दम भरा कि मुझ पर और मेरे विभाग पर जो आरोप लगाए हैं मैं उनका खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में लीगल एक्शन लूंगा। लीगल एक्शन के लिए एक्सपर्ट से बात करके आगे बताऊंगा। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

● **जितेंद्र तिवारी**

कथा पॉलिटिक्स का अखाड़ा

मप्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। दावेदार क्षेत्र में लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए नित-नए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बार मिशन 2023 में टिकट के दावेदार मतदाताओं को आकर्षित करने और अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। प्रदेशभर में नेता अपने-अपने क्षेत्र में धार्मिक कथा करा रहे हैं। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा के सिमरिया में 5 से 7 अगस्त तक कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की हनुमान कथा करवाने जा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता के वर्तमान समय में संभवत: यह पहला अवसर है जबकि कोई कांग्रेसी नेता उनके मुखारविंद से होने वाली हनुमत कथा का मुख्य यजमान बनेगा।

चूंकि धीरेंद्र शास्त्री व्यासपीठ से हर बार हिंदू राष्ट्र और सनातन के वैभव की हुंकार भरते हैं अत: यह आश्चर्यजनक है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को सिरे से नकारने वाली कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख वरिष्ठ नेता उनकी कथा करवाने जा रहा है। क्या यह कमलनाथ का अपनी पार्टी के हिंदू राष्ट्र के स्टैंड से पृथक आयोजन है अथवा कमलनाथ के बहाने कांग्रेस मप्र में हिंदुत्व की राजनीति करके भाजपा के हिंदुत्व को चुनौती देना चाहती है? हाल के वर्षों में प्रदेश के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग हो अथवा पुजारियों को सरकारी मानदेय का प्रश्न या मंदिरों की दुर्दशा से लेकर हाल ही में लोकार्पित महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मामला, भाजपा सरकार को कमलनाथ ने घेरा है और इसमें उन्हें जनता का साथ भी मिला है। फिर सरकार भी कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दों से विमुख हुई है जिसका लाभ कमलनाथ ने उठाया है। ऐसे में कमलनाथ द्वारा धीरेंद्र शास्त्री की हनुमत कथा करवाना यह संदेश देता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब कांग्रेस भी भाजपा के साथ तू डाल-डाल, मैं पात-पात का खेल खेलेगी।

हालांकि भाजपा के नेता कमलनाथ के हिंदुत्व को नकली हिंदुत्व बताते रहे हैं, किंतु उनके कई ऐसे निर्णय हैं जिनसे यह साबित होता है कि कमलनाथ ने अपनी पार्टी के मत से हटकर हिंदुत्व के पक्ष में काम तो किया है। एक कांग्रेसी नेता के हवाले से यह पता चला है कि कमलनाथ प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवाने वाले हैं। इसके अलावा कई विधानसभा क्षेत्रों में भागवत कथा और शिव महापुराण की कथा का आयोजन भी होगा। इस वर्ष 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर कमलनाथ के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ के सार्वजनिक आयोजन आयोजित करवाए थे। वहीं पिछले वर्ष महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को कमलनाथ ने भोपाल के मिंटो हॉल में हनुमान चालीसा के सवा करोड़ जाप करवाए थे।

कमलनाथ संभवत: इकलौते कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में दिए गए फैसले के बाद प्रसन्नता व्यक्त की। जिस दिन फैसला आया उस दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय दीयों से रोशन था और कमलनाथ के निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अपनी ओर से 11 चांदी की ईंटें दान दी थीं। इससे पूर्व अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कमलनाथ ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर और ओंकारेश्वर में मंदिरों का विकास, राम वनगमन पथ बनाने का मंत्रिमंडल का प्रस्ताव और सर्किट की स्थापना आदि कार्य करके हिंदुओं के एक बड़े वर्ग में अपनी छवि बनाई थी।

मप्र में कथा-सत्संग के माध्यम से चुनाव जीतने का दांव पुराना है जिसका सर्वाधिक लाभ भाजपा के नेताओं ने उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती स्वयं कथावाचक रह चुकी हैं और उनके राजनीति में प्रवेश से पूर्व नेता अपने क्षेत्र में उनकी कथा करवाकर चुनाव जीतने का उपक्रम करते रहे हैं। कोरोना कालखंड में प्रदेश में कई कथावाचकों का उभार हुआ जिन्हें राजनीतिक सफेदपोशों ने स्थापित कर दिया। ये कथावाचक अब क्षेत्रवार राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रतिनिधि हो चुके हैं जो प्रदेश की 150 से अधिक विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखते हैं। बुंदेलखंड में धीरेंद्र शास्त्री, मध्य क्षेत्र और मालवा में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा, ग्वालियर-चंबल संभाग में पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा का बोलबाला है। जया किशोरी की भी प्रदेश में बड़ी मांग है। बीते 9 माह में विभिन्न कथावाचकों द्वारा 500 से अधिक कथाएं प्रदेशभर में हो चुकी हैं जिनमें से अधिकांश के यजमान राजनीतिक दलों के नेता थे। पिछले वर्ष संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भी कथा पॉलिटिक्स का फॉर्मूला सफल रहा था और यही कारण है कि मप्र में इस बार जमकर कथाओं के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

रुद्राक्ष के सहारे घर-घर पहुंच रहे नेता

कभी राम के सहारे अपनी राजनीतिक वैतरणी पार करने वाली भाजपा के बाद अब कांग्रेस के नेता भी धर्म की राजनीति में उत्तर आए हैं। दावेदारों के साथ-साथ वर्तमान विधायक भी धार्मिक यात्राओं के बाद शिव के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार कराने में लग गए हैं। इंदौर की विधानसभा 1, 4 व 5 में रुद्राक्ष व शिवपुराण में नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसी के चलते घर-घर पंचमुखी रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इंदौर में इन दिनों 15 लाख से अधिक रुद्राक्ष पहुंच चुके हैं। वैसे तो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक पांच में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही उम्मीदवार फिलहाल तय नहीं हैं, लेकिन सांसद से विधायक का चुनाव लड़ चुके सत्यनारायण पटेल और देपालपुर से पूर्व विधायक व रेनेसां यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति स्वप्निल कोठारी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन दोनों ही ने जन-जन तक पहुंचने के लिए रुद्राक्ष वितरण और धार्मिक आयोजनों को माध्यम बनाया है। इसी तरह विधानसभा 4 में गौड़ परिवार की खिलाफत करने वालों में गंगा मिश्रा भी घर-घर रुद्राक्ष बांट रहे हैं, लोकेंद्र सिंह गौड़ और राजसिंह गौड़ भी शिव महापुराण करवा रहे हैं। विधानसभा दो में रमेश मेंदोला भी घर-घर रुद्राक्ष बांट रहे हैं। हर वार्ड में यह रुद्राक्ष वितरण का कार्य जारी है। विधानसभा 1 में विधायक संजय शुक्ला शुरू से ही सभी धर्मों के लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार वार्ड स्तर पर धार्मिक यात्राएं करवा रहे हैं। कथाओं के सहारे कभी भाजपा नेता अपनी धार्मिक उपस्थिति दर्ज कराते थे। शुक्ला भी इसी तर्ज पर बड़ी कथाएं करवा चुके हैं तो अब वे वार्ड स्तर पर पूरे सावन माह महारुद्राभिषेक करवा रहे हैं। उनके बैनर पोस्टर में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ प. प्रदीप मिश्रा भी नजर आ रहे हैं।

मप्र के महुए से अंग्रेज पिएंगे चाय

नशीली शराब से मदहोश बना देने वाले महुए से अब तरोताजगी, चुस्ती, फुर्ती लाने वाली ग्रीन टी यानी चाय भी बन रही है। यह चाय हिंदुस्तान ही नही इंगलिस्तान यानि इंग्लैंड तक धूम मचा रही है। मप्र के बैतूल समेत 9 जिलों से इसके लिए इंग्लैंड महुआ भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, हाई फूड क्वालिटी का यह महुआ बैतूल के जंगलों से आदिवासियों के हाथों चुनवाया जा रहा है। अपनी ठंडी आबो हवा में अंग्रेज इस महुए से बनी चाय का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।

आमतौर पर आदिवासी महुआ को सड़ाकर उसकी शराब बनाते हैं। जिसे शादी, तीज त्यौहारों में उपयोग किया जाता है। कई इलाकों में यह अवैध रूप से बेची भी जाती है। लेकिन अब इस महुआ के नए उपयोग ने इसके बेहतर इस्तेमाल के विकल्प खोल दिए हैं। सबसे ज्यादा सुखद यह है कि जिस महुए की कीमत आदिवासियों को बाजार में 30 से 35 रुपए किलो मिल रही है, इस ग्रीन टी वाले कॉन्सेप्ट के बाद वह बढ़कर तीन गुना ज्यादा यानि 110 रुपए किलो हो जाएगी। लंदन बेस्ड कंपनी ओ फॉरेस्ट इसे 110 रुपए किलो खरीद रही है। जानकार बताते हैं कि बैतूल से लंदन भेजा जा रहा महुआ पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। इसकी गुणवत्ता और तादाद अन्य जिलों से ज्यादा है। यही वजह है कि यहां से 100 टन महुआ भेजे जाने का अंग्रेज कंपनी ने अनुबंध किया है।

बैतूल जिले के दक्षिण वन मंडल में वन विभाग ने 1250 महुए के पेड़ों का चयन किया है। इनकी जीपीएस लोकेशन लेकर इन पेड़ों को 71 हितग्राहियों में बांट दिया गया है। ये पेड़ कुछ तो जंगली क्षेत्र में है तो कुछ पेड़ आदिवासियों के खेतों में। वन विभाग इन्हीं 71 आदिवासियों से फिलहाल महुआ खरीद रहा है। इस साल इन लोगों से 1870 किलो महुआ खरीदा गया है। जिसकी इंग्लैंड की कंपनी ने बकायदा यहां पहुंचकर टेस्टिंग भी की है। टेस्टिंग के लिहाज से यह बहुत बेहतर ग्रेड का पाया गया है। वन विभाग ने सभी हितग्राहियों को हरी नेट उपलब्ध कराई है। इस नेट को महुआ के पेड़ के नीचे फैलाकर बांध दिया जाता है। इस नेट में गिरने वाले महुआ को आदिवासी प्रतिदिन इकट्ठा करते हैं। नेट पर एकत्रित होने के कारण इस पर न तो धूल लगती है और न ही यह खराब होता है। एक पेड़ से हर हितग्राही 80 से 100 किलो महुआ एकत्रित करता है। अच्छे सीजन में यह और भी अधिक मात्रा में मिल जाता है। एकत्रित किए जाने वाले इस महुआ को प्लास्टिक सीट पर रखकर उस पर एक अन्य सीट रखकर सुखा लिया जाता है। करीब एक सप्ताह सुखाने के बाद इसे प्लास्टिक बैग्स में पैक कर दिया जाता है।

महुए से लड्डू भी बनता है

महुए से लड्डू भी बनाए जाते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले महुआ को पानी में फुलाया जाता है। इसके बाद उसे सुखाकर घी में तला जाता है। महुआ में तीसी, ड्राई फूड, सौंप, तले ईलायची व गुड़ मिलाकर ओखली में कूटा जाता है। इसके बाद लड्डू बनाया जाता है। खुद डॉक्टरों ने भी माना कि महुआ लड्डू गर्भवती महिलाओं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रामबाण हो सकती है। वहीं अब महुआ से चाय की खोज करने से अब इस चाय को भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रजिया शेख ने बताया कि देशभर में ग्रीन टी मशहूर है। इसके अलावा अदरक और कई तरह की चाय का भी लोग लुफ्त उठाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने महुआ से चाय बनाने की विधि सीखी और इसे तैयार किया। उन्होंने बताया कि उनका पूरा स्टाफ महुआ से बनी चाय ही पीता है। रजिया शेख ने बताया कि महुआ से बनी चाय में कोई नशा नहीं होता है। महुआ फल को पेड़ से तोड़ने के बाद इसे सुखाया जाता है और फिर धोया जाता है, जिसके बाद इससे चाय तैयार की जाती है। उन्होंने दावा किया कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। बैली फैट के लिए भी यह फायदेमंद हो सकती है। लघु वनोपज संघ के मुताबिक, महुआ से अलग-अलग प्रोडक्ट तैयार करने को लेकर यूरोप के कई देशों की कंपनियां रिसर्च कर रही हैं। धीरे-धीरे इससे बनी चाय वहां फेमस हो रही है। अभी ग्रामीण अंचलों में इसके लड्डू तैयार किए जाते हैं तो वन धन केंद्र कुकीज और बिस्किट तैयार कर रहा है।

बैतूल से संकलित किया गया यह महुआ मंडला भेजा जा रहा है। जहां अन्य 9 जिलों से भी महुआ भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, प्रदेश के हरदा, नर्मदापुरम, सीधी, उमरिया, अलीराजपुर, मंडला भी इकट्ठा कर यह महुआ इंग्लैंड के लिए भेजा जा रहा है। जहां से यह छत्तीसगढ़ के जरिए ओ फॉरेस्ट कंपनी को सौंप दिया जाएगा। जो इसे इंग्लैंड भेजेगी। खास बात यह है कि इस महुआ का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी किया गया है। इसके लिए भोपाल में आयोजित वन मेले में कंपनी से अनुबंध किया गया था। दक्षिण वन मंडल के डीएफओ विजयनानतम टीआर बताते हैं कि ग्रीन टी के इस कॉन्सेप्ट से महुए की अच्छी कीमत मिलेगी। जो आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने में मील का पत्थर साबित होगा। यहां मिलने वाले फूड ग्रेड महुए की कीमत कंपनी से 110 रुपए किलो मिल रही है। जिसमें से परिवहन, संकलन के खर्चे काटकर आदिवासियों को 94 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाएगा। जबकि अब तक उन्हें महज 30 रुपए किलो बाजार से मिल रहा था। आने वाले समय में इससे बिस्किट बनने की भी योजना है। जिसकी डिमांड आने पर महुए की मांग बढ़ जाएगी।

बस्तर में रहने वाली रजिया शेख ने इससे महुआ टी बनाया और जगदलपुर शहर में महुआ टी का स्टॉल लगाया था। रजिया शेख ने बताया कि बस्तर में जगदलपुर शहर और अन्य जिलों में भी महुआ टी के छोटे-छोटे स्टॉल लगाए गए हैं। जहां लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं ऑनलाइन भी महुआ टी उपलब्ध होगी। जिससे आसानी से भारत के साथ ही विदेशों में रहने वाले लोग भी महुआ टी का लुफ्त उठा सकेंगे। महुआ टी पेपर पैकेट में पैक कर दिया जा रहा है। किसी तरह के प्लास्टिक का यूज नहीं किया जा रहा है और 100 ग्राम की महुआ टी की चाय की कीमत 60 रुपए रखी गई है और एक पैकेट से 7 से 8 बार चाय बनाई जा सकती है।

सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद महुआ से चाय तैयार की जा रही है। जिसको अच्छा रिस्पॉन्स भी स्थानीय लोगों के साथ दूर दराज से बस्तर घूमने आने वाले पर्यटक दे रहे हैं। दरअसल, ठंड के मौसम में इस महुआ टी का स्वाद चखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। महुआ लड्डू के बाद महुआ टी इन दिनों बस्तर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए भी पसंद बनी हुई है। इस चाय की चुस्की के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। रजिया शेख ने बताया कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में महुआ टी स्टॉल उपलब्ध हो इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

चीतों के सामने भोजन का भी संकट

पार्क की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में

कूनो को बब्बर शेर (एशियाटिक लायन) के लिए तैयार किया गया था। वर्ष 2013 में चीतलों का घनत्व 61 चीतल प्रति वर्ग किमी था, जो अब 18 रह गया है। प्रकाश वर्मा वर्ष 2020 से पार्क में पदस्थ हैं। इस अवधि में पार्क में शिकार के कई मामले सामने आए हैं। यहां तक कि चीते आने से पहले चीता बाड़े के नजदीक एक तेंदुए का शिकार हो गया था। 7 अप्रैल 2023 को पार्क में लगे ट्रैप कैमरे ने एक तेंदुए की फोटो ली है, जिसमें उसके गले में फंदा है। 15 अप्रैल 2023 को एक हायना के गले में भी फंदा फंसा होने की फोटो कैमरों ने खींची है। 29 अप्रैल को पार्क के कोर क्षेत्र से आलम मोंगिया नाम का व्यक्ति पकड़ाया था, जिसके पास से देशी कट्टा और जमीन में गड्ढा खोदकर छिपाई गई बंदूक जब्त हुई थी।

कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत की वजह अकेली कॉलर आईडी नहीं है। वहां चीतों के सामने प्रे-बेस (भोजन) का भी संकट है, जो भविष्य में बढ़ेगा। इसकी पुष्टि भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने भी की है। जनवरी 2023 में पार्क में कराई गई वन्यप्राणियों की गिनती में चीतों का मुख्य भोजन चीतलों की संख्या प्रति वर्ग किमी 18 निकली, जबकि 2021 में यह प्रति वर्ग किमी 23 और 2013 में 61 थी। 10 वर्ष में एक तिहाई संख्या कम होना इसका प्रमाण है कि पार्क में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जंगल से चीतलों के गायब होने का मुख्य कारण शिकार है, जिसके प्रमाण भी मिले। इसी मामले में डीएफओ प्रकाश वर्मा को 23 फरवरी 2023 को हटाया गया था। यह तबादला आदेश साढ़े तीन माह बाद निरस्त किया है।

खुले जंगल में छोड़े गए चीते दूर-दूर भाग नहीं रहे थे, बल्कि भोजन के लिए संघर्ष कर रहे थे। पार्क में जब चीतल नहीं मिले, तो वे पार्क से 200 किमी दूर उप्र की सीमा में भी पहुंच गए। सामान्य तौर पर चीतों का वजन 50-60 किलो होता है पर गर्दन में घाव और उसमें संक्रमण के कारण 11 जुलाई को मृत पाए गए चीते तेजस के शव का वजन केवल 43 किलो निकला। जानकारों ने भी माना कि उसे खाना नहीं मिला। वन्यजीव संस्थान ने ऐसे ही प्रमाणों के साथ चीता निगरानी समिति और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अधिकारियों को पार्क में प्रे-बेस के संकट पर चेताया था। यह भी कहा था कि इस दिशा में तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में पार्क में पानी की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए गए थे। उधर, प्रकाश वर्मा को रिलीव न करने से पूर्व मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक जेएस चौहान भी नाराज थे। क्योंकि दिल्ली के अधिकारियों से रिश्ते अच्छे होने के कारण वर्मा उनके निर्देश नहीं मान रहे थे। चौहान ने उन्हें रिलीव कराने के लिए शासन को पत्र लिखा था और 3 जुलाई को दिल्ली में हुई बैठक में जब पार्क प्रबंधन की बात आई, तो चौहान ने माइक्रो लेवल पर जाकर दिल्ली से प्रबंधन की बात कह दी। यही अधिकारियों को नागवार गुजरी और उनको हटा दिया गया।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को केंद्र सरकार से अधिक मौतों को रोकने के लिए शेष चीतों को अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस बी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि इतने कम समय में चीतों की मौत चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। साथ ही शीर्ष अदालत ने उस वातावरण की उपयुक्तता पर भी चिंता जताई है जहां इन चीतों को स्थानांतरित किया गया है। कोर्ट ने चीतों को राजस्थान स्थानांतरित करने की सिफारिश करते हुए कहा कि केंद्र इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने के बजाय इस पर उचित कार्रवाई करे।

गौरतलब है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत केंद्र सरकार नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को भारत में फिर से बसाने के उद्देश्य से लाई थी। हालांकि पिछले चार महीनों में भारत में जन्मे तीन शावकों सहित आठ चीतों की अलग-अलग घटनाओं में बीमारियों के चलते मौत हो गई है। इनमें से दो चीतों की मौत पिछले सप्ताह ही हुई है। जस्टिस गवई ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले सप्ताह दो और मौतें। यह प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनता जा रहा है? कृपया कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने, पूछा की सभी चीतों को फैलाने के बजाय एक ही स्थान पर क्यों रखा गया? एक साल से भी कम समय में होने वाली 40 फीसदी मौतें कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं करतीं। इसके साथ ही न्यायाधीश गवई ने केंद्र से चीतों को राजस्थान के जवाई राष्ट्रीय उद्यान में भेजने पर भी विचार करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि राजस्थान के अभयारण्यों में से एक (जवाई राष्ट्रीय उद्यान) तेंदुओं के लिए बेहद प्रसिद्ध है। जो उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर है। उन्होंने उल्लेख किया कि वहां का परिदृश्य बेहद अच्छा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इसे सकारात्मक नजरिए से देखते हुए वहां चीतों के लिए एक और अभयारण्य बनाने का सुझाव केंद्र को दिया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रतिष्ठित चीता स्थानांतरण परियोजना के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। भाटी ने कहा कि परियोजना ने इस प्रक्रिया के दौरान 50 फीसदी मौतों का अनुमान लगाया था। जस्टिस पारदीवाला ने चीतों की मौत से जुड़े कारणों के बारे में पूछताछ करते हुए सवाल किया कि मौतें क्यों हो रही हैं, क्या ये जंगली बिल्लियां हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं हैं। या भारत की जलवायु उनके लिए अनुपयुक्त है? क्यों वे गुर्दे या श्वसन प्रणाली से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं। ऐसे में अदालत ने केंद्र से एक अगस्त 2023 को होने वाली अगली सुनवाई पर सुझावों के साथ, परियोजना की स्थिति पर अपडेट देने के लिए कहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने बहाली की इस परियोजना की देखरेख और इस मामले में सलाह देने के लिए एक चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया था। 17 जुलाई, 2023 को प्रसिद्ध चीता विशेषज्ञ विंसेंट वैन डेर मेरवे ने इस बारे में अपने अवलोकन और परिप्रेक्ष्य साझा किए थे। विशेषज्ञ ने पैनल को समझाया कि भारत में चीतों की आबादी स्थिर होने से पहले हमें कम से कम 50 संस्थापक चीतों की आवश्यकता होगी। उसके बाद चीतों के अस्तित्व और आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित करने के लिए, हमें दक्षिणी अफ्रीकी और भारतीय आबादी के बीच चीतों का आदान-प्रदान करना होगा।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

जगमगाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे

देश के सबसे पिछड़े और गरीब क्षेत्र में शामिल बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने लगी है। इसी क्रम में अब बुंदेलखंड हाईवे को सोलर लाइट से रोशन करने की योजना तैयार की गई है।

उप्र के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे पर सरकार एक नई शुरुआत करने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को उप्र सरकार अब सोलर एक्सप्रेस-वे बनाने जा रही है। एक्सप्रेस-वे पर सोलर पैनल के जरिए रोशनी के साथ-साथ एक्सप्रेस-वे से सटे आसपास के गांव भी जगमगाएंगे। यूपीडा ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सौर ऊर्जा से लैस करने की तैयारी कर रहा है। यूपीडा की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का लेटर जारी कर दिया गया है। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत वृहद स्तर पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के जरिए इस पूरे एक्सप्रेस-वे को सौर ऊर्जा से लैस करने की अनूठी पहल की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, लगभग 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सौर ऊर्जा चलित एक्सप्रेस-वे के तौर पर विकसित करने की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके लिए यूपीडा की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का लेटर जारी कर कंपनियों के आवेदन मांगे गए हैं। इसके अंतर्गत सोलर पैनल को एंपैनल करने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन और सुझाव मांगे गए हैं। यूपीडा ने इसके लिए 17 अगस्त दोपहर 3:00 बजे तक कंपनियों से आवेदन मांगे हैं।

सोलर पैनल लगाने वाली कंपनियों का आवेदन मिलने के बाद आगे इनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि 4 लेन वाले इस 296 किलोमीटर लंबे हाईवे में कैरेज-वे और सर्विस लेन के तौर पर दो हिस्से हैं। इन्हीं दोनों के बीच लगभग 15 से 20 मीटर चौड़ाई की पट्टी वाला क्षेत्रफल पूरे एक्सप्रेस-वे में खाली है। अब इसी क्षेत्र को सोलर पैनल से पाटने की योजना है, जिससे पूरा एक्सप्रेस-वे सौर ऊर्जा से लैस होगा।

दरअसल, बुंदेलखंड में बिजनेस सिटी स्थापित करने की घोषणा के बाद एक्सप्रेस-वे पर अब सोलर मेगा प्लांट तैयार किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की पहचान सौर ऊर्जा के रूप में होगी। यूपीडा के मुताबिक, सीईओ के निर्देश पर 296 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सौर ऊर्जा चालित एक्सप्रेस-वे के तौर पर विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर सोलर पैनल्स को इंपैनल करने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन व सुझाव मांगे हैं। उप्र सरकार सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रही है। इसको लेकर प्रदेशभर में कई जगहों पर बड़े-बड़े सौर ऊर्जा के मेगा प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं अब सौर ऊर्जा के जरिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को रोशन करने की दिशा में योगी सरकार प्रयास कर रही है। 4 लेन वाले एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ सोलर पैनल्स लगाने दिशा में काम किया जाएगा। यूपीडा ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट का लेटर जारी किया है। इसके अनुसार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सोलर एक्सप्रेस-वे में परिवर्तित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पूरी योजना का पीपीपी मॉडल के अंतर्गत सोलर पैनल इंप्लांटेशन किया जाएगा।

उप्र बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के साथ ही औद्योगिक गलियारों और हाईवे के रखरखाव पर योगी सरकार जोर दे रही है। अब नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। इस महामार्ग का पूरा संचालन सोलर पॉवर से किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर उप्र एक्सप्रेस-वे औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) काम कर रही है। ऐसा देश में पहली बार होने जा रहा है, जब इतने बड़े एक्सप्रेस-वे का संचालन सोलर पॉवर से होगा। उप्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि उच्च गुणवत्ता वाले हाईवे और एक्सप्रेस-वे के निर्माण व रखरखाव दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही इसे नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ते हुए एक खास इनोवेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सौर ऊर्जा से लैस करने की अनूठी पहल को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

गांव भी होंगे रोशन!

बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर भी कई जगह सौर ऊर्जा के पैनल लगाए गए हैं लेकिन इन पैनल से बनने वाली सोलर एनर्जी टोल प्लाजा व कुछ इलाके को ही रोशनी दे पाती है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के पूरे 296 किलोमीटर के रास्ते को ही सोलर एनर्जी से जगमगाने की योजना है। यूपीडा के एसीईओ हरिनाथ शाही का कहना है कि ये अभी शुरुआत है। अगर कार्य योजना ने ठीक ढंग से कम किया और पीपीपी मॉडल पर यह योजना कारगर रही तो एक्सप्रेस-वे पर लगे सोलर पैनल से हम अतिरिक्त बिजली भी बना सकेंगे, जिसको भविष्य में पास के पॉवर ग्रिड से जोड़कर बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से सटे गांवों को भी रोशन करने की कोशिश होगी। यूपीडा की ओर से बताया गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर 15-20 मीटर चौड़ाई वाली पट्टी सोलर पार्क के तौर पर विकसित की जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे उप्र के सबसे आधुनिक और सुविधा संपन्न एक्सप्रेस-वे में शुमार है। उल्लेखनीय है कि 4 लेन वाले इस 296 किमी लंबे हाईवे में मेन कैरियज-वे और सर्विस लेन के रूप में दो हिस्से हैं। इन्हीं दोनों के बीच लगभग 15-20 मीटर चौड़ाई की पट्टी है, यह खाली है, जिसे कृषि भूमि से अलग करने और बाड़ लगाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी क्षेत्र को सोलर पैनल्स से पाटने की योजना है। इससे पूरा एक्सप्रेस-वे सौर ऊर्जा से लैस हो जाएगा।

डिजिटल सूदखोरों का ऋणजाल

पिछले साल जुलाई 2022 में भोपाल में एक नौजवान निशंक राठौर की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में था। वह रेल की पटरी पर मरा हुआ पाया गया और उसके पिता के मोबाइल पर ठीक उसी समय ऐसा मैसेज आया जिससे लगता था कि उसे नबी से गुस्ताखी की सजा दी गई है। हालांकि पुलिस ने जांच की तो कुछ और ही कहानी सामने आई। जांच में पुलिस को पता चला कि निशंक ने कई लोन एप्स से लोन लेकर क्रिप्टो करंसी में निवेश किया था। वह पूरी तरह से लोन एप्स के जाल में फंस चुका था और संभवत: इसी जाल से निकलने के लिए उसने आत्महत्या का रास्ता चुना तथा अपनी आत्महत्या का कारण छिपाने के लिए घरवालों को भी गुमराह किया।

ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां लोन एप्स के जरिए लिए गए ऋण न चुका पाने पर लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपनी जीवनलीला ही समाप्त कर देते हैं। अभी जब यह लेख लिखा जा रहा है उस समय हैदराबाद में एक युवक नरेश लोन एप के चलते अपनी जीवनलीला समाप्त कर चुका है। मीडिया के अनुसार करीमनगर का रहने वाला नरेश एक वर्ष पहले नौकरी के लिए हैदराबाद आया था और अरबीनगर में लकी डीलक्स बॉयज हॉस्टल में रह रहा था। उसके पास एक दिन प्राइवेट लोन एप से मैसेज आता है और फिर वह उस एप से लोन ले लेता है। वह लगातार उसकी किश्तें चुका रहा होता है। मगर लोन एप के कर्मियों ने उससे कहा कि उन्हें सारा पैसा एक साथ चाहिए जिसके बाद वह अवसादग्रस्त हो गया और उसने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस का कहना है कि युवा लोन लेने से बचें। परंतु कोई भी युवा लोन के चक्कर से कैसे बच सकता है जब अपनी इच्छाओं की तुरंत पूर्ति करने के लिए लोन लेने को ही समझदारी बताया जा रहा हो। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है तो क्रेडिट कार्ड बिल पर ईएमआई, घर खरीदना है तो होम लोन, या फिर घूमने जाना है तो पर्सनल लोन। मनपसंद वाहन चाहिए तो व्हीकल लोन! आपकी कोई भी इच्छा है जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो बाजार आपके लिए लोन का टोकरा लेकर खड़ा है। कर्ज लेकर खर्च करो के सिद्धांत का प्रचार लोगों को इतना प्रभावित कर चुका है कि लोग अपने आप ही फंसने चले आते हैं। लोन एप्स वालों को बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। आपको करना ही क्या है, बस कुछ डिटेल्स देनी हैं और मिल गया कर्ज।

डिजिटल एप से ऋण कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से ले सकता है। बहुत ही आकर्षक विज्ञापन लोन को लेकर दिन भर नेट पर आते हैं कि एक क्लिक में लोन मिल जाएगा। लोन तो आकर्षक शर्तों पर दे दिया जाता है, परंतु उसे चुकाया कैसे जाएगा? इस यक्ष प्रश्न पर बात नहीं होती। तब तक इस पूरी प्रक्रिया पर बात नहीं होती तब तक जो भी आत्महत्याएं हो रही हैं, वह आत्महत्याएं ही कहलाती रहेंगी। जबकि वह हत्याएं हैं। वह उन सपनों के जाल में फंसाकर की जाने वाली हत्याएं हैं, जिसमें लोन के माध्यम से क्षणिक खुशियों को पूरा करना तो सम्मिलित होता है, परंतु उन क्षणिक खुशियों को पूरा करने के पीछे जो अंधकारपूर्ण यथार्थ है, उसे दबा दिया जाता है। सारा जोर यहां पर आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का है। निरर्थक आवश्यकताओं को प्राथमिकता समझकर व्यक्ति इस प्रकार फंसता है कि वह बाहर निकल ही नहीं पाता। जैसा भोपाल के उस परिवार के साथ हुआ था जिसने थोड़े से लालच में अपनी खुशहाल जिंदगी को तबाह कर दिया। वह व्यक्ति अच्छी खासी नौकरी करके अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, मगर थोड़े से पैसों और जरूरतों के चलते वह ऑनलाइन एक्स्ट्रा वर्क और उसके बाद लोन के जाल में फंस गया और जब उसके अनुसार कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पत्नी और दोनों बच्चों के साथ 12 जुलाई 2023 को आत्महत्या कर ली थी! उसने अपने सुसाइड नोट में अपने तमाम परिजनों से क्षमा मांगी थी। एक दौर में साहूकारों के खिलाफ सामाजिक और बौद्धिक अभियान खूब चला। उन्हें शोषक बताया गया और उनकी जगह बैंकिंग सिस्टम को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया गया जहां सब कुछ तय मानक पर होता है। लेकिन आज जिस तरह से डिजिटल साहूकार पैदा हो गए हैं, उनका लोन वसूलने का तरीका इतना भयावह है कि उसके सामने मदर इंडिया के सुक्खी लाला की काल्पनिक कहानी भी कम डरावनी लगेगी।

● **बृजेश साहू**

तत्काल दे देते हैं ऋण डिजिटल एप्स

बेरोजगार या कम आय वाले लोगों को जहां बैंक से ऋण मिलना कठिन होता है और तमाम औपचारिकताएं होती हैं, वहीं डिजिटल एप्स चुटकी बजाते ही व्यक्ति को ऋण प्रदान कर देते हैं। चूंकि उसको ब्याज के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया जाता इसलिए जब वह ऋण चुकाना आरंभ करता है तो उसे पता चलता है कि वह तो वर्षों के लिए एक बंधुआ मजदूर बन गया। वह जो कमा रहा है वह इन्हीं के लिए कमा रहा है और जब वह एक दिन इनके लिए नहीं कमा पाता तो यह लोग वसूली एजेंट ही नहीं भेजते हैं बल्कि उसके फोन से चुराई गई निजी तस्वीरें और वीडियो भी मोर्फ करके उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देते हैं। ऋण लेने वालों के रिश्तेदारों को कॉल करने लगते हैं और उन्हें गालियां देने लगते हैं कि तुम्हारे एक परिचित ने लोन का पैसा नहीं लौटाया है। एक किस्सा खोजने जाएं तो कई किस्से सामने आते हैं, परंतु कोई भी आज इन डिजिटल लुटेरों और इंस्टेंट लोन की इस चकाचौंध के विषय में बात नहीं कर रहा। कोई भी इन एप्स को या फिर उस व्यवस्था को जिसमें ऋण न चुकाए जाने पर बैंक द्वारा भी जब समय नहीं दिया जाता तो प्रणाली को दोषी नहीं ठहराता। जैसे हाल में ही केरल में एक मां-बेटी ने बैंक लोन के तगादे के कारण आत्महत्या कर ली। ऐसे डिजिटल लुटेरों की संगठित डकैती की चपेट में जो लोग आ रहे हैं वह या तो मध्यवर्ग के लोग हैं या फिर वे गरीब लोग जिन्हें कुछ हजार रुपए तक की आवश्यकता होती है। गरीबों की आवाज उठाने का दावा करने वाले वो लोग ऐसे शोषण से लगातार होती आत्महत्याओं पर शांत हैं जिन्होनें एक दौर में ऐसी सूदखोरी के खिलाफ सामाजिक माहौल खड़ा कर साहूकारों को खलनायक घोषित कर दिया था। लेकिन आज लोन वसूली के नाम पर डिजिटल एप्स लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं तो कोई इसे सामाजिक विमर्श का मुद्दा क्यों नहीं बनाता?

मेट्रो ने पकड़ी रफ्तार

ट्रायल रन को लेकर काउंटडाउन शुरू

इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में इस साल सितंबर में ट्रायल रन किया जाना है। इंदौर में सुपर कारिडोर के 5.9 किलोमीटर के हिस्से में यह ट्रायल रन होना है। इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि भले ही हमने समय सीमा सितंबर तय की है, लेकिन हम इसे अगस्त मान कर चल रहे हैं। इसी के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मोकअप कोच में असली कोच की तरह कुर्सियां, हत्थे, स्क्रीन आदि लगी होगी। इसका फर्श, रंग, आकार एकदम असली कोच जैसा ही होगा।

भोपाल और इंदौर में सितंबर 2023 से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करना है। इसके लिए मेट्रो कंपनी ने निर्माण कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। 24 घंटे काम चल रहा है। ट्रायल रन के लिए 25 से 30 अगस्त के बीच मेट्रो ट्रेन का पहला रैक इंदौर पहुंचेगा, जबकि भोपाल के लिए 10 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुभाष नगर तक 4.4 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल रन होना है। इसके लिए रेलवे ट्रैक और मेट्रो के स्टेशन बनाने का काम तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार इस रूट पर सिविल वर्क 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। फिलहाल स्टेशन के अंदर लिफ्ट लगाने और बिजली से संबंधित कामों को पूरा किया जा रहा है। अंदर से सिविल वर्क पूरा हो चुका है। केवल बारीक काम शेष है। अगस्त के अंत तक इस रूट के सभी स्टेशनों व रूट का सिविल वर्क और पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

सितंबर 2023 से शुरू होने वाला ट्रायल रन तीन माह तक चलेगा। जनवरी 2024 में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त इस मार्ग को परखेंगे। उनके संतुष्ट होने के बाद प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो संचालन की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अगले साल मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर पर दौड़ सकती है। अधिकारियों ने बताया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर में केवल रेलवे ट्रैक व स्टेशन का काम बाकी है। कॉरिडोर में आने और जाने के लिए 8.8 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया जाना है। इसमें 4.2 किलोमीटर ट्रैक बिछा लिया गया है। डीबी सिटी माल, केंद्रीय विद्यालय और रानी कमलापति स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन का काम अंतिम चरण में है।

मेट्रो ट्रेन कैसी होगी, इसकी जानकारी देने के लिए मेट्रो का मोकअप (मेट्रो की बोगी की प्रतिकृति) भोपाल आ चुका है। स्मार्ट पार्क में स्ट्रक्चर बनाकर इसे स्थापित किया गया है। साथ ही यहां तंबू लगा दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री से अनावरण के लिए तिथि नहीं मिलने की वजह से इसे शहरवासियों के लिए खोला नहीं गया। आम लोग माक अप या मेट्रो के डिब्बे में पहुंचकर टीवी, अलार्म, इलेक्ट्रिक कनेक्शन सहित अन्य चीजों का अवलोकन कर सकेंगे। डिब्बे में 50 लोगों के बैठने और 250 लोगों के खड़े होने का इंतजाम किया गया है। मप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी मनीष सिंह का कहना है कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री की मंशानुसार प्रायोरिटी कॉरिडोर में सितंबर से ट्रायल रन करना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं।

इंदौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 17.5 किमी के एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम कर रहा है। इसमें से 5.9 किमी के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सिविल वर्क पूरा हो चुका है। यह वही हिस्सा है, जहां सितंबर तक सरकार मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन करना चाहती है। 1200 से अधिक पियर्स पर खड़े एलिवेटेड कॉरिडोर का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। हालांकि छिटपुट कई काम बचे हैं। चूंकि अभी कमर्शियल उपयोग नहीं होगा, सिर्फ ट्रायल होगा, इसलिए साज-सज्जा पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्टेशनों की डिजाइन व ड्राइंग तैयार है, लेकिन मेट्रो के स्टेशनों को पूरी तरह तैयार होने में अभी वक्त लगेगा। सरकार ने सितंबर 2023 डेडलाइन तय की है। इसीलिए छुट्टी के दिन भी काम किया जा रहा है। श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि गांधीनगर से लेकर 5.9 किमी यानी टीसीएस चौराहे तक ट्रायल होगा। आमजन के लिए कमर्शियल उपयोग के लिए इसे अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। यानी मेट्रो में नियमित सफर करने के लिए लोगों को अगले साल तक इंतजार करना होगा। मेट्रो स्टेशन पर पीईबी स्ट्रक्चर को बनाने में अधिक समय लगना तय है। स्टेशन, क्रॉस रनर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, सीढ़ियां और लिफ्ट सहित कई काम बचे हैं। इंदौर में अभी पटरी बिछना बाकी है। 5.9 किमी में से 90 प्रतिशत पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। 5 स्टेशनों का काम चल रहा है। क्रॉस ओवर बनना है। वह काम अब शुरू होगा। क्रॉस ओवर में ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती है। वाया डक्ट का काम हो गया है। स्टेशन पर फ्लोरिंग का काम होना बाकी है। स्टेशनों की सीढ़ियां और लिफ्ट का काम शेष है। स्टेशन पर एंट्री व एग्जिट का काम चल रहा है। पीईबी स्ट्रक्चर का काम भी दो दिन में शुरू होगा। यह नीले रंग का स्ट्रक्चर है, जो स्टेशन के ऊपर छत की तरह होता है। इसी में सबसे ज्यादा समय लगेगा।

मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि मार्च माह में ही वड़ोदरा में एल्सटॉम कंपनी ने कोच का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह कंपनी भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए तीन कोच की 52 ट्रेन यानी 156 कोच की आपूर्ति करेगी। भोपाल मेट्रो के लिए 3 कोच की 27 ट्रेनें और इंदौर के लिए 3 कोच की 25 ट्रेनें आएंगी। कोच की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 2.9 मीटर है। यह ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 15 साल तक ट्रेन का मेंटेनेंस भी कंपनी करेगी। साथ ही अनुबंध में रोलिंग स्टाफ, सिग्नलिंग और दूरसंचार की आपूर्ति और स्थापना के लिए संयुक्त अनुबंध किया गया है। मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने दोनों शहरों के नागरिकों को मेट्रो ट्रेन से पहले से परिचित कराने के लिए मोकअप कोच की आपूर्ति करने के निर्देश दिए थे। यह अप्रैल माह के अंत तक मिलने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि कई शहरों में जहां मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहे थे, वहां इस तरह से मोकअप कोच लगाने की शुरुआत की गई थी। मोकअप कोच हूबहू असली कोच की तरह होते हैं। सरल भाषा में डमी कोच भी कह सकते हैं। इन्हें थोड़ी ऊंचाई पर एक प्लेटफार्म बनाकर स्थापित किया जाता है। वहां लोग इसमें सवार होकर इसे देख सकेंगे।

● **सुनील सिंह**

लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा है क्यों बरपा?

मानसून सत्र की एक ही उपलब्धि...
...बिन चर्चा बिल पास

विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में
कौन पास, कौन फेल?

संसद का 23 दिनी मानसून सत्र समाप्त हो गया। सबको उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के 8 महीने पहले होने वाले इस सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे, लेकिन तय समय तक चलने वाले इस सत्र में केवल हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। विपक्ष जहां वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या मणिपुर हिंसा पर धारा 176 के तहत चर्चा के लिए अड़ा रहा, वहीं सत्तापक्ष 267 पर चर्चा के लिए खड़ा रहा। इस कारण संसद केवल आखिरी तीन दिन ही चल पाया। वह भी विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने पर।

● राजेंद्र आगाल

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसलिए पूरा विश्व इसे एक आदर्श देश की तरह देखता है। लेकिन यहां लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में पिछले करीब एक दशक से जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, उससे हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिरकार लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा क्यों है बरपा? हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र में तो सारी हदें पार होती नजर आईं। मणिपुर हिंसा को लेकर पूरा विपक्ष सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार था। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर हिंसा को लेकर आरोपों की बौछार की, वहीं सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जमकर उनकी खिल्ली उड़ाई। जिसने भी संसद की यह कार्यवाही देखी उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा क्यों है बरपा?

5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और मणिपुर हिंसा के बीच संसद के मानसून सत्र से देश को बड़ी उम्मीद थी। लेकिन इस सत्र के दौरान केवल हंगामा ही होता रहा। इस सत्र की एकमात्र उपलब्धि यह रही कि सारे बिल बिना चर्चा के पारित हो गए। वहीं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में भले ही सत्तारूढ़ पार्टी फ्लोर पर जीत गई और विपक्षी हार गए, लेकिन असली हार तो जनता की हुई है। जिसके टैक्स के पैसे से माननीय हंसी-ठिठोली करते रहे।

अरबों रुपए स्वाहा

मानसून सत्र में किस पार्टी को क्या मिला, इस पर बात करने से पहले यह जान लें कि देश को क्या मिला। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर रोज हंगामे होते रहे। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर हिंसा पर बयान देने की मांग करता रहा और हंगामा होता रहा। बता दें कि 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन संसद की कार्यवाही हंगामे के चलते बाधित होती रही। इस दौरान भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट से ट्वीट कर खर्च का ब्यौरा जारी किया। भाजपा के अनुसार संसद की कार्यवाही पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए, हर घंटे में 1.5 करोड़ रुपए और हर दिन करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भाजपा का कहना है कि ये पैसा देश की जनता का है, जो हर दिन विपक्ष के हंगामे के कारण बर्बाद हुआ। वहीं विपक्ष इसके लिए सरकार को दोषी बताता रहा। मानसून सत्र की शुरूआत से ही विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा में मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की घटना पर केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाता रहा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस घटना पर बयान देने की भी मांग की, ऐसे में रोजाना सदन की कार्यवाही बाधित होती रही और लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्षों को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इससे जनता को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की रोटियां सिंकती रहीं। इससे जनता के टैक्स से मिले अरबों रुपए स्वाहा हो गए।

बिन चर्चा बिल पास

20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चले इस सत्र के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि मानसूत्र सत्र 23 दिनों तक चला, जिसमें कुल 17 बैठकें हुई हैं। इस दौरान लोकसभा में 20 बिल और राज्यसभा में 5 बिल पेश किए गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कुल 22 विधेयक पारित किए गए, जबकि राज्यसभा में 25 विधेयक। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली सेवा बिल समेत कुल 23 बिल पास किए गए हैं। बिल तो 23 पास हो गए लेकिन इन पर चर्चा में कितने मिनट खर्च किए गए यह अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड है। खबरों के अनुसार लोकसभा में 22 विधेयक पारित हुए, जिनमें से 20 पर एक घंटे से भी कम चर्चा हुई। 9 विधेयक तो लोकसभा में महज 20 मिनट के भीतर पारित हो गए। लोकसभा में सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधन विधेयक पारित होने में तो 2 मिनट भी नहीं लगे। राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाने का विधेयक महज 3 मिनट के भीतर लोकसभा में पारित हो गया। इस बीच मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा तो हुई लेकिन अंततः मणिपुर की पीड़ा अनसुनी ही रह गई। विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई के भी मुद्दे उठाता रहा लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। केवल और केवल इस सत्र में सरकार की ओर से कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमले ही होते रहे और उनके सवालों की खिल्ली उड़ाई गई।

गौरतलब है कि मणिपुर में कुकी और नगा समुदाय मैतेई समुदाय को जनजाति वर्ग का दर्जा देने का विरोध कर रहा है, यही कारण है कि मणिपुर हिंसा की चपेट में है। वहीं मानसून सत्र की शुरुआत से पूर्व दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का मामला सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया और विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। विपक्ष ने सदन में इस मामले में चर्चा की मांग की, हालांकि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई तो विपक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए अन्य मांगें शुरू कर दीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने की मांग की। इसके बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार ने विपक्ष को। यानी अविश्वास प्रस्ताव भी व्यर्थ गया। इस दौरान मणिपुर हिंसा का कोई समाधान नहीं निकला।

पूरे सत्र में मणिपुर मुद्दा गरमाया हुआ रहा, इसके साथ ही विपक्षी दलों ने कुछ दूसरे मुद्दों पर भी सदन में सरकार को घेरकर रखा। मानसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही बाधित रही। मानसून सत्र में मात्र 44 घंटे 13 मिनट ही कामकाज हुआ। सत्र में लोकसभा की कार्यवाही 46 फीसदी रही, निचले सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सत्रह बैठकें हुईं। सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, इस पर 19 घंटे 59 मिनट चर्चा हुई। चर्चा में 60 सदस्यों ने भाग लिया। स्पीकर ने कहा कि यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इस पर चर्चा 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को हुई। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पेश हुए और 22 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों में बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बताया गया कि सदन में नियम 377 के अधीन 361 प्रतिवेदन दिए गए। सत्र के दौरान 1209 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। उनके मुताबिक संसद की स्थाई समिति ने उन्हें 65 प्रतिवेदन दिए। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्य कार्य के संबंध में 4 जुलाई से शुरू हुआ था। सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्य कार्य के संबंध में 4 अगस्त को

राज्यसभा में 28 तो लोकसभा में 22 प्रतिशत हुआ कामकाज

संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में महज 28 फीसदी कामकाज हुआ है। सत्र के दौरान कुल 19 विधेयक राज्यसभा से पास किए गए हैं। ज्यादा वक्त संसद की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित रही। 17वीं लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई 2021 को शुरू हुई और इस दौरान 17 बैठकों में 28 घंटे 21 मिनट कामकाज हुआ। 76 घंटे 26 मिनट संसद में हुए हंगामे, विपक्ष के विरोध और अन्य बाधाओं की वजह से बाधित ही रहा। मौजूदा संसद सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। पेगासस जासूसी केस से लेकर महंगाई और किसान आंदोलन विपक्ष के प्रमुख मुद्दे रहे। विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से सदन का काम एक दिन भी निर्बाध रूप से चलता नजर नहीं आया। केंद्र सरकार ने विपक्ष पर हंगामा करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि विपक्ष संसद की कार्यवाही में लगातार रुकावट पैदा कर रहा है। संसद का काम अपेक्षा के अनुरूप होता नजर नहीं आया है। पहले राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त तक चलने वाली थी लेकिन 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। सत्र के दौरान कामकाज बीते पांच सत्रों की तुलना में बहुत कम था, जिसमें सदन ने 95 प्रतिशत काम किया था। हालांकि लोकसभा से बेहतर कामकाज राज्यसभा में हुआ है। लोकसभा में काम की जगह हंगामा खूब हुआ। हर दिन विपक्ष की नाराजगी सदन में साफ नजर आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन न चलने देने की वजह से पीड़ा जाहिर की। ओम बिरला ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद कहा कि लोकसभा के वेल में तख्तियां पकड़े सदस्य और नारेबाजी करना सदन की परंपरा नहीं है।

गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 134 विधेयक पेश किए गए। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि एक तरफ सत्तापक्ष और विपक्ष हंगामा करते रहे, आपस में लड़ते रहे, दूसरी तरफ सदन में बिल बिना चर्चा के पास होते रहे।

अपनी-अपनी ताकत का आंकलन

राजनीति के हर कदम के कुछ घोषित, तो कुछ अघोषित मकसद होते हैं। यह भी दिलचस्प है कि उसके घोषित मकसद से कहीं ज्यादा अघोषित और सांकेतिक मकसद महत्वपूर्ण होते हैं। विपक्ष द्वारा लोकसभा में पेश अविश्वास प्रस्ताव का घोषित मकसद मणिपुर के मामले को राष्ट्रीय नैरेटिव का हिस्सा बनाना रहा, लेकिन इसका अघोषित मकसद आगामी लोकसभा चुनाव का मुद्दा तय करना और उसके जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना था। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी बहिर्गमन के बाद ध्वनि मत से गिर चुका है और आगामी लोकसभा चुनाव तक के लिए मोदी सरकार की राह का कांटा दूर हो गया है। इसके बाद यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव अपने घोषित और अघोषित दोनों लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहा? इसमें दो राय नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव अपने घोषित मकसद में किंचित कामयाब रहा, लेकिन वह अपने सांकेतिक और अघोषित लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, एक तरह से कांग्रेस ने तश्तरी में सजाकर मोदी सरकार को अगले चुनाव के लिए अपना एजेंडा स्थापित करने और उसी के अनुरूप चुनाव अभियान चलाने की सहूलियत प्रदान कर दी है।

राहुल की सदस्यता बहाली का राजनीतिक असर कितना?

राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाना कांग्रेस के लिए किसी जंग के जीत लेने से कम नहीं है। संसद के बजट सेशन के दौरान ही 23 मार्च, 2023 को सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। संसद सदस्यता खत्म, लेकिन संसद के अगले ही सत्र यानी मानसून सेशन के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बदौलत अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं का उत्साह तो देखते ही बन रहा है, राहुल गांधी के चेहरे पर भी अंदर की खुशी की झलक नजर आ रही है। निश्चित रूप से इस पूरे वाकये का साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर भी असर होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी गठबंधन ये सब किस तरीके से देख रहा है? राहुल गांधी की सदस्यता चली जाने के बाद कांग्रेस नेताओं की सक्रियता तो बढ़ी हुई देखी जा सकती थी, लेकिन विपक्षी दलों पर सबसे बड़ी पार्टी होने का दबदबा हल्का पड़ने लगा था। बीच की अवधि में कांग्रेस की तरफ से उठाए गए कदम और फैसले इस बात की तस्दीक भी करते हैं। यूपीए के पीछे छूट जाने और इंडिया के रूप में विपक्षी दलों का गठबंधन सामने आने के पीछे एक बड़ी वजह राहुल गांधी के साथ हुई हाल फिलहाल की घटनाएं ही समझी जानी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व की प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी के कारण ही 2019 में विपक्षी दल एकजुट नहीं हो सके थे। अब 2024 के लिए भी फिर से ये सवाल खड़ा हो सकता है। 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का दावा था कि उनकी पार्टी भाजपा को सत्ता में आने ही नहीं देगी। ऐन उसी वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मन ही मन प्रधानमंत्री पद पर दावा कर बैठी थीं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विपक्षी खेमे के तमाम कद्दावर नेता ममता बनर्जी के दिल्ली आते ही उनके इर्द-गिर्द जुट जाते, और भाजपा को सत्ता से बाहर किए जाने के फॉर्मूले पर विचार विमर्श चालू हो जाता। आम चुनाव से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी की रैली भी उनकी हौसलाअफजाई के लिए काफी थी। एनडीए दोबारा छोड़ देने के बाद जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हुए तो कांग्रेस को जरा भी अच्छा नहीं लगा। पहले तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और फिर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर मामले को जितना हो सका टाला गया, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता चली जाने के बाद कांग्रेस को मजबूरन हथियार डालने पड़े थे।

सबसे पहली बात यह कि जिस कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, उसके प्रदर्शन को देखना होगा। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना, पहला संबोधन था। उनके चाहने वाले ही नहीं, विरोधियों की भी निगाह राहुल गांधी के संबोधन पर थी। चाहने वाले इस उम्मीद में थे कि अपने भाषण के जरिए वे केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूत घेरेबंदी करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ सत्तापक्ष आशंकित था कि राहुल कहीं नया टंटा न खड़ा करें। लेकिन राहुल ने अपने अनुयायियों को जहां निराश किया, वहीं सत्तापक्ष को राहत दे दी। उनके लचर प्रदर्शन के बाद अब सत्तापक्ष चुनावी मैदान में बार-बार उन्हें अयोग्य बताएगा, उनकी नाकामियां गिनाएगा। सत्तापक्ष यह साबित करने की कोशिश करेगा कि राहुल भले ही अधेड़ हो चुके हों, लेकिन उनमें अभी भी बचपना है। सत्तापक्ष वोटरों को यह भी समझाने की कोशिश करेगा कि देश किसी अपरिपक्व के हाथ में नहीं दिया जा सकता।

कांग्रेस और उसके रणनीतिकार भूल गए कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने यह समूचे देश को संबोधित करने का मौका है। एक शानदार अवसर वे चूक गए। वाममोर्चे के एक-दो सदस्यों को छोड़ दें तो समूचा विपक्ष ही अविश्वास प्रस्ताव पर दिशाहीन नजर आया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से भी उम्मीद थी कि वे कुछ तर्क देंगी। लेकिन उन्होंने भी निराश किया। एक दौर में समाजवादी राजनीति अपनी धारदार भाषण कला और तर्कों के कारण जानी जाती थी। लेकिन चाहे जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल, उसके सदस्य भी कोई धारदार और वजनी तर्क पेश नहीं कर पाए। जनता दल यू के सांसद गिरधारी यादव के संबोधन का आशय क्या रहा, वह शायद ही लोकसभा के सदस्य कुछ समझ पाए होंगे।

फिर विवादों में फंस गए राहुल

अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दो भाषण बहुत ही विवादास्पद रहे, एक तो राहुल गांधी का, जिन्होंने अपने भाषण में भारत माता की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर सत्तापक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। सदस्यता खोने से पहले लोकसभा में अपने अंतिम भाषण में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी के रिश्तों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिन्हें लोकसभा के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने फिर अडानी का नाम लेते हुए कहा कि वह आज अडानी पर नहीं बोलेंगे। दूसरा विवादास्पद भाषण रहा सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का। वैसे उनका हर भाषण विवादास्पद हो जाता है, लेकिन बाद में वह यह कहकर बच निकलते हैं कि उन्हें हिन्दी नहीं आती, इसलिए गलत शब्द मुहं से निकल जाते हैं। हालांकि जब 370 हटाई जा रही थी, तब उन्होंने लोकसभा में कह दिया था कि जम्मू कश्मीर विवादास्पद है, इसलिए भारत को वहां से 370 हटाने का अधिकार नहीं। जब यह मामला उल्टा पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि वह तो पूछ रहे थे कि सरकार को अधिकार है या नहीं। लेकिन उनका सवाल भी गलत था, क्योंकि भारत की नजर में कश्मीर विवादास्पद नहीं है, वह भारत का अभिन्न अंग है। इस बार उन्होंने जानबूझकर नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी कह कर पुकारा। हीरा कारोबारी नीरव मोदी एक भगौड़ा है, जिसके खिलाफ इंटरपोल के वारंट जारी हैं। राहुल गांधी को जिस मामले में दो साल की सजा हुई है, उस मामले में राहुल गांधी ने भी जिन मोदियों को चोर कहा था, उनमें नीरव मोदी का नाम भी लिया था। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी को ऐसा धृतराष्ट्र भी कहा जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न होते देखता रहा। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने नियमों का हवाला देकर उन्हें माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अविश्वास प्रस्ताव निपट जाने के बाद उनका मामला आचरण कमेटी को सौंपने और तब तक उन्हें सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव पास किया गया। विपक्ष उस समय वॉकआउट कर चुका था, इसलिए न तो वह खुद अपना बचाव कर सके, न ही विपक्ष का कोई अन्य सदस्य।

बिखरे विपक्ष का दांव खाली

राजनीति में जो कहा जाता है असल में वह होता नहीं। जो वास्तविकता होती है, उसका संदेश सिर्फ संकेतों के जरिए दिया जाता है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का कुछ इसी अंदाज में उठाया गया कदम रहा। मणिपुर के बहाने मोदी सरकार को घेरना विपक्ष का घोषित मकसद था, लेकिन हकीकत में उसकी मंशा एक नैरेटिव के माध्यम से मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की थी। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के ठीक पहले ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल हुई, इसलिए यह कांग्रेस द्वारा राहुल को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का पड़ाव भी बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष और विशेषकर राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हुए? तीन दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का नतीजा देखें तो इन सवालों का जवाब विपक्ष के लिहाज से निराशाजनक है। तमाम विपक्षी नेताओं और राहुल गांधी ने संसदीय मंच के बेहतर उपयोग का अवसर गंवा दिया। इस बार राहुल के समर्थक ही नहीं, उनके विरोधियों को भी उनके भाषण का बेसब्री से इंतजार था। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए करीब 60 प्रतिशत देश की थाह लेने वाले राहुल से उम्मीद थी कि वह विनोबा न सही, कम से कम चंद्रशेखर की तरह अपने जमीनी अनुभवों के जरिए संसद को संबोधित कर अपना अनुभव बांटेंगे। राहुल के राजनीतिक विरोधी भी सशंकित थे कि कहीं उनका सामना बदले हुए राहुल से न हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल का भाषण निराशाजनक रहा। उम्मीद थी कि सरकार पर उनके हमलों की धार तीखी होगी, लेकिन वह प्रभावहीन रहे।

प्रधानमंत्री ने फेरा पानी

प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो राहुल गांधी एक वरदान समान हैं। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने राहुल का नाम नहीं लिया, अलबत्ता इस तथ्य को स्वीकार भी किया। अविश्वास प्रस्ताव हो या विश्वास प्रस्ताव, चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री को

ही देना होता है। इस नाते उनकी बारी सबसे आखिर में आती है। चूंकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, इसलिए वह प्रधानमंत्री के जवाब के बाद स्पष्टीकरण मांग सकती थी। लेकिन उसने खुद ही यह मौका खो दिया। वह ठोस और जानदार आरोप नहीं लगा सकी और आखिर में स्पष्टीकरण के वक्त समूचे विपक्ष के साथ सदन से बहिर्गमन कर गई। प्रधानमंत्री को एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव ने मौका दे दिया। उनके जवाब को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। पहले हिस्से में उन्होंने जहां अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की गिनती कराई, वहीं मणिपुर समेत समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं के लिए अतीत की कांग्रेस सरकारों के कदमों को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने लोहिया को उद्धृत करते हुए पूर्वोत्तर की अशांति के लिए नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। वेरियर एल्विन के सुझाव पर नेहरू ने पूर्वोत्तर को एक तरह से संरक्षित और बफर जोन बना दिया था, जहां विकास की किरणें नहीं पहुंचनी थी। नेहरू शासन में पहुंची भी नहीं। इसका लोहिया ने विरोध करते हुए कहा था कि 30 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कोल्डस्टोरेज में तब्दील करके उसे विकास से वंचित कर दिया गया है। लोहिया ने उस क्षेत्र में घुसने का बार-बार प्रयास किया और संरक्षित क्षेत्र बनाने का बार-बार विरोध किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर लोहिया के बहाने कांग्रेस के साथ खड़े समाजवादी दलों को भी निशाना बनाया। मणिपुर की समस्या के लिए उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर रहस्यपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अदालतों में जो हो रहा है, वह सबको पता है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि अधीर रंजन चौधरी भले ही इस बात पर खुश होते रहें कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को संसद में बोलने के लिए विवश कर दिया लेकिन यह बोलना क्या विपक्ष के हित में गया है? इस मौके का उपयोग उन्होंने देश को संबोधित करने के रूप में लिया

और इसका भरपूर फायदा उठाया। एक तरह से मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी, जिसका कम से कम विपक्ष को तो कोई फायदा नहीं होने वाला।

अविश्वास प्रस्ताव के बाद की राजनीति

संसद का मानसून सत्र निपट गया। अब मौका है यह आंकलन करने का कि सरकार भारी पड़ी या विपक्ष। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब रहा, या विपक्ष खुद कटघरे में खड़ा हो गया। विपक्ष ने बेहिचक स्वीकार किया है कि वह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया क्योंकि वह मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहता था। बहस की शुरुआत भी पूर्वोत्तर के सांसद गौरव गोगोई से करवाई गई थी, जिन्होंने अपने भाषण का लगभग आधा समय मणिपुर पर ही बोला। बहस का जवाब निश्चित ही प्रधानमंत्री को देना था, और वह तीन दिन की बहस के बाद आखिरी दिन 10 अगस्त को जवाब देने आए भी, लेकिन उनका मणिपुर पर जवाब शुरू होने से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होती है, तो प्रधानमंत्री के जवाब के बाद अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले को फिर से बोलने का मौका मिलता है और उसके बाद वोटिंग होती है।

अपनी बात रखकर मतदान करवाने से पहले वॉकआउट करके विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया। अगर वह मणिपुर पर आखिरी समय तक आक्रामक रहता और प्रधानमंत्री के मणिपुर पर दिए गए जवाब के बाद गौरव गोगोई फिर से सवाल करके प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने के बाद वॉकआउट करते तो विपक्ष की गंभीरता दिखाई देती। लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट तब किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के खिलाफ अपने सांसदों से नारे लगवा रहे थे। निश्चित ही सदन में नारेबाजी दोनों तरफ से अमर्यादित व्यवहार था। लोकसभा स्पीकर ने दोनों पक्षों को नारेबाजी करने से रोका भी, लेकिन इस बार नारेबाजी मोदी के भाषण का हिस्सा था, वह खुद नारे लगवा रहे थे। सवाल फिर वही है कि विपक्षी एकता का वैसा प्रदर्शन लोकसभा में क्यों नहीं दिखा, जैसा राज्यसभा में दिखा। विपक्ष अपनी रणनीति में इस लिहाज से फेल हुआ कि दिल्ली सेवा बिल पर उसने राज्यसभा में तो वोटिंग करवाई, लेकिन लोकसभा में न दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग करवाई, न अविश्वास प्रस्ताव पर।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के संबोधन में दिखी चुनाव की झलक

अविश्वास प्रस्ताव पर सत्तापक्ष की ओर से विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जैसा रवैया दिखाया, उसमें भावी चुनावी अभियान की झलक दिखी। अमित शाह ने तथ्य-तर्क के साथ ही कटाक्ष की जुगलबंदी से विपक्ष को करारा जवाब दिया। राहुल के भाषण के बाद अमित शाह ने लोकसभा में अपनी बात रखी और इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अपने तर्कों, तथ्यों और तंज के जरिए रचे भाषाई प्रतीकों के माध्यम से वह विपक्षी खेमे पर भारी पड़े। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जवाब से साफ कर दिया है कि अगले चुनाव में भाजपा की ओर से कांग्रेस को सत्ता का भूखा और देश की समस्याओं की जड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिस पूर्वोत्तर को लेकर इन दिनों माहौल तल्ख है, उसकी समस्याओं के लिए भी नेहरू पर उंगली उठाई जाएगी। नेहरू ने एक विदेशी मानवशास्त्री वेरियर एल्विन के सुझाव पर नेफा को संरक्षित घोषित किया था। मोदी ने अपने जवाब में वेरियर का नाम तो नहीं लिया, पर संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराने का संकेत जरूर किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के समाजवादी खेमे को भी लोहिया के जरिए चोट पहुंचाई। जाहिर है कि आगामी चुनाव में मोदी लोहिया के बहाने विपक्षी समाजवादी धारा का भी विरोध करेंगे। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मोदी और उनकी सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर सत्तापक्ष ने अपनी उपलब्धियों को ही देश के सामने रखा। इस अवसर का लाभ उठाकर मोदी ने परिवारवाद और दरबारवाद के लिए सीधे-सीधे गांधी-नेहरू परिवार पर हमला बोल दिया। इससे यह तो तय है कि आगामी चुनावों में इन मुद्दों को भाजपा जोर-शोर से उठाएगी।

'स्पेस अप' इंडिया पर दुनिया का भरोसा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सफल अभियानों के इतिहास में गत दिनों एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अथवा पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) श्रृंखला के 56वें यान ने उड़ान भरी। यान अपने साथ ले जाए गए सिंगापुर के सात उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षा में भेजने में सफल रहा। इसरो का यह तीसरा व्यावसायिक अभियान था। चौथा अभियान सितंबर में प्रस्तावित है। इस श्रेणी का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन पीएसएलवी-सी51/ अमेजॉनिया-1, 28 फरवरी 2021 को और दूसरा, पीएसएलवी-सी 53 पिछले साल 30 जून को प्रक्षेपित किया गया था। पीएसएलवी-सी 56 मिशन को पूरा किया है इसरो की आनुषांगिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ने। यह कंपनी इसी साल 22 अप्रैल को भी पीएसएलवी-सी55/ टेलईओएस सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुकी है। एनएसआईएल की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके अलावा इसरो की एक और व्यावसायिक कंपनी सितंबर 1992 में आरंभ की गई एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लि. (एसीएल) है। यह मुख्यतः मार्केटिंग के लिए है। इसका काम इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि का प्रचार व व्यावसायिक दोहन करना है।

पिछले तीस साल में व्यावसायिक दृष्टि से इसरो ने एक लंबा और महत्वपूर्ण सफर तय किया है। लेकिन अगर वैश्विक अंतरिक्ष बाजार के आकार के हिसाब से देखें तो हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2022 में ग्लोबल स्पेस एक्स्प्लोरेशन मार्केट 186 अरब डॉलर का था। यह 16.21 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहा है। इस दर से यह वर्ष 2032 तक बढ़कर 1879 अरब डॉलर हो जाएगा। इसके मुकाबले भारतीय अंतरिक्ष बाजार की मौजूदा वैल्यू आठ अरब डॉलर ही है, और विकास दर सिर्फ 4 प्रतिशत। इस विकास दर के हिसाब से हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2040 तक 40 अरब डॉलर की होगी। लेकिन, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक संभावनाएं हैं। मल्टीनेशनल मैनेजमेंट कन्सल्टेंसी फर्म आर्थर डी लिटिल (एडीएल) की रिपोर्ट इंडिया इन स्पेस : ए डॉलर 100 बिलियन इंडस्ट्री बाय 2040 का दावा है कि वर्ष 2040 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इसकी वजह है सरकार द्वारा अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टरों के लिए खोल देना।

इस समय भारत में करीब 190 एक्टिव स्पेस स्टार्टअप्स हैं, जो इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जगह सुनिश्चित कर रही हैं। ये कंपनियां, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स निर्माण और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरों वाले सेटेलाइटों का निर्माण तथा उपग्रह आधारित डेटा सेवाएं उपलब्ध कराने जैसी तरह-तरह की अंतरिक्षीय गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। 2014 में देश में केवल एक स्टार्टअप था। एक दशक में दो सौ गुना संख्या हो जाना, स्वयं में बहुत उत्साहवर्द्धक है। 2021-30 की अवधि के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप्स पर इंक42 की रिसर्च बताती है कि इनकी औसत वार्षिक विकास दर लगभग 30 प्रतिशत है और वर्ष 2030 तक इनके लिए करीब 77 अरब डॉलर के अवसर उपलब्ध होंगे। देश में स्पेसटेक स्टार्टअप्स को 205 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है और उन्होंने वर्ष 2014 से मई 2023 तक, कुल 33 डील की हैं।

भारत में करीब चार सौ निजी स्पेस कंपनियां हैं। इस विशाल संख्या की बदौलत भारत सर्वाधिक स्पेस कंपनियों वाले देशों में पांचवें स्थान पर पहुंच चुका है। इन कंपनियों में छिपी संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इनमें लगभग 112 मिलियन डॉलर का निवेश भी किया है। वर्ष 2022 में अंतरिक्षीय कार्यक्रमों पर खर्च के मामले में हम आठवें स्थान पर थे। अमेरिका (61.97 अरब डॉलर), चीन (11.94 अरब), जापान (4.90 अरब), फ्रांस (4.20), रूस (3.42), यूरोपियन यूनियन (2.60), जर्मनी (2.53) के मुकाबले हमने सिर्फ 1.93 बिलियन डॉलर ही खर्च किए। इसके बावजूद हम एक स्पेस सुपर पॉवर बनने की ओर अग्रसर हैं। फिर भी हमारी इसरो, विश्व की छठवीं सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। आज हम अमेरिकी खर्च के चार प्रतिशत से भी कम खर्च के बावजूद उसकी बराबरी में खड़े हैं, उसके साथ समझौते कर रहे हैं तो इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे बढ़ते प्रभुत्व का परिचय मिलता है। हमारी किफायत ही हमारी ताकत है। इस ताकत का परिचय दुनिया को हमने एक दशक पहले वर्ष 2013 में दिया था, जब महज 450 करोड़ रुपए के खर्च में हमने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सबको हैरान कर दिया था। आज हम दुनियाभर में कम लागत वाले उपग्रहों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इस ताकत को हम लगातार बढ़ाते गए हैं। पिछले दो दशकों में इसरो 34 देशों के 381 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है।

● **प्रवीण सक्सेना**

सिंगल विंडो क्लीयरेंस और ऑथराइजेशन का काम

अंतरिक्ष उद्यमों में छिपी अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिहाज से सरकार ने इस साल इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। इसके मुताबिक इसरो मुख्यतः नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों व अनुप्रयोगों में अनुसंधान व विकास और बाह्य अंतरिक्ष के बारे में इंसानी समझ के विस्तार पर ध्यान देगा। अंतरिक्ष नीति चार विभिन्न, लेकिन एक-दूसरे से संबद्ध इकाईयों पर जोर देती है, जिनका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। खासकर ऐसी गतिविधियों में, जो पारंपरिक रूप से इसरो के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसरो के अलावा, इन इकाईयों में प्रमुख है, इनस्पेस (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर)। इनस्पेस स्पेस लॉन्च, लॉन्च पैड तैयार करने, सेटेलाइटों की खरीद-बिक्री, डेटा प्रसार जैसे कामों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस और ऑथराइजेशन का काम करेगी। साथ ही, यह सरकारी तथा निजी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियां, उत्पाद, प्रक्रियाएं और उत्कृष्ट कार्यप्रणालियां भी साझा करेगी। दूसरी इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्मों के व्यावसायिक दोहन, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, लीजिंग, स्पेस उपकरणों, प्रौद्योगिकी, प्लेटफॉर्मों और अन्य परिसंपत्तियों की व्यवस्था का काम देखेगी। इनके अलावा अंतरिक्ष विभाग है, जो अंतरिक्षीय प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा तथा अंतरिक्ष नीति के तहत समग्र दिशा-निर्देश उपलब्ध कराएगा।

क्या चुनौती बन पाएगा इंडिया?

मिशन 2024 में भाजपा नीत एनडीए को सरकार से बाहर करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। अब तक हुई 2 बैठकों में गठबंधन की एकता मजबूत दिखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया मोदी को चुनौती दे पाएगा?

विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया) रखकर भाजपा को असहज कर दिया है। धर्म और राष्ट्रवाद के सहारे राजनीति करने वाली भाजपा के इस एकाधिकार को विपक्ष ने इस बार अलग अंदाज में चुनौती दे दी है। विपक्ष ने अपने लिए नारा भी राष्ट्रवाद से जुड़ा चुना है- जीतेगा भारत। विपक्ष ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया) नाम बहुत सोच समझकर रखा है।

विपक्ष के बड़े नेताओं की मानें, तो यह नाम राहुल गांधी ने दिया है। सन् 2014 के बाद यह पहला अवसर है, जब विपक्ष को सिर्फ उसके नाम के ही आधार पर ऐसी चर्चा देशभर में मिल गई है। विपक्ष ने हाल के दिनों में अपने गठबंधन को तेजी से आकार दिया है। यह इस बात से भी जाहिर हो जाता है कि गठबंधन के 26 दलों में, जिनके सदस्य संसद में हैं; उन्होंने भाजपा (एनडीए) सरकार के खिलाफ साझा रणनीति अपनाई है। विपक्ष की तेजी का ही असर था कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को भी लंबे समय बाद साझी बैठक करनी पड़ी।

हाल के दो लोकसभा चुनावों में भाजपा ने खुद को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का चैम्पियन बताकर चुनाव लड़ा और उसे सफलता भी मिली। निश्चित ही 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उप्र, गुजरात और 2023 में कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने खुलकर इस मुद्दे को अपनाया। लेकिन उसे सफलता मिली-जुली ही मिली। बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में उसे नाकामी मिली और दो जगह कामयाबी। भाजपा के इस राष्ट्रवाद को विपक्ष ने उसी की पिच पर जाकर चुनौती दी है। विपक्ष, जैसा कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि भाजपा के राष्ट्रवाद के विपरीत कांग्रेस (विपक्ष) का राष्ट्रवाद संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष सोच पर आधारित है।

देखें, तो राष्ट्रवाद वास्तव में कांग्रेस का नारा था। आजादी के समय से ही। लेकिन भाजपा ने बहुत चतुराई से इसे कांग्रेस से छीन लिया। आजादी से पहले की बात करें, तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की ही भूमिका थी, आरएसएस की नहीं। नरम और गरम दल दोनों के ही अधिकतर नेता कांग्रेस की ही विचारधारा में पले, बढ़े; या फिर वामपंथी तेवर के साथ, जिसमें देश के लिए जान भी दे देने का जज्बा शामिल था। आरएसएस तो कहीं तस्वीर में कभी रहा ही नहीं। लेकिन भाजपा ने पिछले दो दशक में राष्ट्रवाद का नारा कांग्रेस से चुराकर अपना बना लिया। हां, एक अंतर यह जरूर है कि भाजपा का राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद है, जबकि कांग्रेस का समग्र राष्ट्रवाद। यानी सभी धर्मों और समुदायों से मिलकर बना राष्ट्रवाद। गठबंधन को इंडिया नाम देकर विपक्ष ने इसी राष्ट्रवाद को अपनाकर भाजपा को चुनौती देने की ठानी है।

विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने से भाजपा खेमे में चिंता है। यह उसके नेताओं के बयान से साफ जाहिर होता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री अब अपने हर भाषण में इंडिया नाम का जिक्र करने लगे हैं। एक बार उन्होंने विपक्ष के इंडिया नाम की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। अगले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। भाजपा की कोशिश विपक्ष के इंडिया को बदनाम करने की है, ताकि उसके अपने इंडिया के लिए चुनौती पैदा न हो। लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के नेता भाजपा की इस बेचैनी को समझ रहे हैं और उसी तर्ज में जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन आखिर में यह इंडिया (देश) की जनता होगी, जो यह तय करेगी कि वास्तव में किसका इंडिया उसे पसंद है- भाजपा का या विपक्ष का। अर्थात् हिंदू राष्ट्रवाद या समग्र राष्ट्रवाद। देखा जाए, तो विपक्ष का यह इंडिया नामकरण कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उपजा है। राहुल का द आइडिया ऑफ इंडिया समग्र राष्ट्रवाद की बात करता है। एक ऐसा राष्ट्रवाद, जो देश के सभी धर्मों और समुदायों को समाहित करता है; न कि भाजपा के हिंदू राष्ट्रवाद की तरह एक ही धर्म की बात करता है। कहा जा सकता है कि 2024 का चुनाव इस समग्र राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद के बीच होना है। विपक्ष इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगा और भाजपा विपक्ष (कांग्रेस) के इस राष्ट्रवाद को भ्रष्ट, परिवारवादी, देश-विरोधी आदि-आदि बताती जाएगी। साफ है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर भाजपा के एकाधिकार को गंभीर राजनीतिक चुनौती दे दी है। यह भाजपा के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को भी चुनौती होगी। हो सकता है भाजपा किसी प्रॉक्सी के जरिए विपक्ष के इंडिया नाम के खिलाफ कोर्ट

सीटों का पेच

कांग्रेस के रणनीतिकारों ने देशभर में अपनी मजबूत सीटों या उन सीटों जो बदले माहौल में (भविष्य के विधानसभा चुनाव नतीजों के कारण) उसकी झोली में आ सकती हैं; को लेकर खाका तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, पार्टी 390 से 400 सीटों पर लड़ने पर जोर दे सकती है। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकार इस चीज का ध्यान रखेंगे कि साथी विपक्षी दलों का सीटों के बंटवारे में कोई विरोध नहीं रहे। शायद कोशिश रहेगी कि जहां भी कांग्रेस का उम्मीदवार हो, वहां साथी विपक्षी दल का उम्मीदवार न उतरे और न कांग्रेस का अपना उम्मीदवार अन्य दलों की सीटों पर उतरे। कांग्रेस 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 400 से अधिक सीटों पर लड़ती रही है और 2009 में उसे 200 से ज्यादा सीटें मिली थीं। देशभर में 152 सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर भाजपा से है और दूसरे दलों का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस मान रही है कि यदि वह खुद को मजबूत करती है, तो 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा को ज्यादा सीटों पर मात दे सकती है।

भारत जोड़ो यात्रा-2 बदलेगी माहौल?

राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा-2 की तैयारी कर रहे हैं। यह यात्रा गुजरात के पोरबंदर से त्रिपुरा के अगरतला तक की हो सकती है। उप्र सहित कुछ चुनावी राज्यों में यह यात्रा होगी। अकेले उप्र में 80 लोकसभा सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी प्रदेश में पूरे 23 दिन यात्रा करेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि यात्रा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी कुछ जगह साथ रखने के लिए सहमत कराया जा सके। यही नहीं, रालोद के जयंत चौधरी, जो बेंगलूरु बैठक में शामिल हुए थे; को राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल करने की कोशिश की जाए। कांग्रेस रालोद के साथ गठबंधन कर ले, तो हैरानी नहीं होगी। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आ सकते हैं। कांग्रेस का फोकस पश्चिमी उप्र पर है और उसकी नजर लोकसभा की 27 सीटों पर है। सन् 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थीं और उसके नेता मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राज्य में उसे फिर ऐसा करने का अवसर दे सकती है। भारत जोड़ा यात्रा-2 का जिम्मा इस बार मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर होगा, जो इसकी रूपरेखा बनाने में जुटे हैं। यात्रा का संभावित महीना सितंबर हो सकता है। यदि 2 अक्टूबर की तारीख तय हुई, तो यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू की जा सकती है। यह यात्रा त्रिपुरा तक जाएगी। पिछली यात्रा में राहुल गांधी उप्र पहुंचे तो थे; लेकिन गाजियाबाद से प्रवेश करते हुए शामली, बागपत होते हुए हरियाणा चले गए थे। भारत जोड़ो यात्रा-2 का मार्ग मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए तय होगा।

में पहुंचे और विपक्ष को इंडिया नाम इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश करे। देखना दिलचस्प होगा कि यदि ऐसा होता है, तो उसका क्या नतीजा निकलता है? कानून के ज्यादातर जानकार मानते हैं कि शायद ही अदालत विपक्ष को ऐसा करने से रोकेगी; क्योंकि देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, जिनके नाम में इंडिया शब्द इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी की कोशिश हाल के महीनों में भाजपा के राष्ट्रवाद को भेदभावपूर्ण, बहुसंख्यकवादी और हिंसक बताने की रही है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी उन्होंने यही बताया था और इसे मोहब्बत की दुकान कहा है यानी देश के हर नागरिक से प्यार, नफरत नहीं। जमीनी जानकारी बताती है कि राहुल गांधी को इस यात्रा से अपनी छवि बदलने और खुद को जनता की बीच पहुंचाने में सफलता मिली है। राहुल यह संदेश देने में सफल रहे कि उनकी यात्रा सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश को बचाने की है। अब इंडिया नाम रखकर गठबंधन यही संदेश दे रहा है।

कांग्रेस इस महागठबंधन का नेतृत्व अभी नहीं कर रही, लेकिन बेंगलूरु की बैठक में जिस तरह सभी नेता कांग्रेस के इर्द-गिर्द दिखे, उससे साफ लगता है कि इन दलों ने यह महसूस कर लिया है कि कांग्रेस के ही नेतृत्व में भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। महागठबंधन अब मुंबई की बैठक में आगे जाने की बड़ी चीजें तय करेगा। यह बैठक 30 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बेंगलूरु बैठक के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं हुई थी। बैठक में भाजपा का मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा देने पर जरूर सहमति बनी है। सीटों पर बंटवारे में शायद अभी वक्त लगे। इंडिया गठबंधन के सभी दल एक समय में एक ही काम करने की रणनीति पर चल रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में जिस तरह से विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार को मणिपुर और अन्य मुद्दों पर घेरा है, उससे जाहिर है कि संसद में भी यूपीए की जगह इंडिया सरकार से लड़ रहा है। शायद भाजपा को भी इसकी उम्मीद नहीं रही होगी। गठबंधन अब मुंबई की बैठक में शायद गठबंधन के अध्यक्ष और संयोजक के अलावा अन्य पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दे दे। गठबंधन के एक नेता ने कहा- मुंबई की बैठक में हम 11 सदस्यों वाली एक समन्वय समिति को अंतिम रूप दे सकते हैं। गठबंधन अलग-अलग समितियां गठित करने पर भी काम कर रहा है, जो अलग-अलग मुद्दों को देखेंगी। मुंबई में इंडिया में शामिल 26 दलों के बीच सीट-बंटवारे, चुनाव की तैयारियों और प्रचार प्रबंधन को लेकर चर्चा होनी है। गठबंधन अपना मुख्य सचिवालय दिल्ली में बनाने पर भी सहमत हो सकता है। यह तय है कि गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देशभर में बड़ा अभियान शुरू करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें आयोजित होंगी और भाजपा पर प्रहार किया जाएगा।

गठबंधन किसी एक नेता को अभी अपने चेहरे के तौर पर सामने नहीं करेगा। पिछली दो बैठकों में दिखा है कि ज्यादातर दलों का झुकाव राहुल गांधी की तरफ है। लेकिन उनकी लोकसभा सदस्यता का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है, तो यह कांग्रेस ही नहीं गठबंधन के लिए भी बड़ी जीत होगी। राहुल गांधी ही गठबंधन में ऐसे नेता हैं, जिनकी राष्ट्रव्यापी छवि है। बेंगलूरु की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वह प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं।

दिलचस्प बात यह भी है कि टीवी चैनलों के हाल में गठबंधन के नेता को लेकर किए सर्वे में भी अधिकतर लोग राहुल गांधी को ही नेता के रूप में सबसे ज्यादा वोट दे रहे हैं। वैसे इस दौड़ में ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक का नाम लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन वाले यूपीए के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के ही हक में दिखते हैं, जिनमें तमिलनाडु के एमके स्टालिन से लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन तक शामिल हैं। मुंबई की बैठक में गठबंधन सोनिया गांधी को अपना अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर सकता है। बेंगलूरु की बैठक में सोनिया गांधी ने जो सक्रियता दिखाई थी, उससे साफ है कि वह इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। सोनिया गांधी की उपस्थिति ने इस बैठक में मीडिया का ध्यान भी अपनी तरफ काफी खींचा था, जिससे विपक्ष में सोनिया गांधी के महत्व का पता चलता है। भाजपा ने इसे कांग्रेस के गठबंधन को हाईजैक करने से जोड़ा और प्रचार भी किया कि नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने से खुश नहीं हैं। हालांकि एक दिन के ही भीतर नीतीश कुमार ने बयान देकर साफ कर दिया कि यह बात सही नहीं है और सब मिलकर भाजपा को हराएंगे।

● **विपिन कंधारी**

अगले आम चुनाव के पहले राउंड का मतदान होने में करीब 8 महीने रह गए हैं, लेकिन चुनाव अभियान अभी ही अपने चरम पर पहुंच चुका है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सहायकों और राजनीतिक नेताओं की हर चाल, हर बयान और हर भाषण से साफ दिख रहा है। यह प्रधानमंत्री की विदेश नीति संबंधी महत्वपूर्ण चालों से भी स्पष्ट हो रहा है। चुनाव अभियान काफी पहले से तो शुरू हो ही गया है, इसमें उल्लेखनीय बात यह भी है कि विपक्ष भी साझा मकसद के साथ सक्रिय हो गया है।

दूसरे राउंड में भाजपा

चुनावी लोकतंत्र के डीएनए में ही यह शामिल है कि चुनाव में विपक्ष को हमेशा सत्तासीन सरकार को हटाने का मौका नजर आता है। इस बार न केवल जोश उफान पर है, बल्कि गठबंधन बनाने के मामले में काफी यथार्थपरक कोशिश भी की गई है। 2019 में ऐसा नहीं था। कांग्रेस छत्तीसगढ़, मप्र और राजस्थान जैसे तीन राज्यों में अपनी जीत से उत्साहित थी। उसका मानना था कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का जो नारा दिया था वह बाजी मारने वाला साबित होगा। यह इन तीन हिंदी प्रदेशों में तो चल गया था और मोदी को धूल चाटनी पड़ी थी, लेकिन आम चुनाव में वह कारगर नहीं रहा। आप जिस खेमे के हों उसी के मुताबिक कह सकते हैं कि कांग्रेस मुगालते में थी और उसे शर्मसार होना पड़ा, या पुलवामा-बालाकोट कांडों ने पूरे चुनाव को वह मोड़ दे दिया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप चाहे जैसे भी व्याख्या करें, हम सब जानते हैं कि अंतिम नतीजा क्या हुआ था। इस बार फर्क यह है कि सबसे बड़े पुरस्कार, यानी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक्शन काफी पहले से ही शुरू हो गया है। इस हद तक कि आम चुनाव से कुछ महीने पहले तीन प्रमुख हिंदी राज्यों और तेलंगाना में होने वाले चुनावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अतीत में, राज्यों के चुनावों को (भले ही गलती से) दिशासूचक माना जाता था, लेकिन विशेष तौर पर आज हमें छोटे-से मगर साहसी राज्य मिजोरम को भी शामिल करना चाहिए। भले ही यह लोकसभा में केवल एक सांसद भेजता है, लेकिन यह मणिपुर का महत्वपूर्ण पड़ोसी राज्य है और एनडीए का धीरज खोता सदस्य है। यह ऐसा है जैसे हमारे सबसे बड़े राजनीतिक लीग में सेमी-फाइनल को छोड़ सीधे फाइनल में छलांग लगा दी गई है। कुछ बातों ने इस चुनाव को खासकर मोदी और भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इंडिया के गठन के साथ एक ऐसा विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है, जिसका विस्तार पूरे देश में है। हालांकि उसके कुल सांसदों की संख्या केवल 144 है, लेकिन वे 20 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से आए हैं। इसके अलावा इस गठबंधन के सदस्य 11 राज्यों में सत्ता में हैं। पहले के तीसरे मोर्चे जैसे खिचड़ी गठबंधन की जगह इस नए गठबंधन की धुरी एक राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसे कुछ और दल भी इससे जुड़ सकते हैं। तब यह और ज्यादा ताकतवर दिखेगा।

भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने की चाभी यह है कि उप्र में और बिहार को छोड़ दें तो अधिकतर हिंदी राज्यों में वह दोबारा सबका सूपड़ा साफ कर दे। भाजपा के पक्ष में जो बातें जा सकती हैं उनमें यह भी है कि विपक्ष के वे

बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी

भाजपा सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में पिछले 20 सालों के दौरान भाजपा की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसे जनता के बीच ले जाने की तैयारी की गई है। इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इस बारे में विभागों से वर्षवार योजनाओं की उपलब्धियां तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें वर्ष 2003 से 2018 तक भाजपा सरकार की योजनाएं और दिसंबर 2018 से मार्च 2020 को छोड़कर अब तक की जनहितैषी योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देना, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, आवास योजना, जनजातीय वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के अलावा बड़ी उपलब्धि दिलाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता में रखा गया है।

वोट बंट जाएं जो भाजपा की झोली में न जाने वाले हों, खासतौर से मुस्लिम वोट। भाजपा चाहेगी कि उप्र में यह वोट सपा, बसपा, कांग्रेस, और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच बंट जाए। वैसे, कर्नाटक चुनाव ने संकेत दिया है कि मुस्लिम वोट अब काफी मजबूती से उस पार्टी के पक्ष में एकजुट हो रहा है जो भाजपा को हरा सकती है। इंडिया जैसा बड़ा गठबंधन उनके लिए चयन आसान बना सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक समीकरण आज 2019 के मुकाबले पूरी तरह भिन्न है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अब ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि भारत कमजोर स्थिति में है। वास्तव में, आज का भारत 2019 के भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर है और दुनिया में उसका रुतबा भी बढ़ा है।

दरअसल, दुनिया बदल गई है। अब वह पुलवामा कांड के बाद की गई जवाबी कार्रवाई को, या किसी पड़ोसी देश के बहाने अपने देश में राष्ट्रवादी भावना को भड़काने जैसी किसी बड़ी कार्रवाई को आसानी से बर्दाश्त नहीं करने वाली। पाकिस्तान ने आर्थिक मोर्चे पर घुटने टेक दिए हैं और वह गहरे आंतरिक राजनीतिक संकट

से जूझ रहा है। इसलिए वह भड़काऊ कार्रवाई अब शायद ही करेगा। इसके अलावा, चीन लद्दाख और दूसरी जगहों में एलएसी पर अपनी गतिविधियां तेज ही कर रहा है।

वास्तव में, जिस तरह पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया है कि अब वह सीमा पर शायद ही कोई संकट खड़ा करेगा, उसी तरह चीन इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसे अगर राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से फायदेमंद दिखेगा तो वह उकसाने वाली कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ आप कुछ भी शुरू करके तुरंत अपनी जीत की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन चीन के मामले में यह छूट नहीं ले सकते। यही वजह है कि मोदी सरकार चीन के मामले में बड़ी सावधानी से और शांतिवादी तेवर से कदम उठाती रही है। अब जबकि पिछले जाड़ों में बाली में शी-मोदी की छोटी मगर महत्वपूर्ण बैठक के बारे में चीन ने भेद खोल दिया है, हम देख सकते हैं कि हालात को शांत करने के लिए किस तरह चीन की ओर हाथ बढ़ाया जा रहा है। यह विदेश नीति संबंधी वही कदम है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। चुनाव से पहले चीन ने अगर उकसाऊ कार्रवाई की, तो वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा और सरकार के लिए एक चुनावी चुनौती होगी क्योंकि वह दावे करती रही है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा उसके अब तक के इतिहास में इतनी मजबूत कभी नहीं रही।

संभव है, मोदी ने सुलह की कोशिश पहले ही की हो, लेकिन उसे गुप्त रखा गया हो। इसके बाद चीन ने जोहान्सबर्ग में अजित डोभाल और वांग यी की बैठक के दौरान चीनी भाषा में जो बयान जारी किया उसमें बड़ी कुटिलता से बाली बैठक का जिक्र कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले तो उस बैठक को शिष्टाचार मुलाकात बताया था, मगर अब उसे बड़ी असहजता से कबूल करना पड़ा कि उस बैठक में कुछ ठोस बातें भी हुईं। यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण कहानी कहता है।

● इन्द्र कुमार

एकजुटता पर फोकस

देश में कांग्रेस जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मजबूत है उनमें से एक छत्तीसगढ़ है। यहां गाहे-बगाहे पार्टी में खींचतान और टकराव नजर आ जाती थी, मगर बीते कुछ दिनों में किए गए बदलाव ने पार्टी के नेताओं को करीब ला दिया है, अब तो पार्टी में एकजुटता नजर आने लगी है। राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं चाहता कि चुनाव से पहले गुटबाजी उभरे या फिर आपसी खींचतान की संभावना बढ़े, लिहाजा पार्टी ने बीते दिनों कुछ फैसले किए जिसके मुताबिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहन मरकाम से लेकर दीपक बैज को सौंपी गई, तो टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। किसी तरह की नाराजगी न पनपे इसलिए मोहन मरकाम को भी कैबिनेट में जगह दी गई। एक मंत्री प्रेमसाय टेकाम को मंत्री पद से हटाया गया तो उन्होंने जरूर अपनी नाराजगी जताई। राज्य की कांग्रेस की स्थिति पर गौर करें तो संतुलन की राजनीति पर पार्टी हाईकमान से लेकर प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश हो रही है, वहीं धार्मिक आयोजनों के जरिए धर्म प्रेमियों को अपने करीब लाया जा रहा है।

● रायपुर से टीपी सिंह

अजित को लेकर फंसी भाजपा

भाजपा के कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट को गठबंधन सरकार में शामिल करने का फैसला बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। कार्यकर्ताओं ने जून 2022 में शिवसेना में दो फाड़ के बाद कभी फडणवीस सरकार में सिर्फ एक मंत्री रहे एकनाथ शिंदे को फडणवीस को नजरअंदाज कर मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय का कड़वा घूट इसलिए पी लिया था कि भाजपा सरकार में आ रही थी और शिवसेना की कमर टूट रही थी। लेकिन अचानक अजित पवार के अपने समर्थक विधायकों के साथ सरकार में शामिल होने को महाराष्ट्र में भाजपा के कैडर के साथ संघ के स्वयंसेवक भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक देवेंद्र फडणवीस अकेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उपमुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब अजित पवार के भी उपमुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में दो उपमुख्यमंत्री होने के बाद न केवल मंत्रिमंडल में भाजपा की ताकत कम हुई है बल्कि देवेंद्र फडणवीस की भूमिका भी सीमित हो गई है।

● बिन्दु माथुर

महारानी के भविष्य पर असमंजस

अब यह तय है कि राजस्थान में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहीं सत्ता में वापसी की कोशिश करने के लिए अशोक गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर घेर रही भाजपा में नेतृत्व का पेंच अभी भी उलझा हुआ है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व न तो यह खुलकर घोषणा कर रहा है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और न ही किसी एक नेता का नाम आगे कर चुनाव में जाने की बात कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में पिछले 10 महीने में सात रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 सितंबर 2022 को पहली रैली सिरोही जिले के आबू रोड में की थी और आखिरी रैली 8 जुलाई 2023 को बीकानेर में की थी। मोदी की इन रैलियों की खास बात यह रही कि किसी भी रैली में मोदी ने यह प्रदर्शित नहीं होने दिया कि प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री उनकी नजर में कौन है। मोदी ही नहीं, पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और वर्तमान अध्यक्ष नड्डा ने भी राजस्थान में संगठन की बैठक के दौरान किसी एक नाम को आगे कर चुनाव लड़ने के संकेत नहीं दिए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की इस रणनीति से एक ओर जहां राजस्थान भाजपा के नेता अपने लिए उम्मीद की किरण देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शीर्ष नेतृत्व के इस व्यवहार से असहज महसूस कर रही हैं। गौरतलब है कि 2019 में सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से वंसुधरा राजे भाजपा के बैनर और होर्डिंग्स से लगभग बाहर हो गई थीं। इससे नाराज होकर वंसुधरा राजे ने भी पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मोदी की अजमेर रैली में वसुंधरा राजे न सिर्फ पोस्टरों, होर्डिंग और मंच पर दिखाई दीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर वसुंधरा राजे का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई।

भाजपा वसुधंरा को सम्मान दे रही है लेकिन वह नहीं कह रही है जिसे वसुंधरा सुनना चाह रही हैं। साफ है इसी साल चुनाव में जाने वाले इस राज्य को आलाकमान ने अपने हाथ में ले लिया है। राजस्थान में केंद्रीय हाईकमान ने सभी नियुक्तियां कर दी हैं और केवल चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान किसके हाथ में होगी यह निर्णय अभी तक लटका कर रखा है। क्या राजे चुनाव समिति की प्रमुख बनाई जाएंगी, जो अकेला अहम खाली पद बचा है? प्रदेश में गहलोत को हटाने के लिए सारी रणनीति और नारे दिल्ली से दिए जा रहे हैं। तंज भरा प्रचार गीत गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी भी दिल्ली से बनाकर भेजा गया है। इस बीच वसुंधरा राजे ने चुनाव पूर्व राज्यव्यापी यात्रा निकालने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति मांगी है। वसुंधरा राजे ने 2018 में भी राज्यवापी यात्रा निकाली थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार अभी तक उन्हें हरी झंडी नहीं दी है। कारण साफ है प्रदेश के लगभग सभी बड़े नेता वसुंधरा राजे द्वारा राज्यव्यापी रैली निकालने के खिलाफ हैं। प्रदेश के नेता चाहते हैं कि अगर यात्रा निकले तो उसकी अगुवाई नेताओं का समूह करे, अकेली वंसुधरा राजे नहीं। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व ने इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है।

प्रदेश में अपनी भूमिका और भविष्य को लेकर चिंतित वसुंधरा राजे ने 13 जुलाई को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। अध्यक्ष के साथ बैठक में वसुंधरा ने साफ कहा था कि प्रदेश में उनकी क्या भूमिका होगी, इसे पार्टी स्पष्ट करे। वसुंधरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि प्रदेश भर के कार्यकर्ता उनसे पूछते हैं और वह बताने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि नड्डा ने भी साफ कहा कि पार्टी की पूरी नजर राजस्थान पर है और जो भी फैसला होगा वह समय आने पर बता दिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के सभी नेताओं को आपसी मतभेद को भुलाकर साथ मिलकर काम करना है। खबर है कि वसुंधरा ने संकेतों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दिया है कि वह प्रदेश नेतृत्व पर अपना दावा छोड़ने के मूड में नहीं है। पार्टी ने भी वसुंधरा को कह दिया है कि पार्टी गहलोत सरकार को हराने के लिए यह तय कर चुकी है कि प्रदेश का विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

भाजपा-रालोद के मिलन का योग

अखिलेश यादव ट्विटर पर सांड से परेशान दिखते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक खेत उनके अपने ही सहयोगी चरते जा रहे हैं।

दरअसल, ओम प्रकाश राजभर के बाद सपा के एक और गठबंधन सहयोगी जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। खबर है कि भाजपा और रालोद के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। एनडीए में शामिल होते ही रालोद को केंद्र और उप्र सरकार में शामिल किया जाएगा। रालोद के एनडीए का हिस्सा बनते ही पश्चिमी उप्र में विपक्ष से नजदीकी चुनावी टक्कर होने की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली सेवा बिल पर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी जयंत चौधरी ने एनडीए सरकार के खिलाफ मतदान नहीं किया। उनके वोट से नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन इसके जरिए उन्होंने अपनी रणनीति का संकेत दे दिया। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि उनकी पत्नी अस्पताल में थीं, इसलिए वह मतदान करने नहीं आ सके। भाजपा खेमा लंबे समय से जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए डोरे डाल रहा था, लेकिन जयंत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बजाय योगी आदित्यनाथ से आश्वासन चाह रहे थे, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति पश्चिमी उप्र में केंद्रित है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

भाजपा के लिए पूरा मैदान

बिहार में पिछले महीने भाजपा की एक रैली में उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जिस बर्बर अंदाज में लाठियां चलाईं और उसके सांसदों-विधायकों को पीटा वह बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का प्रस्थान बिंदु हो सकता है। असल में बिहार एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। भाजपा के सामने बिहार की राजनीति की केंद्रीय ताकत बनने का वास्तविक अवसर है। एक बार पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद यह अवसर आया था लेकिन उस समय भाजपा इस अवसर का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थी। यह भी कह सकते हैं कि वह लोकसभा चुनाव में मिली भारी भरकम जीत के बाद अति आत्मविश्वास में थी इसलिए 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की ओर से बनाए गए मंडल की राजनीति के नैरेटिव को बहुत हल्के में लिया था। भाजपा नेता इस मुगालते में रहे कि नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति के नेता हैं और उनका अखिल भारतीय करिश्मा ऐसा है कि उनके सामने लालू और नीतीश की पारंपरिक मंडल राजनीति नहीं टिकेगी। तभी चुनाव नतीजा भाजपा के लिए सदमे की तरह था और यही वजह रही कि पहला मौका मिलते ही वह फिर से नीतीश की शरण में पहुंच गई। लेकिन इस बार भाजपा सावधान है और अपने दांव-पेंच आजमाने को तैयार है।

2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उसने बहुत बारीकी से नीतीश कुमार को कमजोर करने की राजनीति की। चिराग पासवान का एनडीए से अलग होना और 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना इसी राजनीति का हिस्सा था। इस राजनीति ने नीतीश कुमार की पार्टी को न सिर्फ तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, बल्कि तीसरे दर्जे की पार्टी भी बना दिया। उनका अपना वोट आधार बहुत कम हो गया और राष्ट्रीय जनता दल लगातार दूसरी बार प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरी। इसके बाद सब कुछ लिखित पटकथा की तरह हुआ। नीतीश कुमार मंडल की राजनीति को बचाने और अपनी पार्टी के अस्तित्व की रक्षा के लिए राजद के साथ चले गए। उन्होंने लालू प्रसाद के साथ मिलकर सात पार्टियों का एक गठबंधन बनाया। जदयू और राजद के नेता इसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानते रहे लेकिन असलियत यह है कि उनकी इस राजनीति ने बिहार में विपक्ष का पूरा स्पेस भाजपा को सौंप दिया। अभी इकलौता विपक्ष भाजपा है और पूरा मैदान उसका है। इससे पहले नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक यानी डेढ़ साल तक भाजपा इकलौते विपक्ष के तौर पर थी लेकिन तब वह विपक्ष की राजनीति करने की बजाय इस इंतजार में थी कि नीतीश कुमार कब वापसी करेंगे और भाजपा कब सत्ता में लौटेगी।

● विनोद बक्सरी

आजादी की 77वीं वर्षगांठ

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन

जय हिन्द

आजादी की 77वीं वर्षगांठ

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, देवास

तोशाखाना तो बहाना है

पाकिस्तान में सरकारी खजाने को तोशाखाना कहते हैं और उस तोशाखाना से सामान गायब करने या नियमों के विरुद्ध जाकर तोहफों को हथिया लेने के पहले आरोपी नहीं है इमरान खान। नवाज शरीफ से लेकर आसिफ जरदारी तक पर भी इस तरह के कई आरोप हैं। पर सजा इमरान खान को हुई तो इसका एक ही मतलब है कि मौजूदा हुकूमत और फौज किसी तरह से अगले चुनाव में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और उसके चेयरमैन इमरान खान को बाहर रखना चाहती है। इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है, इसका मतलब है कि वह अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। पर यह खेल मौजूदा सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की ऊंची अदालतों से इमरान खान कई बार अपना बचाव कराते रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल को उनका संरक्षक ऐसे ही नहीं कहा जाता। वैसे, तोशाखाना का मामला है बड़ा दिलचस्प। प्रधानमंत्री के नाते विदेशों से इमरान खान

को जो भी तोहफे मिलते, घर में बैठी उनकी बेगम बुशरा बीवी उसको ठिकाने लगा देती। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार तोहफे सरकारी तोशाखाना में जमा होने की बजाय सीधे प्रधानमंत्री आवास में आते और बुशरा बीवी तय करती कि किसको खजाने में जमा करना है और किसे अपने पास रख लेना है। फिर नियमों की खानापूर्ति की जाती। बुशरा बीवी की दोस्त फराह गोगी तोहफे को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने जाती और सीधे कैश बैग में भरकर स्पेशल विमान से लेकर आती थी। तब न सेना उनसे पूछती थी और न कोई अन्य सरकारी महकमा।

तोशाखाना का सबसे बड़ा घोटाला तब सामने आया जब दुबई के एक व्यापारी उमर फारूक जहूर ने यह दावा किया कि इमरान खान को सउदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो हीरो से जड़ित घड़ी दी थी, उसे उन्होंने 20 लाख डॉलर में इमरान खान से खरीद लिया है। उसने उस तोहफे को बकायदा अपने घर से लाइव जीओ टीवी को दिखाया। जहूर ने उस हीरे जड़ी घड़ी का बाजार में अंतरराष्ट्रीय मूल्य कई गुणा अधिक बताया था। लेकिन इमरान खान ने यह दावा किया था कि उनके लोगों ने वह घड़ी तोशाखाना से खरीद कर यहीं एक स्थानीय दुकानदार को बेच कर नियमानुसार 20 प्रतिशत पैसा जमा करा दिया था। इस घोटाले के बाद तो तोशाखाना से मंगाए और गायब किए सामानों की लंबी फेहरिस्त आ गई। उनमें कुछ जेवर, एक सोने की परत वाली पिस्तौल, करतार साहिब रूट के उद्घाटन के समय सिखों द्वारा दिए गए सोने के कलश इत्यादि तोशाखाना से गायब हुई चीजों में शामिल मिले। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले दर्ज कराया गया। पर इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने निचली अदालत से केस की सुनवाई के लिए कहा और लगभग डेढ़ साल बाद अब सेशन कोर्ट ने इमरान को सजा सुनाई है।

● ऋतेन्द्र माथुर

कार्यालय नगरपालिका परिषद, इटारसी

15 अगस्त 2023, स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर नगर के विकास का नया इतिहास रचने का संकल्प लेकर नगरवासियों की समस्यामुक्त जिन्दगी का हक दिलाने में प्रयासरत रहेंगे।

नागरिक बन्धुओ से विनम्र अपील

- शहर में पॉलीथिन प्रतिबंधित है, कृपया पॉलीथिन का इस्तेमाल न करें।
- घर का कचरा बाहर न फेंके। कचरा, एकत्रित कर कचरा, नगरपालिका के कचरा वाहन में ही डाले।
- करों का भुगतान समय सीमा में करें।
- नलों में टोंटी लगावें, जल को व्यर्थ न बहने दें।
- पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षों को न काटें और न ही काटने दें एवं वृक्षारोपण करें।
- विवाह तथा जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन अवश्य ही करावें।
- निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही करें।
- घरों में वर्षा जल संचयन किया जाए।

श्री पंकज चौरे, अध्यक्ष — श्रीमति रितु मेहरा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी

उपाध्यक्ष तथा समस्त पार्षदगण
समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण,
नगरपालिका परिषद इटारसी जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका परिषद पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2023 पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन

चले गए जो हँसते-हँसते बांध अपने सर पे कफन
उन शहीदों की बली को हमारा शत-शत नमन

-: साथ ही विनम्र अपील है कि :-

1. मेरी माटी मेरा देश "हर घर तिरंगा" के तहत घर में तिरंगा आवश्यक लगावें।
2. नगर पालिका के कचरा वाहन में ही सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग डालें।
3. खुले में शौच न करें एवं अपने घरों में बने शौचालयों या सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करें।
4. अपने नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।
5. पोलीथिन का उपयोग न करें।
6. जल ही जीवन है इसे व्यर्थ न बहावें।
7. निकाय के समस्त करों का भुगतान समय पर करें।
8. जन्म-मृत्यु का पंजीयन समय पर करावें।

श्रीमति नीना नवनीत नागपाल, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् पिपरिया — श्री संतोष परते, उपाध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् पिपरिया — श्री आर.पी. नायक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् पिपरिया

कार्यालय नगरपालिका परिषद सिवनी मालवा, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

15 अगस्त 2023

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

-: अपील :-

1. स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 अन्तर्गत सूखा कचरा नीले डस्टबीन में एवं गीला कचरा हरे डस्टबीन में डालें।
2. स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में नियत स्थान के अलावा सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर कचरा नहीं फेंके/सफाई के नियत समय के पश्चात् कचरा नहीं फेंके।
3. समय पर नगरपालिका के सम्पत्तिकर, दुकान किराया, जलकर एवं अन्य करों का भुगतान करें।
4. अपने पालतू पशुओं को सड़क पर आवारा न छोड़ें जिससे जानमाल की हानि न हो।
5. पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए पॉलिथीन का उपयोग न करें।

(शीतल भलावी), मुख्य नगरपालिका अधिकारी, न.पा. सिवनी मालवा — (श्रीमती स्वाति शैलेन्द्र गौर), उपाध्यक्ष, न.पा. सिवनी मालवा — (रीतेश (रिंकू) जैन), अध्यक्ष, न.पा. सिवनी मालवा

एवं

समस्त पार्षदगण नगरपालिका परिषद सिवनी मालवा

चीन के गले की फांस बना सीपेक

चीन और पाकिस्तान सीपेक के दस साल पूरे होने पर भले ही एक-दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह अतिमहात्वाकांक्षी परियोजना चीन के गले की फांस बन गई है। चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग गत दिनों इस्लामाबाद पहुंचे तो थे अपनी दोस्ती और परियोजना के प्रति अपनी वचनबद्धता निभाने के लिए, लेकिन परदे के पीछे उन्होंने आतंकवाद की भेंट चढ़ रही इस परियोजना पर अपनी चिंता भी जताई। 62 अरब डॉलर के निवेश वाली इस परियोजना में चीन पैसे के साथ अपने लोगों को भी खोता जा रहा है। उसके दर्जनों नागरिक पाकिस्तान में आंतकवाद का शिकार बन चुके हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर, जो सीपेक के नाम से ज्यादा मशहूर है, 2013 में शुरू हुआ। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। प्रारंभ में इसकी लागत 46 अरब डॉलर आंकी गई थी, लेकिन बाद में इसका बजट बढ़ाकर 62 अरब डॉलर तय कर दिया गया। चीन और पाकिस्तान ने इस परियोजना को गेम चेंजर के रूप में प्रचारित किया, लेकिन समय बीतने के साथ यह परियोजना पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट तो चीन के लिए आर्थिक के साथ-साथ मानवीय संकट का पर्याय बन गई है।

सीपेक पश्चिमी चीन के खुनजेराब से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक हाईवे, रेलवे और एनर्जी पाइपलाइन की परियोजना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्वादर पोर्ट है, जिसे चीन ने दूसरा दुबई बनाने के सपने के साथ शुरू किया था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं मिला है। उल्टे महंगे कर्ज और परिवहन खर्च में बढ़ोतरी के कारण बिजली और गैस महंगी ही होती चली जा रही है। यह सपना अब भयानक हकीकत में बदलने लगा है।

चीन ने पाकिस्तान में इस परियोजना के लिए 25 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश किया है। 1,000 किलोमीटर सड़क और 6,000 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो गया। लेकिन यह निवेश पाकिस्तान के लिए फायदे की बजाय बर्बादी का कारण बन गया। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा इस्लामाबाद इस परियोजना के लिए कर्ज पर कर्ज लेता चला गया। पाकिस्तान पर लगभग 100 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, उसमें से एक तिहाई से अधिक चीन से लिया गया कर्ज है। हालात यहां तक पहुंच गए कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। चीन ने अपने कर्ज को वसूल न करके उसे रोल ओवर कर दिया है, पर उसे माफ नहीं करने वाला है। यानी आने वाले दिनों में चीनी कर्ज में और इजाफा ही होने वाला है।

● **कुमार विनोद**

ध्वजारोहण...

ग्वालियर। भारतीय स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड ग्वालियर द्वारा कार्यालय में ध्वजारोहण सहित रंगारंग एवं सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड ग्वालियर चंबल संभाग तथा तकनीकी संभाग ग्वालियर के सभी कर्मचारी निर्धारित गणवेश में उपस्थित रहे। मंडी बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रबंध संचालक की ओर से दिए गए सम्मान को आज मंडी श्योपुर (ब वर्ग) के सचिव एसडी गुप्ता, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मंडी दतिया की एएसआई मेघा आर्य को सम्मानित किया गया। संभाग में उत्कृष्ट कार्य किए जाने के लिए मंडी गुना के जितेंद्र रघुवंशी एएसआई, सहभागिता कार्यक्रम के विजेता अशोक बंसल सहा वर्ग 2, सांस्कृतिक कार्यक्रम के विजेता वीरेन्द्र बाथम एएसआई को संयुक्त संचालक द्वारा सम्मानित किया गया।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

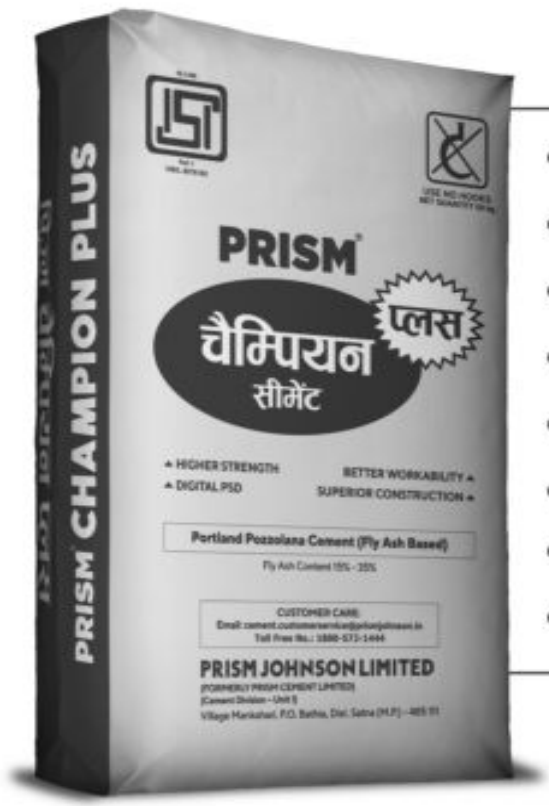

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

मां हो न

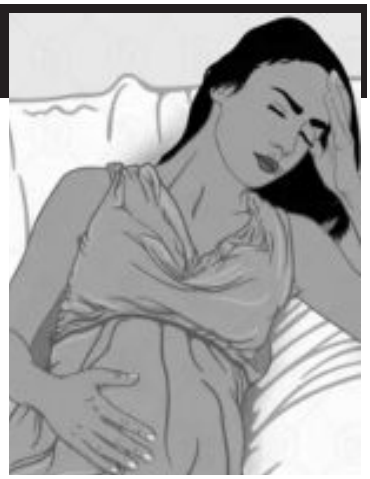

कल शाम से वसुधा दर्द से छटपटा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पांव कटकर गिर जाएंगे। रात में ही उसने बगल में सोये अपने पति को उठाकर कहा- अब दर्द सहन नहीं हो रहा, अस्पताल ले चलो। आधी नींद में ही विजय बोला- बस अब सुबह होने ही वाली है, चलते हैं। और वह खर्राटे लेने लगा। तड़पते हुए लंबी-लंबी सांसें लेकर किसी तरह वसुधा ने रात गुजारी।

दर्द से वसुधा को रुलाई आ रही थी। वह छटपटाकर कभी पेट पकड़ती तो कभी कमर। उसे लग रहा था जैसे अब उसका पेट, कमर और पैर फट जाएगा। सुबह होते ही अस्पताल जाने के लिए वसुधा को गाड़ी में बिठाया गया। घर के निकट ही अस्पताल है। विजय के पिता ने आदेशात्मक स्वर में कहा- मंदिर होते हुए अस्पताल जाना। विजय की मां पास के मंदिर जाकर पुत्र प्राप्ति की कामना करके लौटी, उसके बाद सभी अस्पताल गए। वसुधा दर्द से कराह रही थी, बीच-बीच में उसकी चीख निकल जाती थी।

अस्पताल पहुंचते ही नर्स उसे ओटी में ले गई। सिजेरियन होना तय था क्योंकि वसुधा का रक्तचाप इन दिनों काफी बढ़ा हुआ रह रहा था। लगभग दो घंटे बीत गए। सभी की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं कि कब नर्स आए और खुशखबरी सुनाए। तभी नर्स ट्रे में शिशु को लेकर आई। सभी के चेहरे पर खुशी छा गई; पुत्र जो हुआ था। शिशु को देखने के लिए सभी बेचैन थे। कोई तस्वीर ले रहा है, कोई चेहरे का मिलान खुद से कर रहा है, कोई उसका रंग-रूप देख रहा है। विजय के पिता ने कहा- विजय, पहले जाकर मंदिर में लड्डू चढ़ा आओ। विजय मंदिर में लड्डू चढ़ाने बाजार की तरफ चला गया।

एक तरफ एक स्त्री चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता के भाव थे। वह अब भी उसी दरवाजे की तरफ बार-बार देख रही थी जिधर से नर्स आई थी। नर्स ने लाकर बच्चे को दिया तो मारे खुशी के वे रोने लगीं, फिर बच्चे को प्यार कर धीरे से नर्स से पूछा- बच्चे की माँ कैसी है? वह ठीक है न? नर्स ने मुस्कुराकर कहा- वह बिल्कुल ठीक है। तुम जच्चा की मां हो न! उस मां की डबडबाई आंखों ने नर्स को सब समझा दिया था।

- डॉ. जेन्नी शबनम

रक्तदान

सर, प्रमोद जी आए हैं रक्तदान करने। कंपाउंडर ने कहा।

कौन प्रमोद जी? डॉक्टर साहब ने पूछा।

सर, ये हर साल यहां दो बार रक्तदान करने आते हैं। कंपाउंडर ने बताया।

ठीक है। भेजो उन्हें। डॉक्टर ने कहा।

नमस्ते सर। मैं प्रमोद हूं। इसी गांव में रहता हूं। स्वस्थ आदमी हूं। लगातार रक्तदान करता रहता हूं। आज भी इसीलिए आया हूं। प्रमोद ने हाथ जोड़कर कहा। नमस्कार प्रमोद जी। कंपाउंडर ने मुझे आपके बारे में बता दिया है। अच्छी बात प्रमोद जी। मैंने सुना है कि आप हर साल दो बार रक्तदान करते हैं। कोई खास वजह? डॉक्टर साहब ने यूं ही पूछ लिया। डॉक्टर साहब, सामान्यत: लोग अपने पसंदीदा बड़े-बड़े नेताओं, अभिनेताओं के जन्मदिन पर रक्तदान करते हैं, पर मैं अपने पिताजी और माताजी, जिनकी बदौलत मैं इस दुनिया में आया हूं, उनके जन्मदिन पर साल में दो बार रक्तदान करता हूं। संयोगवश दोनों के जन्मदिन में छह माह का अंतराल है। इससे मेरे रक्तदान में कोई अड़चन नहीं है। प्रमोद ने कहा। वाह! क्या नेक विचार हैं। काश! सभी आपकी तरह सोचते। प्रमोद जी के हाथ में सुई चुभाते हुए डॉक्टर साहब ने कहा।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

भोपाल विकास प्राधिकरण

क्रमांक 6616/राजस्व/भोविप्रा/23 — भोपाल, दिनांक 11.08.23

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य दर पर ऑनलाईन आमंत्रित रिक्त सम्पत्ति जैसे:- भूखण्ड/भवन/प्रकोष्ठ/डुप्लेक्स/हॉल/वाणिज्यिक/दुकानें. जो कि निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन ऑफर वेबसाइट **https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in** के माध्यम से नियत दर/ प्रस्ताव दिनांक 14.08.23 से दिनांक 28.08.2023 तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर / आवेदन पत्र दिनांक 29.08.23 को लगभग 12.30 बजे खोले जावेंगे।

निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट **www.bda.org.in** पर देखे जा सकते है।

क्र.	योजना का नाम	ऑफर/ नियत दर	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति की संख्या	रिमार्क
1.	मिसरोद फेस-02 (पी.एस.पी.) सेक्टर-ए	ऑफर	भूखण्ड	01	रेरा पंजीयन क्र.-पी-बी.पी.एल-17-1018
2.	सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस-2 विभिन्न आकार के भूखण्ड	ऑफर	भूखण्ड	44	रेरा पंजीयन क्र.-पी-बी.पी.एल-17-1018
3.	एयरोसिटी फेस-1	ऑफर	भूखण्ड	39	रेरा पंजीयन क्र.-पी-बी.पी.एल-17-246
4.	नवीबाग	ऑफर	वाणिज्यिक	11	रेरा पंजीयन क्र.-पी-बी.पी.एल-17-837
5.	गुरू रविन्द्रनाथ टेगौर, साकेत नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
6.	अन्नपूर्णा काम्पलेक्स (पी.एण्ड.टी. चौराहा)	ऑफर	हॉल	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
7.	सोनिया गाँधी परिसर (कोटरा सुल्तानाबाद)	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
8.	अन्नपूर्णा काम्पलेक्स (पी.एण्ड.टी. चौराहा)	ऑफर	प्रकोष्ठ	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
9.	एम जी रूसिया नगर, पीपलनेर	ऑफर	डुप्लेक्स	04	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
10.	कटारा हिल्स सेक्टर-ए एवं सी	ऑफर	दुकानें	31	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
11.	महालक्ष्मी आवासीय परिसर	ऑफर	2 बीएचके प्रकोष्ठ	34	रेरा पंजीयन क्र.-पी-बी.पी.एल-17-306
			3 बीएचके प्रकोष्ठ	29	
12.	आई.एस.बी.टी. (कुशाभाऊ ठाकरे टर्मिनल)	ऑफर	दुकानें	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
13.	गुरू रविन्द्रनाथ टेगौर, परिसर (साकेत नगर)	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
14.	अन्नपूर्णा काम्पलेक्स (पी.एण्ड.टी. चौराहा)	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
15.	पंचशील नगर	ऑफर	दुकानें	04	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
16.	महर्षि पतंजलि	ऑफर	दुकानें	35	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
17.	पंडित भीमसेन जोशी परिसर, साकेत नगर (एम्स के पास)	ऑफर	दुकानें	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
18.	माता मंदिर (न्यु मार्केट)	ऑफर	दुकानें	08	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
19.	आमेर कॉम्पलेक्स नाले के ऊपर जोन-2 एम.पी. नगर	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
20.	स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स	ऑफर	भवन	18	रेरा पंजीयन क्र.-पी-बी.पी.एल-21-2845
21.	स्वामी विवेकानन्द परिसर, कटारा हिल्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	45	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
22.	स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स स्थित डुप्लेक्स भवनों	ऑफर	भवन 02 एमआईजी/	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
			02- एलआईजी	02	
23.	केंद्रवर्ती आवासीय योजना स्थित भूखण्ड	ऑफर	भूखण्ड	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
24.	विद्या नगर फेस 1	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
25.	गौरीशंकर कौशल अर्फोडेबल आवासीय योजना बर्रई चरण-1	ऑफर	मिश्रित/व्यवसायिक भूखण्ड	09	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
26.	महर्षि पतंजलि, गेंदसमड	नियत दर	प्रकोष्ठ	22	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
27.	स्वामी विवेकानन्द परिसर, कटारा हिल्स स्थित ई.डब्ल्यू.एस.	नियत दर	ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ	12	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
28.	अमरावद खुर्द	नियत दर	एल.आई.जी. डुप्लेक्स	21	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
29.	नवीबाग योजना (बैरसिया रोड)	नियत दर	2 बीएचके प्रकोष्ठ	23	रेरा पंजीयन क्र.-पी-बी.पी.एल-17-837

नोट:- वेबसाईट पर दिये गये लिंक को ओपन करने के पश्चात् आपको योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें सेम्पल फार्म, योजना के मानचित्र तथा प्रकोष्ठ/दुकान/हॉल के मानचित्र व अपलोड करने हेतु विभिन्न आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देखी जा सकती है। ऑनलाईन फॉर्म भरने हेतु प्राधिकरण की आई.टी. सेल से सम्पर्क किया जा सकता है।

(2) किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष भोविप्रा भोपाल का निर्णय मान्य होगा। (3) मध्यप्रदेश शासन एवं प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले नियम एवं शर्तें आप पर बंधनकारी होंगी। (4) यदि किसी भी कारण वश ऑफर अस्वीकार किया जाता है तो मान. अध्यक्ष महोदय/संचालक मण्डल का निर्णय मान्य होगा। (5) विज्ञापन में प्रकाशित नियम एवं शर्तें तथा आवंटन पत्र में उल्लेखित नियम एवं शर्तें आप पर बंधनकारी होंगी।

आवश्यकतानुसार जानकारी हेतु सम्पर्क:-

1- श्री रवि सिंह मो.-8770234380,

सम्पदा अधिकारी

भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल

जब डायरेक्टर ने जितेंद्र को फिल्म से आउट कर मिथुन पर खेला दांव

बात उन दिनों की है, जब साल 1985 में फिल्म गंगा, जमुना, सरस्वती के बनाने की चर्चा हो रही थी उस दौरान इस फिल्म का नाम अमर अकबर एंथोनी पार्ट 2 रखने की योजना बनाई गई थी। मनमोहन देसाई ने अपनी 1977 वाली अमर अकबर एंथोनी की सफलता के बाद ही ये फैसला किया था। अमिताभ बच्चन गंगाराम का, जितेंद्र जमुनादास का तथा ऋषि कपूर सरस्वतीचंद्र के किरदार में रखकर ही स्क्रिप्ट भी तैयार की गई थी। लेकिन जितेंद्र ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह मिथुन चक्रवर्ती को मिली। लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो यह फिल्म फ्लॉप हो गई।

बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा

अपने देश में राजनीति भी उद्योग धंधों के जैसे अपार संभावनाओं से भरा हुआ एक व्यापार है। जिसको इस व्यापार की समझ है वह सफल व्यापारी है। और जिसको समझ नहीं है, वो पिटा हुआ खिलाड़ी है और सफलता की राह देख रहा है। राजनीति कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राजनीति को भी स्थापित और चमकाने के लिए वही मेहनत लगती है जो किसी भी उद्योग धंधे में लगती है। उतना ही पूंजी लगती है जितनी उद्योग धंधों में लगती है। और किसी भी उद्योग धंधे में भी प्रोडक्ट को जनता के सामने अपने को लाइमलाइट में बनाए रखना पड़ता है, राजनीति में भी यही करना पड़ता है। बस अंतर इतना है कि उद्योग धंधे में सामान रहता है और राजनीति में इंसान रहता है।

जिस तरह कंपनियां बिना अच्छे-बुरे की परवाह किए बस अपने सामान को बेचने पर ध्यान देती हैं, अपने नफा-नुकसान पर ध्यान देती हैं, उसी तरह राजनीति में भी बिना अच्छे बुरे की परवाह किए मुद्दे उठाते रहिए, मुद्दे बनाते रहिए। व्यापार हो या राजनीति यदि आपको यह कला आती है तो आपकी सफलता की गारंटी सौ परसेंट है। और अपना देश तो हमेशा मुद्दों से भरा ही रहता है, कभी मुद्दों का अकाल नहीं रहता। अपने देश में बारिश का अकाल हो सकता है, अनाज का अकाल हो सकता है, लेकिन मुद्दों का अकाल कभी नहीं हो सकता। कभी हिंदू-मुस्लिम, कभी मंदिर-मस्जिद, तो कभी राजस्थान, कभी मणिपुर, तो कभी बंगाल... मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बस जहां से मन करे वहां से मुद्दे उठा लीजिए। राजनीति कीजिए खूब कीजिए और अपना परचम लहराने की तैयारी कर लीजिए।

संसद से लेकर घर तक कहीं पर भी मुद्दा उठाइए, याद रखिए आपका मुद्दा उठाना ही आपको लोगों की नजरों में बनाए रखेगा। लाइमलाइट में बनाए रखेगा। पहले के जमाने में लोग संसदों में मुद्दा उठाते थे और सड़कों पर उठाते थे। लेकिन आजकल नया जमाना है पहले की अपेक्षा हर चीज के लिए ऑप्शन ज्यादा है। और पहले जितनी मेहनत भी नहीं करनी है। पहले सिर्फ संसद और सड़क ही प्रचार-प्रसार के साधन थे, अब तो आप सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक अपनी जुबानी गोली कहीं भी चला सकते हैं। याद रखिए बंदूक की गोली से भी ज्यादा जुबान की गोली कारगर है, अगर इसे ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इधर कुछ सालों से सभ्यता का कुछ ज्यादा ही विकास हो गया है। अत: संसद में मुद्दे कम हाथ-लात, कुर्सी ज्यादा चलती है। इसलिए अपनी सुरक्षा भी स्वयं करनी है। आप मुद्दे उठाइए लेकिन आपको इतना ध्यान रहे कि आप के मुद्दे फुसफुसिया बम ना साबित हो जाएं। जो फुसफुसा कर शांत हो जाए। मुद्दा ऐसा उठाइए, जो प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आपके पीछे पड़ जाए।

आपकी खूब खबर रखी जाए, आपके बारे में विपक्ष वाले चुनिंदा शब्दों से नवाजें और आपकी खूब बुराई करें। और निंदा से बिल्कुल मत डरिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी जो डर गया वह मर गया, लेकिन राजनीति में जो डर गया वह घर गया, तो आपको बस मैदान में डटे रहना है। बस इस कहावत को याद रखिए... बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, की तर्ज पर अपने आप को संतुष्ट करते रहिए। आप के बोल बच्चन ऐसे होने चाहिए कि आपके ऊपर दो चार मुकदमे तो यूं ही लाद दिए जाने चाहिए। ताकि आप अपने आपको बेचारा और प्रताड़ित भी दिखा सकें। आपके विरोधी आपके पीछे-पीछे जागते-सोते हुए आपके पीछे लगे रहें और सोचे और अपना माथा पीटे, अरे यह मुद्दा कैसे छूट गया हमसे? और अपने सलाहकारों को भरपेट लानत मलामत करें। तभी आप के मुद्दे की सार्थकता है।

रोज एक नया मुद्दा खोजिए, पहले के जमाने में विशेष उपलब्धियां किसी के नाम होती थीं, आज के जमाने में विवादित मुद्दे भी अलग फलां-फलां के नाम हो जाती हैं। और एक बार आप कोई विवादित मुद्दे के द्वारा फेमस हो गए, आप की नैया पार लगनी तय है। फिर तो आपको जनता भी अच्छे से पहचान लेगी और राजनीति और बड़ी-बड़ी पार्टियां तो आपको जाने कौन-कौन सी उपाधियों से नवाज कर आप की राजनीति की खटारा गाड़ी को लग्जरी गाड़ी में बदली करवा देंगी और आप की राजनीति की दुकान धड़ल्ले से चल निकलेगी।

● रेखा शाह आरबी

ANU SALES CORPORATION
INDIA INDEPENDENCE DAY
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology & Medical Equipment
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

SECL

A MINI RATNA COMPANY

CATERING TO THE COAL DEMANDS OF A BILLION

EXCAVATING POSSIBILITIES, EMBELLISHING LIVES.

- Futuristic Technology
- Eco-friendly Mining
- Empowering Lives

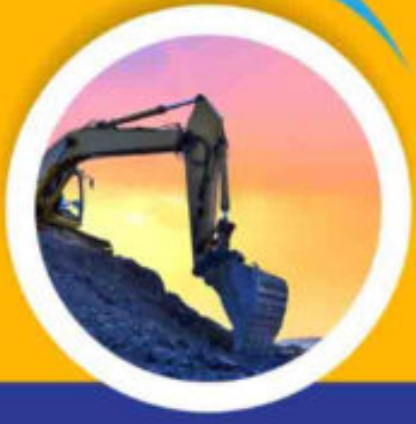

South Eastern Coalfields Limited

(A Mini Ratna Company)

SECL Bhawan, Seepat Road, Bilaspur (C.G) 495006

@southeasterncoalfields secl_cil SECL Media www.secl-cil.in